हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2018 को अध्यक्ष, डॉ० राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में कौंसिल चैंबर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

27.03.2018/1100/SLS-YK-1

अध्यक्षः प्रश्न काल आरंभ। ...(व्यवधान)... श्री जगत सिंह नेगी जी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री जगत सिंह नेगी : Speaker Sir, on a point of order. अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यहां पर आपके ध्यान में लाया कि विधान सभा परिसर में आपने नियमों में डिक्लेयर कर रखा है, कि यहां पर किस-किस किसम की गतिविधियां न हों। यहां कौन आ सकता है, कौन जा सकता है और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का आचरण कैसा हो, यह सब आपने डिक्लेयर कर रखा है। परंतु उसके बावजूद इस बार पहली बार विधान सभा में यह देखने में आया है कि बाहर से जो लोग माननीय मुख्य मंत्री जी को या अन्य मंत्रिगण को मिलने आते हैं, वह यहां आकर नारेबाज़ी कर रहे हैं और विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। कहीं भी किसी भी देश की विधान सभाओं में या पार्लियामैंट में इस किसम की कोई परिपाटी नहीं है। इसको रोकने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आपने अपना फ़ैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अभी तक बताया नहीं है।...(व्यवधान)...यह लोकप्रिय नहीं है। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, नियम होते हैं जिनके तहत काम चलता है। आपने सारे संस्थानों को ख़त्म करके यहां विधान सभा परिसर में राजनीतिक भाषण देने शुरू कर दिए। मुख्य मंत्री जी और मंत्रिगण राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। यह गलत प्रथा शुरू की गई है और इस विधान सभा की गरिमा को ख़त्म करने की कोशिश की गई है।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : नेगी साहब, ठीक है, आपकी बात हो गई।

श्री जगत सिंह नेगी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस पर आपका संरक्षण चाहते हैं और इस पर फ़ैसला होना चाहिए। जो इस किसम की प्रवृत्ति शुरू की गई है, उसको तुरंत रोका जाए और जो लोग नारेबाज़ी कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ केस दर्ज़ किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप अपनी बात रखें।

27.03.2018/1100/SLS-YK-2

शिक्षा मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, प्वायंट ऑफ ऑर्डर तो तब होता है जब कोई चीज़ प्रोसीडिंग्ज में ऑर्डर में न होने की बात हो, इसलिए इसमें प्वायंट ऑफ ऑर्डर की बात नहीं है। साथ ही, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय विधान सभा से संबंधित है। जो परंपरा है उसके अनुसार अगर कोई बात विधान सभा से संबंधित है तो वह हाऊस में न उठाकर माननीय अध्यक्ष महोदय के चैंबर में जाकर उठाई जा सकती है। अगर कोई विषय सरकार से संबंधित है तो उसे आप यहां पर अवश्य उठाएं। यह भी एक प्रोपराइटी है, मर्यादा का ही सवाल है। माननीय सदस्य तो इस सदन के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। उनको मालूम है कि जब विधान सभा से संबंधित बात होती है तो वह हाऊस में नहीं उठाई जाती बल्कि उसके लिए रूल्ज में अलग से प्रोविज़न्ज हैं। हम उसे उनके अनुसार उठाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्होंने यह बात ध्यान में लाई है, उसको सरकार की ओर से हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन जो विधान सभा को करना है उसके लिए आप विधान सभा अध्यक्ष से उनके चैंबर में बात करें तो ज्यादा उचित होगा।

अध्यक्ष : मुकेश अग्निहोत्री जी, क्या आप भी कुछ कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री को यह मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि हमने लिखित तौर पर यह बात माननीय अध्यक्ष को दी है। आप अपना तालमेल पहले माननीय अध्यक्ष जी के साथ भी रखें। ...(व्यवधान)...अगर आप हमें बोल सकते हैं, ...(व्यवधान)... आपने कहा विषय माननीय अध्यक्ष से उठाना चाहिए जबकि हम पहले ही लिखित तौर पर दे चुके हैं।...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो तालमेल की बात हो। संसदीय कार्य मंत्री हमेशा हमें उपदेश देने के लिए खड़े होते हैं। इनको मालुम होना चाहिए कि हमने अध्यक्ष जी को लिखित में दिया है। हमने यह विषय आपसे उठाया था इसलिए हमें आपका फ़ैसला चाहिए।

अध्यक्ष : मुकेश जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। ...(व्यवधान)...

27.03.2018/1100/SLS-YK-3

श्री मुकेश अग्निहोत्री : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विधान सभा परिसर में पार्टियों के झंडे लगें, ढोल-नगाड़े बजें, विधान सभा परिसर में नारेबाज़ी हो, इसके बारे में हम आपसे फ़ैसला चाहते हैं। यह रोज़ का काम हो गया है। हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे 7 बार के विधायक माननीय मंत्री महेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने हमेशा से परंपराएं देखी हैं, वह कह रहे हैं कि चलता है

27/03/2018/1105/RG/YK/1
श्री मुकेश अग्निहोत्री-----जारी

और हमें इस बात का अफसोस है कि हमारे सात बार के विधायक माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री श्री महेन्द्र सिंह जी, जिन्होंने हमेशा से परम्पराएं देखी हैं, कह रहे हैं कि ऐसा चलता है। इस तरह की बात सदन में नहीं होनी चाहिए। मुख्य गेट के बाहर जो भी करना है, वह करें।

अध्यक्ष : मुकेश जी, ठीक है, हो गया, आप बैठिए।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : नेगी जी, आप बैठिए। अब क्या बोलना है?

श्री जगत सिंह नेगी : इन्होंने मेरा नाम लिया है।---(व्यवधान)----

अध्यक्ष : आप कृपा करके बैठिए। क्या आपको मैंने बोलने की अनुमति दी? आप ऐसे ही उठकर खड़े हो जाते हैं। मुझे बोलने दीजिए, आप बैठिए, I am on my legs. मैं खड़ा हूं, आप बैठिए। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कल श्री जगत सिंह नेगी जी ने विषय को उठा लिया था। मैंने कल भी विषय पर बड़े सहज स्वभाव में कहा था कि हम इस विषय की चिन्ता करेंगे। जो रिकॉर्ड पर है। आज कांग्रेस विधायक दल के नेता अभी तीन मिनट

पहले मेरे कक्ष में आए थे और इन्होंने मुझे पत्र दिया है। मैंने इनको कहा कि बहुत अच्छा है कि आपने मेरे ध्यान में मामला लाया है। इसमें जो भी करने का होगा, वह हम करेंगे। अब इससे ज्यादा इस विषय को बढ़ाना उचित नहीं है। सारा विषय आ गया है। इसलिए अब मैं प्रश्नकाल प्रारम्भ कर रहा हूं। --(व्यवधान)----नेगी जी, देखिए, I won't allow it.मैंने आपको समय दिया, आपका विषय आ गया। I won't allow it. नेगी जी, मैं अलॉऊ नहीं करुंगा। क्योंकि इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। आप यहां सदन में इस बात को नहीं रख सकते। नियम इसकी अनुमति नहीं देते, फिर भी मैंने आपको बोलने की अनुमति दी।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

27/03/2018/1105/RG/YK/2

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए, बैठिए। "Matter in the jurisdiction of Hon'ble Speaker, no matter relating to Vidhan Sabha Secretariat which falls under the jurisdiction of Hon'ble Speaker shall be raised in the Hon'ble House in any form". और मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह विषय आ गया और मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरह से देख लिया है। --(व्यवधान)----मुकेश जी, एक मिनट कृपा करके बैठिए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यह आप पर या आपकी कार्य-प्रणाली पर कोई आक्षेप नहीं है। लेकिन यह विधान सभा परिसर के बाहर जो हो रहा है, वह बात आपके समक्ष लाई जा रही है। आपने यह नियम दिखाया।--(व्यवधान)----

अध्यक्ष : मैंने नियम तो तब दिखाया जब नेगी नहीं सुन रहे हैं।

श्री जगत सिंह नेगी : मैं खूब सुन रहा हूं और दोनों कानों से सुन रहा हूं। --(व्यवधान)----

अध्यक्ष : प्रश्नकाल आरम्भ।

27/03/2018/1105/RG/YK/3

प्रश्न सं. 219

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी बिलासपुर में इन्होंने बैठक की और बहुत सारे मुद्दों को निपटाने के लिए इन्होंने आदेश दिए। लेकिन जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि चंगर एरिये की एक स्कीम आन्नदपुर हाईडल से जो 25 क्यूसेक पानी हिमाचल प्रदेश को मिला है जिसके लिए केन्द्र सरकार ने 88,09,00,000/- रुपये स्वीकृत किए थे, वह स्कीम बनकर तैयार हो गई और उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो कागजों में सींचित बताया गया है और जमीन पर उन गांवों एवं पंचायतों तक पानी नहीं गया। इस बारे में जब मैंने विभाग से बैठक की, तो मुझे यह उत्तर मिला था कि अगर इनको पानी देना है, तो 18,00,00000/- रुपये चाहिए और इसकी मांग हमने सैक्रेट्री साहब से की है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह पानी न तो हमारे मरियारी गांव में जा रहा है, न हमारे तिरसू पंचायत में जा रहा है, न हमारे लखणू पंचायत में जा रहा है और ज्यादातर हरिजन बस्तियां हैं, जिनको छोड़ दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस स्कीम के लिए जो धनराशि चाहिए और जो विभाग मांग रहा है, मैं इसमें यह नहीं कहूंगा कि इसमें क्या गल्तियां होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ,खेतों को पानी देने के लिए विभाग का दृष्टिकोण क्या है?

27.03.2018/1110/जेके/एजी/1

प्रश्न संख्याः 219ः----जारी--------

श्री राम लाल ठाकुरः------जारी-------

दूसरे, श्री प्रणव मुखर्जी जी माता नैना देवी में माथा टेकने के लिए आए थे जब वे प्लानिंग कमिशन के चेयरमैन थे। उन्होंने कुल 10 करोड़ रूपए सड़क बनाने के लिए और काला कुण्ड से नैना देवी को पानी लाने के लिए पैसा सैंक्शन किया था। स्कीम बन गई थी, नैना देवी को पानी आ गया था लेकिन उसके बाद विभाग ने उस स्कीम को अबैंडन कर दिया। अगर मान लो गर्मियों के दिनों में जो चार पंचायतें नीचे हैं, नैना देवी को पानी आन्नदपुर हाईडल चैनल से आ गया लेकिन जिसके ऊपर पैसा खर्च किया है वह नकराना पंचायत

है,खरकड़ी पंचायत है, सलोआ है, माकड़ी है। नीचे गोबिन्दसागर के किनारे पर पानी की गर्मियों में ज्यादा दिक्कत आती है इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो कालाकुण्ड -नैनादेवी वाली स्कीम बनी है, जिसका सामान चोरी हो गया, उसकी एफ0आई0आर0 तक दर्ज़ नहीं करते हैं, उस स्कीम को चलाने के लिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सदन में बता दें कि उस स्कीम का क्या होगा?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में इसी सत्र के दौरान पिछली बार जब माननीय राम लाल ठाकुर जी ने प्रश्न किया था, मैंने इनको आश्वस्त किया था कि सत्र के दौरान जब बीच में ब्रेक आएगी, मैं जिला बिलासपुर का भ्रमण करूंगा और उस भ्रमण के दौरान आपको पहले सूचित करूंगा और उसके बाद जो भी वहां की ग्रीवेंसिज़ होंगी उन ग्रीवेंसिज़ को सॉल्व करने की हम भरसक कोशिश करेंगे। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो पीने के पानी की स्कीम और सिंचाई की स्कीम की वस्तुस्थिति के बारे में जानना चाहा है, उसमें पहली स्कीम LWSS बहल से त्यूनखास री, स्वाहण, यह स्कीम 22 बस्तियों के लिए है। इन 22 बस्तियों के लिए स्कीम दो चरणों में है। प्रथम चरण में बैहल पंचायत आती है।

27.03.2018/1110/जेके/एजी/2

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय मंत्री जी यह डिस्कस हो गया है इसको रहने दो, जो दूसरी स्कीम है उसके बारे में आप बताएं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः ठीक है, इसको रहने दूं। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बस्सी रोड़-जामन कोट खास टोबा व दबट के बारे में जानना चाहते हैं। इस स्कीम की AA&ES 5.12. 2009 को हुई। इस स्कीम में AA&ES में 1 करोड़ 2 लाख 24 हजार का प्रावधान था। इस पर 1 करोड़ 1 लाख 92 हजार रूपए खर्च किए गए। योजना का जल स्त्रोत आन्नदपुर हाईडल चैनल से वाटर ट्रीटमैंट प्लांट कोट खास में लगा करके 11 बस्तियों के लिए कर दिया। यह स्कीम सुचारू रूप से चल रही है।

उठाऊ सिंचाई परियोजना आन्नदपुर हाईडल चंगर उठाऊ सिंचाई योजना बस्सी के बारे में जानना चाहा है, इसकी AA&ES 22.06.1999 को 28 करोड़ 37 लाख रूपए की हुई थी। उसके बाद AA&ES 31.03.2010 को 88 करोड़ की हुई और योजना का उद्घाटन 27.03.2011 को हुआ। वर्तमान में आज तक इस योजना के ऊपर जैसे रिवाइज्ड AA&ES इसकी 88 करोड़ कुछ हजार के लगभग हुई थी। उस पर आज तक 87 करोड़ 46 लाख रूपया खर्च हो चुका है। इस सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 2350 हेक्टेयर भूमि सिंचाई में लानी थी लेकिन अभी तक केवलमात्र 1600 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है।

27.03.2018/1115/SS-AG/1

प्रश्न संख्याः 219 क्रमागत

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

बाकी जो 750 हैक्टेयर भूमि अभी सिंचाई के अन्तर्गत लाने को है और इस 750 हैक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाने के लिए जैसे माननीय सदस्य जी की चिन्ता है, विभाग की भी चिन्ता है और **इसका जो चाक एरिया डिवैल्पमैंट का काम है उसकी एक डी0पी0आर0 बना करके भारत सरकार को भेजी है जोकि 15 करोड़ 31 लाख की है। अब जैसे ही भारत सरकार से राशि स्वीकृत होकर आयेगी तो हम इस स्कीम का काम आगे बढ़ायेंगे और इसके काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे।**

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारे इश्युज़ सैटल किये। लेकिन मेरी जो चिन्ता है और जो आपकी भी बिलासपुर में चिन्ता थी, उस कालाकुंड-नैनादेवी की पुरानी स्कीम को आपने टच ही नहीं किया। आनंदपुर हाईडल से नैनादेवी को जो पानी आया, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि जो कालाकुंड-नैनादेवी के नाम से स्कीम बनी थी जो abandon हो गई, वह सारी की सारी बंद पड़ी है उसको अगर चालू कर दिया जायेगा तो चार पंचायतों को पानी आयेगा जोकि ड्रॉट हिट पंचायतें हैं। वहां से मोटरें भी चोरी हो गईं, सर्विस वायर भी चोरी हो गई, डिपार्टमैंट न तो उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज़ कर रहा है

और न कोई उसको पूछने वाला है। करोड़ों रुपये का सामान वहां पर लगा हुआ है। मेरा निवेदन है कि कृपा करके उस स्कीम को चलाने के लिए आप आदेश जारी करें ताकि वह पानी चार पंचायतों को मिल जाए।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो एल0डब्ल्यू0एस0एस0, श्री नैनादेवी जी-कालाकुंड की 1 करोड़ 8 लाख 85 हजार की AA&ES हुई है। यह स्कीम विशेष करके जो श्रद्धालु पूरे देश-विदेश या प्रदेश से नैनादेवी माता जी के मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, वे लगभग प्रतिदिन 50 हजार श्रद्धालु आते हैं। 20 लीटर प्रति श्रद्धालु पानी देने का प्रावधान रखा है और आपने ठीक कहा --(व्यवधान)--

27.03.2018/1115/SS-AG/2

श्री राम लाल ठाकुरः मैंने आपसे यह कहा कि स्कीम abandon हो गई लेकिन पैसा खर्च हुआ है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, इसके बारे में बता रहे हैं। हमने अगला प्रश्न भी लेना है।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः मैंने यह कहा कि आपने ठीक कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपने गलत कहा। आपने ठीक कहा कि इस स्कीम की जो मोटरें और पम्प हैं वे 8.2.2017 से खराब हैं। जब मोटरें खराब हो गईं, पम्प खराब हो गए, अब वहां जो श्रद्धालु आते हैं वहां के जो लोग हैं उनको पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने जो हमारी एल0आई0एस0 आनंदपुर हाईडल चैनल के लिए बनाई गई है उस मीडियम इरिगेशन स्कीम से हमने पानी लिया और फिर इस स्कीम को चालू किया। यह इसका एक पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट यह है जो आपकी चिन्ता है और हमारी भी चिन्ता है, हम ऐसा तो नहीं कहते कि सिर्फ आपकी चिन्ता है हमारी चिन्ता नहीं है। जो मोटरें खराब हैं, पम्प खराब हैं उन्हें ठीक करने के लिए विभाग को कहा है। वैसे जिस दिन हमारी मीटिंग थी, मैंने उस दिन आदेश दिए हैं कि हमारे सामने बड़ा भयंकर सूखा शुरू हो चुका है और जितनी भी मोटरें/पम्पस खराब हैं चाहे वे किसी भी स्कीम के हैं उन्हें तुरन्त विभाग ठीक करवाए। अगर वे ठीक होने की अवस्था में नहीं हैं तो वहां पर नई मोटरें/पम्पस का प्रावधान किया जाए।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, विधायक जी ने सिर्फ इतना जानना चाहा कि वह चोरी वाली एफ0आई0आर0 दर्ज करवायेंगे या नहीं?

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः मेरे पास सूचना नहीं है, मैं विभाग से सूचना मंगवा लूंगा और इनको सूचना दे दूंगा।

27.03.2018/1120/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः220

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं , मेरे मूल प्रश्न के उत्तर का जवाब आया है कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सकों और पैरा-मैडिकल स्टाफ के 3282 पद रिक्त हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक इनको भरने की मन्शा रख रही है?

दूसरे, क्या मंत्री जी बताएंगें कि क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर में कितने विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं और कितने अभी खाली है?

तीसरे, "ग" भाग के उत्तर में कहा गया है कि राही केयर प्राइवेट लिमिटेड को दो डायलेसिस की मशीनें क्षेत्रीय चिकित्सालय हमीरपुर को डानेट करवाई गई थी और अभी तक वे चालू नही हुई हैं। यह जो डायलेसिस की मशीनों को चलाने का काम है, क्या यह प्राइवेट पार्टी को दिया गया है? यदि हां, तो वह कितने पैसे चार्जिज़ करेगी? क्या सरकार उन मशीनों को चलाने के लिए एक टैक्निशियन नहीं रख सकती चाहे आऊटसोर्स पर ही रख दें?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है, एक तो मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय तक लगभग 3282 पद रिक्त हैं और इनको भरने की एक निरन्तर प्रक्रिया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि लगभग 568 विभिन्न श्रेणियों के पद चाहे वह ऑप्रेशन थियेटर असिस्टैंट की बात हो, रेडियोग्राफर की

बात हो । ऑप्रेशन थियेटर असिस्टैंट 120, रेडियोग्राफर 135, फार्मासिस्ट 173, लैबोरेटरी असिस्टैंट 129, ऑफ्थैल्मिक ऑफिसर 11 यानि ये 568 पद हैं तो एक रैक्विजिशन हमने हमीरपुर, पब्लिक सर्विस कमिशन के पास भेजी है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो विभिन्न श्रेणियों के पद रिक्त हुए हैं, ये टोटल वेकेंसीज़ 31.12.2017 तक लगभग 6966 बनती है। यह कोई तीन महीनों में ही पद रिक्त नहीं हुए परन्तु हमारी सरकार की मन्शा बिल्कुल स्पष्ट है और एक निरन्तर प्रक्रिया के तहत ये खाली पद भरे जाने हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने

27.03.2018/1120/केएस/डीसी/2

प्रश्न किया है और जानना चाहा है कि टोटल कितने पद हमीरपुर के अस्पताल में स्वीकृत है और कितने इस समय वहां पर फंक्शनल हैं? यह एक लम्बी सूची है और यह योग 155 है। जो भी श्रेणियां एक अस्पताल को चलाने के लिए होती है जैसे सी.एम.ओ., चिकित्सा अधिकारी, लैब टैक्निशियन, चीफ लैब टैक्निशियन, लैब असिस्टैंट, चीफ फार्मासिस्ट आदि यह संख्या लगभग 155 बनती है। इस समय यहां पर कुल स्टाफ 125 है यानि लगभग 30 पद खाली है। मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि जिस डायलेसिस मशीन की आप बात कर रहे हैं, आपने पहले भी कई बार अनौपचारिक रूप से इस सम्बन्ध में बातचीत की है और आपका विशेष आग्रह रहा है कि उस अस्पताल में दो डायलेसिस की मशीनें दी गई हैं और वे काफी वर्षों से वहां पर थीं लेकिन ,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

27.3.2018/1125/av/dc/1

प्रश्न संख्या : 220------ क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-------- जारी

वे फंक्शनल नहीं हो सकी है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कदम उठाया है और राही केयर प्राइवेट लिमिटिड के साथ हमारा एग्रीमैंट हुआ है। इस बारे में जैसे कि लिखित उत्तर में कहा गया है कि यह चार महीनों में सुचारु रूप से काम करना शुरू करेगी लेकिन हमारी कोशिश रहेगी इस समयावधि से पहले-पहले यह मशीनें काम करना शुरू कर दें। तीसरा, आपने जानना चाहा है कि इसकी अमाउंट वैल्यू क्या रहेगी। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जहां पर इस प्रकार के डाइलायसिस हो रहे हैं तो उसके लिए मरीज से 1100 रुपये लिए जाते हैं और बी0पी0एल0 के मरीजों को यह डाइलायसिस पूरी तरह से मुफ्त है । इस तरह से आपने जो पूछा है मैंने उसका पूरा उत्तर देने की कोशिश की है।

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, सिविल होस्पिटल रोहडू में डाक्टर की सैंक्शन्ड स्ट्रैंथ 30 हैं लेकिन आज की तारीख में वहां केवल 9 डाक्टर हैं और 21 पद खाली पड़े हुए हैं। मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि रोहडू सिविल होस्पिटल में दैनिक ओ0पी0डी0 रजिस्ट्रेशन की संख्या 200 से ऊपर है। वह होस्पिटल केवल रोहडू को ही फीड नहीं करता बल्कि वहां पर जुब्बल और उत्तराखंड से भी मरीज आते हैं। वहां पर आज यह स्थिति है कि 9 डाक्टर में से भी केवल 3-4 डाक्टर मिलते हैं बाकी कहीं कोर्ट केसिज में जाते हैं या पोस्ट मोर्टेम में बिजी हो जाते हैं जिसके कारण ओ0पी0डी0 में केवल 4-5 डाक्टर रहते हैं। वह एक दूरदराज क्षेत्र है और वहां पर अधिकतर लोग गरीब हैं लेकिन डाक्टर न मिलने के कारण अब लोग प्राइवेट होस्पिटल में जाने लगे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा और निवेदन भी करना चाहूंगा कि वहां पर इन पोस्टों को जल्दी-से-जल्दी भरने की कृपा करें।

27.3.2018/1125/av/dc/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने सिविल होस्पिटल रोहडू के बारे में बताया कि वहां पर 30 सैंक्शन्ड पोस्ट्स के अगेंस्ट वर्तमान में केवल 9 डाक्टर काम कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इन पदों को भरना एक निरंतर प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हमारी सार्थक कोशिश जारी रहेगी। लेकिन मैं यहां पर एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि क्या यह केवल पिछले तीन महीनों में ही सब कुछ हुआ है।

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि चिकित्सकों और पैरा मैडिकल स्टाफ के 3282 पद खाली पड़े हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितने चिकित्सक और पैरा मैडिकल स्टाफ के कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए अन्य राज्यों में डेपुटेशन करवा रखा है? प्रदेश में डाक्टरों और पैरा मैडिकल स्टाफ की कमी है। इसके मद्देनज़र क्या आप प्रदेश हित में उन डाक्टरों और पैरा मैडिकल स्टाफ के डेपुटेशन रद्द करके उन्हें ओरिजनल पोस्ट पर लाने के लिए इस मान्य सदन में विश्वास देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हमारे ध्यान में बात लाई है कि यहां के कुछ डाक्टर और पैरा मैडिकल स्टाफ के लोग डेपुटेशन पर अन्य राज्यों में कार्यरत्त हैं। अगर ऐसा है तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि <u>हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनकी अन्य राज्यों में सेवाएं रद्द की जायेंगी।</u>

श्री नरेन्द्र ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी हाल ही में उन्होंने हमीरपुर होस्पिटल में डाक्टरों की काफी नियुक्तियां की हैं। यह होस्पिटल काफी बड़ा है और इसमें लगभग 1200-1400 के करीब दैनिक ओ0पी0डी0 रहती है।

27.03.2018/1130/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 220 क्रमागत्

श्री नरेन्द्र ठाकुर .. जारी।

लेकिन वहां पर अभी तक भी स्पेशलिस्ट मैडिकल, सर्जन और चाइल्ड डॉक्टर नहीं है। ये पद काफी दिनों से खाली पड़ें हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां पर कब तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेज दिए जाएंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य जी ने धन्यवाद किया है, लेकिन धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो सरकार की जिम्मेवारियां हैं, हम इनको श्री जय राम ठाकुर जी की अध्यक्षता में आगे बढ़ा रहे हैं और पूर्ण कर रहे हैं। परन्तु अच्छा है, इन्होंने अच्छी परम्परा को आगे बढ़ाया, धन्यवाद तो किया। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जिन रिक्त पदों और विशेषकर स्पेशलिस्ट की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ओ0पी0डी0 की तादाद भी यहां काफी ज्यादा है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो रिक्त पदों को भरने की बात है, यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है और हम इस प्रक्रिया के तहत इन खाली पदों को आने वाले दिनों में अवश्य भरेंगे। मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं कि मैडिकल कॉलेज, हमीरपुर के लिए सरकार ने अधिकतर औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं। टीचिंग फेक्लटी भी वहां पर उपलब्ध करवा दी गई है और भारत सरकार को इस परिपेक्ष्य में पत्र भी लिखा गया है। ये माननीय मुख्य मंत्री जी का वायदा है, इसलिए अब हमीरपुर में शीघ्र ही मैडिकल कॉलेज बनने वाला है। ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री लखविन्द्र सिंह राणाः आदरणीय अध्यक्ष जी, नालागढ़ हॉस्पिटल 100 बैडिड हॉस्पिटल है और वहां पर औद्योगिकरण नजदीक होने के कारण उस हॉस्पिटल पर काफी ज्यादा प्रैशर रहता है। 100 बैडिड हॉस्पिटल में जितना स्टॉफ होना चाहिए था उसके हिसाब से

यहां पर स्टॉफ की कमी है। पिछले डेढ़ वर्षों से रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर वहां पर नहीं है। यहां पर जो पेशैन्ट्स आते हैं, उनको अल्ट्रासाउंड करवाने

27.03.2018/1130/TCV/HK-2

के लिए प्राइवेट क्लीनिक में जाना पड़ता है, जो बहुत महंगा पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक वहां पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की कमी को पूरा किया जाएगा?

दूसरा, हमारे नालागढ़ में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जोकि 10 बैडिड है। वहां पर सिर्फ दो डॉक्टर्ज़ हैं और ओ0पी0डी0 बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वहां पर काफी है। क्या माननीय मंत्री जी वहां पर डॉक्टर उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र, नालागढ़ में सी0एच0सी0 का जिक्र किया है। इन्होंने स्टॉफ की कमी और औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण वहां पर जो सी0एच0सी0 है, उसके ऊपर दबाव रहता है, का जिक्र किया है। इन्होंने यहां पर रेडियोलॉजिस्ट का भी जिक्र किया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को भी आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि कई जगह जो सी0एच0सीज0/पी0एच0सीज0 हैं, शायद कई वर्षों पहले, वहां जितनी जनसंख्या थी, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, अलग-अलग श्रेणियों के पद सृजित किए गये थे। लेकिन अब आबादी बढ़ने के कारण इसको रिव्यू करने की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी हमने आग्रह किया है कि इसको अवश्य रिव्यू किया जाये और वहां की जनसंख्या को मद्देनज़र रखते हुए यदि पद इत्यादि सृजित करने है तो वह भी किए जाएं। **माननीय सदस्य राणा जी यह सारा विषय हमारे ध्यान में है और हम प्राथमिकता पर इसको करेंगे।**

27-03-2018/1135/NS/HK/1

प्रश्न संख्याः 220 -----क्रमागत

अध्यक्षः अभी प्रश्न पूछने वालों की संख्या काफी अधिक है। मैं बोलता जाऊंगा, लेकिन पिछले कल भी स्वास्थ्य पर चर्चा हो चुकी है। अब श्री जगत सिंह नेगी जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य जल्दी से प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा होगा।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूं कि अभी जो इन्होंने लिखित में जवाब दिया है, उसमें आपने पैरामैडिकल और डॉक्टर्ज़ की कुल 3285 पोस्टों को ज़िक्र किया है। लेकिन अभी आपने जो यहां पर वक्तव्य दिया है, उसमें लगभग 6,000 पोस्टें खाली हैं। इन दोनों में जो विसंगति है तो आपकी कौन-सी बात ठीक है? हम लिखित को ठीक मानें या जो आपने यहां पर कहा है, उसको ठीक मानें। दूसरी बात जो आप यहां पर निरन्तर प्रक्रिया बता रहे हैं। यह निरन्तर प्रक्रिया क्या है और आप इसमें क्या कदम उठा रहे हैं? ----(व्यवधान)--- मुख्य मंत्री महोदय आपको बधाई, आप हमारे पद चिन्हों पर चल रहे हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य क्या आपका प्रश्न हो गया है? सप्लीमैंटरी में तीन प्रश्न नहीं होते हैं। अभी 15 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री जगत सिंह नेगीः अध्यक्ष महोदय, डायलिसिज़ की जो मशीन है, क्या वह मैन्युफैक्चर की जा रही है कि उसको बनाने में चार महीने का समय लग जायेगा? मशीन तो मार्किट में रेडिली अबेलेवल है। आप आज ले कर आओ और लगा दो, यह तो आज ही चल पड़ेगी। मैं जानना चाहता हूं कि यह मशीन क्या चार महीने से मैन्युफैक्चर हो रही है?

अध्यक्षः शायद विधायक महोदय ने माननीय मंत्री जी को ठीक से सुना नहीं है। इन्होंने कहा कि as on 31st, यह 6,000 vacancies हैं। माननीय मंत्री जी आप उत्तर दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : ----(व्यवधान)--- माननीय सदस्य ज़रा सुन तो लीजिये। अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने डायलिसिज़ मशीन के बारे में कहा है कि चार महीने का समय क्यों लग रहा है? मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह लोहे को कूटने वाला

काम नहीं है। व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अगर कोई टैक्नीशियन किसी का डायलिसिज़ करना शुरू कर दे और कुछ गड़बड़ी हो जाये तो यह गलत है।

27-03-2018/1135/NS/HK/2

डायलिसिज़ एक प्रक्रिया है और इसके लिए विभाग ने कुछ नॉर्म्ज़ निर्धारित किये हुए हैं तथा हमें उन्हें पूर्ण करना है। डायलिसिज़ के समय जो डॉक्टर्ज़, टैक्नीशियन और दवाईयों की जरूरत रहती है, इन सारी बातों को हमने पूर्ण करना है। हम इस बात को ले करके कमिटिड हैं कि लगभग हिमाचल प्रदेश के अधिकतर आर0एच0 अस्पताल और बड़े अस्पतालों तथा चिन्हित अस्पतालों में डायलिसिज़ का काम शुरू हो। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश में धर्मशाला, सोलन, मण्डी, कुल्लू, ऊना और बिलासपुर में डायलिसिज़ युनिट स्थापित हो चुके हैं और काम कर रहे हैं। शिमला के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल और सिरमौर में जल्द ही यूनिट शुरू हो जायेंगे। ---(व्यवधान)--- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमीरपुर, चम्बा, पालमपुर, नूरपुर और पांवटा साहिब में डायलिसिज़ यूनिट स्थापित करने के लिए टैंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इन स्थानों पर ये यूनिट स्थापित होंगे। इसके लिए मशीनें भारत सरकार के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां पर विलम्ब हुआ है, वहां पर बिडिंग होनी है। लेकिन इसके लिए हम कमिटिड हैं। माननीय सदस्य नेगी जी वकील भी हैं और यह कह रहे हैं कि आंकड़ों का कन्फयूज़न कैसे हो गया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टॉफ के कुल मिला करके लगभग 10,004 पद स्वीकृत हैं।

27.03.2018/1140/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः 220... जारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री... जारी

जिसके विरुद्ध लगभग 6,722 पद भरे हुए हैं तथा 3,282 पद रिक्त पड़े हुए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से यह विषय रख रहा हूं।

श्री नन्द लालः अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3,282 पदों का बैकलॉग पीछे से चलता आ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले तीन महीनों में विभाग द्वारा कितने डॉक्टर्ज़ के पद भरे गए हैं? हम यह मानते हैं कि पैरा-मैडिकल स्टाफ की भर्तियां स्टाफ सलैक्शन कमीशन, हमीरपुर से होती है। लेकिन वॉक-इन-इंटरव्यू से भी तो कुछ भर्तियां हो रही होगी। The first question is, what is the monthly intake of doctors in the last three months? दूसरा, जो डायलिसीज सैंटर प्राइवेट कम्पनी को दिया which will start functioning in the next four months? तो क्या विभाग दवाई देने वाला स्टाफ या अन्य स्टाफ अपने लैवल पर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है? इसे प्राइवेट कम्पनी को देने की क्या जरूरत थी?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब नई सरकार बनी तो यह ध्यान में आया कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर मैडिकल संस्थान खाली पड़े हुए हैं। जब लोग स्वागत करने के लिए आते थे तो एक एप्लीकेशन अपने साथ लाते थे कि हमारे स्वास्थ्य संस्थान खाली पड़े हुए हैं। उस समय यह चिंता होती थी कि इतने ज्यादा अस्पताल खोलने की क्या आवश्यकता है? मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की नीयत साफ है। सरकार बनने के बाद विभाग ने पिछले दो महीनों में 262 डॉक्टर्ज़ वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से रखे हैं। इन डाक्टर्ज़ को जहां-जहां स्टेशन दिए गए हैं, उनमें से अधिकतर ने वहां पर ज्वाइन कर लिया है। दूसरा, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डायलिसीज वाला काम क्या सरकारी नहीं हो सकता है? मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि सब कुछ हो सकता है। लेकिन हम यह काम पी.पी.पी. मोड़ पर कर रहे हैं। यह सारा काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हो रहा है।

27.03.2018/1140/RKS/YK-2

श्री बलबीर सिंह वर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, चौपाल, शिमला से 120 किलोमीटर दूर है।

चौपाल के क्षेत्रीय अस्पताल में पहले 6-6 बेडिड की सुविधा थी परन्तु पिछली बार इस अस्पताल में 50-50 बिस्तरों की सुविधा हुई है। वहां पर डाक्टरों की बहुत कमी है। एक प्रेग्नैंट महिला को अपने टैस्ट करवाने के लिए 120 किलोमीटर दूर शिमला आना पड़ता है। मेरी आपसे विनती है कि इस दूर-दराज क्षेत्र में डाक्टर्ज और नर्सिज के रिक्त पदों को जल्द-से-जल्द भरा जाए ताकि स्वास्थ्य की दृष्टि से मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि चौपाल और यहां के दूर-दराज क्षेत्रों में अभी भी डाक्टर्ज़ के पद खाली पड़े हुए हैं। मैंने पहले भी कहा है कि वॉक-इन-इंटरव्यू की प्रक्रिया एक निरंतर और सतत् प्रक्रिया है। जैसे-जैसे इंटरव्यूज होते रहेंगे, डाक्टर्ज़ की कमी दूर होगी और हम आपके विधान सभा क्षेत्र का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि जहां विभाग ने 262 डाक्टर्ज/एम.ओज. नियुक्त किए हैं, वहीं पर हम 52 डैंटल सर्जन भी आने वाले दिनों में अलग-अलग अस्पतालों में नियुक्त करने वाले हैं। यह मैं इस सदन को अवगत करवाना चाहता हूं।

27.03.2018/1145/बी0एस0/वाई0के0-1

प्रश्न संख्याः 220.....जारी

श्री सुरेश कुमार कश्यपः माननीय अध्यक्ष महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरांह का दर्जा पूर्व सरकार के कार्यकाल में बढ़ाया गया था। इसमें बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 की गई थी। लेकिन पद स्वीकृत नहीं किए गए थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक इस सी.एच.सी. में पद स्वीकृत कर दिए जाएंगे और कब तक उनको भर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय सदस्य ने सरांह सी.एच.सी. के बारे में बात कही है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिनकी घोषणाएं हो गई हैं और वित्त

विभाग से कोई स्वीकृति नहीं हुई न ही पद स्वीकृत हुए हैं। ऐसे हिमाचल प्रदेश में बहुत से अस्पताल रिव्यू में हैं। यह अस्पताल भी रिव्यू में है। उस अस्पताल को अपग्रेड करने के क्या मापदंड रहे, उनकी संवीक्षा करने के पश्चात ही फैसला लिया जाएगा। मापदंड के अनुसार आपका अस्पताल सही पाया गया तो उस पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्षः मैं इसके बाद 3 सप्लीमेंट्री दूंगा, मेरे सामने 15 माननीय सदस्यों के हाथ खड़े हैं।

श्री राकेश कुमारः माननीय अध्यक्ष जी, सुन्दरनगर का सिविल अस्पताल जिसकी ओ.पी.डी. अनेकों जिला अस्पतालों से ज्यादा है। पूर्व की सरकार ने उस अस्पताल में 100 बिस्तरों से 150 बिस्तरों तक संख्या बढ़ाई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह मात्र घोषणा ही है या उस अस्पताल का दर्जा बढ़ा दिया गया है? उसके साथ-साथ चुनावों से पहले ही सर्जरी के और गायनी के डॉक्टर्स की वहां से बदली हो गई थी। लेकिन उन्हीं दोनों डॉक्टर्स डेपुटेशन में सुन्दरनगर सिविल अस्पताल के लिए जिस दिन चुनाव हुए थे, उस दिन तक के लिए था और दूसरे ही दिन वे वहां से बदली हो गए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टर्स की नियुक्ति कब तक वहां की जाएगी? इसके साथ-साथ सुन्दरनगर सिविल अस्पताल में डाक्टर्स के 12 पद स्वीकृत हैं और ओ.पी.डी. जैसा मैंने कहा कि जिला अस्पताल से ज्यादा है। अन्य सिविल अस्पताल ऐसे भी हैं जहां पर 18-18 पद भी डाक्टर्स के स्वीकृत हैं। क्या भविष्य में सुन्दरनगर सिविल अस्पताल में सरकार डाक्टर्स के पद बढ़ाने का विचार रखती हैं?

27.03.2018/1145/बी0एस0/वाई0के0-2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने जानना चाहा है कि जो इनका सिविल अस्पताल है उसे अपग्रेड किया गया है और इसमें 100 बिस्तरों से बढ़ाकर इनकी संख्या 150 की गई है। मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से अस्पताल हैं और एक लम्बी सूची है। अब जो हमारे मानक

सुनिश्चित किए गए है, उसमें यह ठीक है या नहीं , रिव्यू करने के बाद, संवीक्षा करने के बाद ही हम इसका उत्तर दे सकते हैं और जहां तक इन्होंने सर्जरी और गायनी के डाक्टर्स के लिए कहा है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मुझे भी आपके इस अस्पताल में जाने का मौका मिला था। अच्छा अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है। काफी तादाद में वहां ओ.पी.डी. है। जो भी वहां विशेषज्ञों की कमी है आने वाले उस सतत प्रक्रिया में इस सिविल अस्पताल सुन्दरनगर को हम प्राथमिकता देंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयालः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय स्वास्थ मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने चम्बा जिला का दौरा किया और जो हमारा मैडिकल कॉलेज है और चम्बा का अस्पताल है, जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित था वहां इन्होंने मूलभूत सुविधाएं प्रदान की, लेकिन इसके साथ ही मैं मंत्री जी का ध्यान उन डाक्टर्स की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि सरकारी अस्पतालों में ड्यूटियां दे रहे हैं परंतु साथ ही उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले हुए हैं। इस बात को भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। साथ ही मेरा सिविल अस्पताल चुआड़ी है। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का इन्होंने फट्टा लगा दिया था। बाकी उसमें कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। डाक्टर्स नहीं है, पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं हैं मशीनों की कमी है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कब तक मेरे सिविल अस्पताल चुआड़ी में मूलभूल सुविधाएं प्रदान करेंगे?

27032018/1150/AG-DT/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी ने कहा है कि कुछ डॉक्टर सरकारी सेवा में होने के उपरान्त भी प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही बात कल हमारे विपक्ष के कुछ माननीयों सदस्यों द्वारा भी कही गई थी। विशेषकर जो हमारे सीमावर्ती ज़िले हैं वहां पर ऐसा अधिक हो रहा है। मै माननीय

सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ऐसे चिकित्सक जो प्राईवेट प्रैक्टिस कर रहें हैं, उनका नाम व उस संस्थान का नाम जहां वह कार्यरत हैं, यानी पूरा पता अगर हमें मिल जाये तो हम अवश्य इस मामले की छानबीन कर इस पर कार्रवाई अम्ल में लायेंगे । दूसरी बात जो माननीय सदस्य ने कही कि फटटा लग गया। फटटे तो काफी जगह लगें हैं। लेकिन जहां फटटा लगाया गया क्या वह संस्थान स्वास्थ्य विभाग के मापदण्डों के अनुसार ठीक हैं या नहीं, क्या वह मानकों के अनुरूप हैं या नहीं ? इस बात की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है और समीक्षा करने के बाद ही इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राकेश पठानियाः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा , यह एक बहुत गम्भीर विषय है, प्रश्न भरी जिससे सम्बन्धित है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि हमीरपुर में आपने अभी डॉक्टर भेजे, इसमें 14 स्पैशलीस्ट आपने टांडा मैडिकल कॉलेज से भेजे। क्या यह सत्य है कि पैरा-मैडिकल के लगभग 500 से अधिक पद टाण्डा मैडिकल कॉलेज में रिक्त् हैं? क्या माननीय मन्त्री इस बात से सहमत है कि जो प्राईमरी हैल्थ सेन्टर है जो हमारे गावं को फीड करते हैं, पूरे ज़िला कांगड़ा के प्राईमरी हैल्थ सेन्टर में एक भी गाईनाकोलोजिस्ट उपलब्ध नहीं है। Is it a fact or not? ऐसी परिस्थितियों में where is the hurry to run a medical college? जब नाहन मैडिकल कॉलेज बना था तब नूरपूर से गाईनाकोलोजिस्ट गये थे आज तक वह गाईनाकोलोजिस्ट वापिस नहीं आये। मैडिकल कॉलेज खोलने की इतनी जल्दी क्या है, एम0सी0आई0 की रिक्वायरमेन्ट के लिए क्या आप डॉक्टरज़ को एक जगह इक्टठा कर लेंगे? जहां पर डॉक्टर नहीं है वहां पर क्या होगा? What will happen to the patients

27032018/1150/AG-DT/2

in Tanda and in small PHCs?पी0एच0सी0 का बेसिक कन्सेप्ट ही महिलाओं की सेवा करना है। एक भी गाईनाकोलोजिस्ट हमारी किसी भी पी0एच0सी0 में नहीं है। There is not

even one Gynaecologist in complete District Kangra. मेरा आग्रह है माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय से अनुरोध है instead of hurrying for a medical college जो हमारे अन्य पी0एच0सी0 या सिवील चिकित्सालय है उनका सुदृढीकरण करें उसके बाद ही मैडिकल कॉलेजिज़ की ओर ध्यान दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है हो सकता है कि उनकी यह चिन्ता किसी हद तक ठीक हो कि मेडिकल कॉलेजिज़ को शुरू करने के लिए जल्दबाज़ी क्यों और किस लिए? एक तो मै यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे मैडिकल कॉलेज चल रहे हैं उसमें जो नाहन का मैडिकल कॉलेज है वहां पर एम0सी0आई0 की टीम ने दौरा किया है और लगभग उस मेडिकल कॉलेज के लिए जो आवश्यक मापदण्ड है वह हमनें पूर्ण किये हैं। नेर चोक मैडिकल कॉलेज व चिकित्सालय में एम0सी0आई0 आज वहां आ रही है। मै यह कहना चाहता हूं कि जो यह मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय आप तो स्वयं भी स्वास्थ्य मन्त्री रहे है आप जानते है कि कितनी कठिन परिस्थितयां रहती हैं। लेकिन हमने लगभग इन सभी मेडिकल कॉलेजिज़ की जो आवश्यकताऐं है हम उनको पूर्ण कर रहे हैं। सभी मानक जब पूरें होते हैं उसके उपरान्त ही एम0सी0आई0 किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अपनी मोहर लगाती है। मै यह कहना चाहता हूं कि हमारे सभी मेडिकल कॉलेज एम0सी0आइ0 के मानकों को पूर्ण कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा है कि हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज, यह कॉलेज हमारी प्राथमिकता में हैं और यहां फेकल्टी को मजबूत करने के लिए हम कहीं से कोई प्रोफेसर या डॉक्टर यहां पर नहीं ला रहे।

27.03.2018/1155/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 220 ..जारी

माननीय स्वास्थ्य मंत्री...जारी

राकेश पठानियां जी, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि हमारी जितनी फैकल्टी बन रही है उसमें अधिकतर डॉक्टर्ज़ अन्य प्रांतों से आ रहे हैं। हम इंटरव्यु कंडक्ट कर रहे हैं और इंटरव्यु के तहत जो एक प्रोफ़ैसर, एसोसिएट प्रोफ़ैसर या असिस्टैंट प्रोफ़ैसर के पद के लिए ज़रूरी एलिजिबिलिटी है, उसको पूर्ण कर रहे हैं। इसलिए हम किसी संस्थान से डॉक्टर्ज़ को लाकर उनको खाली नहीं कर रहे हैं। तीसरे, आपने पैरा-मैडिकल स्टॉफ के बारे में कहा। जो टाण्डा का मैडिकल कॉलेज है, राकेश पठानिया जी, सुपर स्पैसिलिटी वहां पर चल रही है। दुर्भाग्य यह है कि जल्दबाज़ी में उसका केंद्रीय मंत्री जी ने लोक सभा के चुनावों के समय, जिसका ज़िक्र माननीय सदस्यों ने इस तरफ से किया, कहीं से ऑनलाईन उदघाटन कर दिया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, वहां पर पैरा-मैडिकल का तो स्टॉफ ही सैंक्शन नहीं हुआ। इसलिए जो हमारे पास पैरा-मैडिकल की कॉलेज की 199 सीटें हैं, उन्हीं से गुज़ारा चल रहा है। मैं आपके माध्यम से इस हाऊस को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी से भी हमने विचार-विमर्श किया है कि जो हमारी सुपर स्पैसिलिटी है, वहां पर पैरा-मैडिकल का स्टॉफ सृजित करने के लिए हमें आपकी हमें सहमति चाहिए, यह भी मैं कहना चाहता हूं। तीसरे, आपने कहा कि पी.एच.सीज. मज़बूत होनी चाहिए। यह जो 262 डॉक्टर्ज़ लगाए गए हैं, उनसे पी.एच.सीज. मज़बूत होंगी। आपने यह भी कहा कि स्पैस्लिस्ट डॉक्टर्ज़ की कमी है, मैं बार-बार यही कहना चाहता हूं कि उस सतत प्रक्रिया में स्पैस्लिस्ट डॉक्टर्ज़ के पद हम अवश्य भरेंगे। जो माननीय सदस्य ने चिंता प्रकट की है, उसमें मैं आपके साथ हूं।

अध्यक्ष : विनोद जी, आप शीघ्रता से पूछें क्योंकि मैंने अभी 3 सदस्यों से बुलवाना है। अब मेरे पास केवल 3 मिनट हैं।

27.03.2018/1155/SLS-AG-2

श्री विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.सी. चौक है, जिसका ज़िक्र मैंने पीछे भी आपसे

किया था। आपने जो भी नए डॉक्टर्ज़ के पद भरे थे, उनमें से एक के ऑर्डर वहां के लिए किए थे जिसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन उन डाक्टर्ज़ ने अभी तक वहां पर ज्वॉयन नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यह जो जिला मण्डी की पी.एच.सी. चौक है, यह ऐसी पी.एच.सी. हैं जहां पर डेली ओ.पी.डी. 200-250 तक होती है। वहां के लिए आप जल्दी से डॉक्टर भेजने की कृपा करें। दूसरे, एक हमारा आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केंद्र सेगली है। पिछले 5 वर्षों से वहां का डॉक्टर डैपुटेशन पर है। वह सैलरी सेगली से निकालता है। जब मैंने पिछली सरकार के समय में ज़िक्र किया था तो कह रहे थे कि सरकार के बिल्कुल करीबी है। मेरा निवेदन रहेगा कि आप आज ही विभाग को आदेश करें कि उसका डैपुटेशन खत्म किया जाए और जहां से वह सैलरी लेता है, वहीं पर इसको भेजा जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, जो श्री विनोद जी ने पी.एच.सी. चौक के बारे में कहा है, वहां पर हमने आदेश किए थे और कोशिश रहेगी कि जिनके आदेश किए हैं वह वहां पर ज्वॉयन करें। मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं, इन्होंने आयुर्वैदिक हॉस्पिटल या आयुर्वैदिक मैडिकल सैंटर्ज़ की बात भी की है, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन आयुर्वैर्दिक डॉक्टर्ज़ के पदों को भरने के लिए 200 पद स्वीकृत हो चुके हैं। आने वाले दिनों में यह कमी भी पूर्ण होगी। मैं विनोद जी को कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा है कि बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति डैपुटेशन पर कहीं लगा है, आपने पहले भी आग्रह किया था, अब इसका डैपुटेशन हमने रद्द कर दिया है। यह जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं।

श्री पवन कुमार काजल : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि कांगड़ा सिविल हॉस्पिटल में पहले केवल एक डॉक्टर था, अब 3 हो गए हैं और कुल मिलाकर 4 हैं जो चारों लेडी डॉक्टर्ज़ हैं। 'बेटी है अनमोल' बात का हम सम्मान करते हैं। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस हॉस्पिटल के लिए 8 पद स्वीकृत थे। मैंने आपसे बार-बार आग्रह भी किया कि इस हॉस्पिटल में 900-1000 के बीच ओ.पी.डी. हैं।...(व्यवधान)...

27.03.2018/1155/SLS-AG-3

अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए, समय समाप्त हो रहा है।

श्री पवन कुमार काजल : आज की तारीख में 250-300 के बीच ओ.पी.डी. हैं। यहां पर जो 4 लेडी डॉक्टर्ज़ हैं वह MBBS हैं। क्या आप कांगड़ा को स्पैस्लिस्ट्ज देंगे चाहे गाइनी स्पैस्लिस्ट ही हो।

27/03/2018/1200/RG/DC/1
प्रश्न सं. 220--- क्रमागत
श्री पवन कुमार काजल-----जारी

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्ट्रासॉउण्ड की मशीन वहां 3-4 महीनों से धूल फांक रही है, तो क्या आप वहां रेडियोलॉजिस्ट का पद भरेंगे?

अध्यक्ष : पवन जी, समय हो गया। क्या फायदा आपको उत्तर नहीं मिल पाएगा। वैसे तो इस विषय पर कल भी चर्चा हो चुकी है।

श्री पवन कुमार काजल : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो पवन कुमार काजल जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन आज वहां हैं। सबसे पहले तो इन्होंने धन्यवाद किया है। धन्यवाद तो माननीय मुख्य मंत्री जी का कि इनके आदेशानुसार हमने चिकित्सकों की नियुक्तियां की हैं। **इन्होंने विशेषज्ञों की बात की है, तो अवश्य आने वाले दिनों में जब भी नियुक्तियां होंगी, तो हम इस अस्पताल का ध्यान जरूर रखेंगे।** वैसे टांडा मैडिकल कॉलेज इनके यहां से नजदीक है। वहां भी विशेषज्ञ हैं और हमारी हर फैकल्टी बहुत मजबूत है, परन्तु जिन बातों का जिक्र इन्होंने किया है, वह मेरे ध्यान में है। उनका अवश्य ध्यान रखेंगे।

श्री सुभाष ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, बिलासपुर जिला अस्पताल एक जोनल अस्पताल है। वहां डॉक्टर्ज के 25 पद हैं और बिलासपुर अस्पताल एक ऐसी जगह स्थित है कि वह

बहुत ही संवदेनशील क्षेत्र है। चार हजार ट्रक प्रतिदिन वहां चलते हैं और मनाली को वहां से ही सारे पर्यटक जाते हैं।

अध्यक्ष : आप सीधे प्रश्न करें। समय कम है।

श्री सुभाष ठाकुर : और वहां प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन वहां और्थोपैडिक का एक भी डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर था उनको हमीरपुर ले गए। एक रेडियोलॉजिस्ट था, उसको नाहन ले गए। इसी तरह से वहां चार डॉक्टर्ज हैं वे अवकाश पर हैं। वहां 7-8 डॉक्टर्ज हैं, बाकी कोई नहीं है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक निवेदन है कि जितने भी जिला अस्पताल हैं, पहले उनकी स्थिति सुदृढ़ कीजिए। उसके बाद कम्युनिटी और प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्ज की स्थिति सुदृढ़ कीजिए। इसके लिए

लिए पॉलिसी लाइए ताकि हर जिला अस्पताल में जो भीड़ होती है, वहां सबको सुविधा मिले। माननीय मंत्री जी की तो वहां ससुराल है इसलिए ये वहां का ध्यान रखेंगे। मेरा इनसे यही निवेदन है।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी ने बहुत विस्तार से इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। लेकिन मैं देख रहा था कि एक प्रश्न में ही प्रश्नकाल का आधा समय निकल गया। स्वाभाविक रूप से विषय की गंभीरता इस बात से आंकी जा सकती है कि संस्थान तो खुले हैं, लेकिन संस्थान खुलने के पश्चात वहां चिकित्सकों, पैरा मैडिकल स्टाफ इत्यादि की उपस्थिति न होना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें सबको सहयोग देने की आवश्यकता है। आप (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) यहां से वहां चले गए और जो करके गए वह सबके सामने है। हम अन्धाधुंध विस्तार की तरफ चले गए और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि जो हम कर रहे हैं, उसकी हालत क्या है? मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इन सारी चीजों के लिए थोड़ा समय चाहिए। हमारे पास दो चीजों के विकल्प हैं। या तो जो खोले गए संस्थान जिनका जिक्र कर रहे हैं कि वहां इतने पद सूजित करिए। पद सृजित करना तो बहुत आसान काम

है। उसमें कुछ नहीं लगता, एक कागज़ ही लगता है। एक निर्णय करना होता है और निर्णय के मुताबिक एक कागज़ पर अधिसूचना जारी कर दी जाती है कि ये पद हमने सृजित कर दिए। लेकिन पदों को भरना एक अलग बात होती है और आप जो कर गए हैं, वह सिर्फ पदों का सृजन करके, संस्थान खोलकर और फट्टे लगाकर चले गए। ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर से दो विभाग एक शिक्षा विभाग और दूसरे स्वास्थ्य विभाग में बहुत कठिनाई है और दोनों ही ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनका सभी व्यक्तियों के जीवन से हमेशा संबंध रहता है। इस दृष्टि से सरकार गंभीर है, प्रयत्न कर रही है और उसके बाद इसमें कार्य करेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 200 डॉक्टर्ज के पद अभी तुरन्त डेढ़ महीने के कार्यकाल में ही भर दिए। लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा समय चाहिए। हमारे मित्र जिस प्रकार से सारी

27/03/2018/1200/RG/DC/3

व्यवस्थाओं को तहस-नहस करके चले गए हैं, आज इस ओर उनकी चिन्ता मुझे वाज़िब नहीं लगती। आप सहयोग दें। अगर आपको लगता है, तो आप अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में तय करें और हमें प्राथमिकता सूची दीजिए कि मुझे इस स्वास्थ्य संस्थान में डॉक्टर चाहिए और उसके बदले में दूसरे संस्थान में चाहे एक साल बाद पद भरिए, लेकिन इस संस्थान में मुझे डॉक्टर चाहिए। आप प्राथमिकता देंगे, उसके अनुसार हम करेंगे।

27.03.2018/1205/जेके/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 220ः-----**जारी**-------

मुख्य मंत्रीः----**जारी**-------

लेकिन आपके समय में दो किलोमीटर पर पी0एच0सी0, तीन किलोमीटर पर पी0एच0सी0 खोल दी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोले हुए चार-चार साल हो गए हैं और आठ

पी0एच0सी0 खोल कर चले गए लेकिन चार सालों से उनमें ताले लगे हुए हैं। अब हम उनको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारी चाजों के बारे में आज सोचने की आवश्यकता दोनो तरफ से है और मेरा आप लोगों से इतना ही निवेदन है। मैं विभाग को बधाई देता हूं कि विभाग इसमें गम्भीरता से लगा हुआ है और इस गम्भीरता को आप लोग भी समझें, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूं।

प्रश्न काल समाप्त

27.03.2018/1205/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम पड़ा कि प्रश्न काल आरम्भ होने से पहले शायद यहां पर कुछ बात हुई थी कि कुछ लोग विधान सभा के परिसर में आ गए थे और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इस बात को लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति दर्ज़ की जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह सारा ज्ञान यहां से वहां जाने पर क्यों आता है? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, गवाह हूं कि यहां पर बाजे-गाजे के साथ लोग आते रहे हैं । कांग्रेस पार्टी का झण्डा हाथ में लेकर आते रहे। यहां पर जिन्दाबाद के नारे लगते रहे। यहां नीचे विधान सभा परिसर में नाटी डालते रहे। मेरे पास उसके प्रमाण है। हमारे पास उसकी वीडियो है। उसके बाद विधान सभा का सत्र धर्मशाला में शुरू होता है और उस वक्त आपकी सरकार का पहला सत्र था उस समय विधान सभा कम्पलैक्स में कांग्रेस पार्टी के नेता गले में कांग्रेस का पटका डाल करके, जिसमें हाथ का निशान और बैजिज लगा करके दर्शक दीर्घा में बैठे रहते थे। जब मैंने वहां विधान सभा के अन्दर प्वाइंट आउट किया था कि यह विधान सभा के अन्दर कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पटके लगा करके वहां पर आ जाओ। इन सारी चीजों को ले करके क्या सोचने की आवश्यकता नहीं है?...व्यवधान.. लेकिन यह ज्ञान, ये सारी चीजें ये सोचते हैं। ...(व्यवधान)..

अध्यक्षः कृपया बैठिए, मुकेश जी, मैं आपको समय दूंगा। एक मिनट, इनको बोलने दीजिए।

मुख्य मंत्रीः यहां पर हमारे लोग आए, प्रदेश की जनता मुख्य मंत्री को मिलने आती है । उनके हाथ में न तो पार्टी का झण्डा था, न ही वे कोई बैजिज़ लगा करके आए और न ही कोई पार्टी का नारा लगा। उन्होंने जो नारा मुख्य मंत्री का लगाया उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों पर सोचना चाहिए। ....व्यवधान.... मुकेश जी जस्टिफाई करने की बात नहीं है। उन्होंने कोई पार्टी का नारा नहीं लगाया। वे आए, बैठे और अपनी समस्या का ज़िक्र किया। समस्या का ज़िक्र करने के बाद हमने उनकी बात सुनी। आप क्या चाहते हैं कि विधान सभा में

हम लोगों से कोई आदमी मिलने ही न आएं? अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इन सारी चीजों का कोई अभिप्राय नहीं है जिस प्रकार से ये बातें कर रहे हैं। ....व्यवधान.... आप भी इसको हमारी कमज़ोरी न समझें। ..(व्यवधान)..

अध्यक्षः मुकेश अग्निहोत्री जी आप बोलिए। ....व्यवधान.... आप लोग बैठिए। ....व्यवधान.... मुकेश जी, मैं आपको समय दे रहा हूं आप बोलिएगा। ....व्यवधान.... आप लोग बैठिए। ....व्यवधान.... मुकेश जी बोलना चाहते हैं, आप बोलिए। आप लोग बैठिए, इनको बोलने दो। ....व्यवधान....

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दें कि इसमें चर्चा नहीं होगी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसमें चर्चा नहीं होगी और अध्यक्ष महोदय, आपने भी रूल कोट कर दिया और मुख्य मंत्री जी उस पर बोल रहे हैं। ....व्यवधान....

(पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

अध्यक्षः आप लोग बैठिए और मुकेश जी को अपनी बात रजिस्टर्ड करवाने दीजिए। ....व्यवधान....प्लीज बैठिए। ....व्यवधान....प्लीज बैठिए। मुकेश जी एक मिनट बैठिए। मुकेश जी क्या आप सुनेंगे? ....व्यवधान....

27.03.2018/1210/SS-HK/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम संख्या बल से डरने वाले नहीं हैं। हमें संख्या बल के बूते दबाने की कोशिश कर रहे हैं। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः क्या आप एक मिनट सुनेंगे?

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः हैल्थ पर सब ने कहा, हम सुनते रहे। मुख्य मंत्री जी यह समझें कि जितने भी इंस्टिट्यूशन्ज़ खुले हैं वे बाकायदा नियमों के मुताबिक खुले हैं, हम चाहते हैं कि सरकार उनको चलाए।

अध्यक्षः मुकेश जी, एक मिनट सुनिये। राकेश जी, आप ठहरिये। राकेश जी, यह क्या हो रहा है? आप बैठिये प्लीज़।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह सरकार है या -(व्यवधान)-

अध्यक्षः मैडम एक मिनट, मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आप कृपया केवल थोड़ा-सा हाथ ऊपर करें, मैं नज़र रखता हूं, आप अपनी बात बोलें और आप तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के स्थान पर हैं, आप किसी भी समय हाथ करेंगे तो हम तुरन्त आपको परमिशन देंगे। कृपया बिना परमिशन के कोई भी मत बोले। इतने अच्छे ढंग से सारा विषय आ रहा है, मुख्य मंत्री जी ने अपनी बात की है, आप अपनी बात बोलें। मैं आपको समय दे रहा हूं, मुकेश जी आप बोलिये।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, कल हमारे माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी ने यह मसला आपके समक्ष लाया। आपने कहा कि मेरे ध्यान में यह बात आ गई है। आपने जजमैंट रिजर्व की है या आप इस पर कोई उचित फैसला देंगे? आज हमने आपको

लिखकर भी दिया और यहां पर मुख्य मंत्री जी भी पांचवीं टर्म के एम0एल0ए0 हैं, इन्होंने सारी परम्पराएं और मान्यताएं देखी हैं। इस हाउस की अपनी गरिमा और मर्यादा है। हमने आपको सुबह भी कहा कि हमने आप पर आक्षेप नहीं किया है। हमने व्यवस्था की बात की है कि बिल्कुल सदन के बाहर ढोल-नगाड़े बज रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। ये मुख्य मंत्री जी के गेट के बाहर बज जाएं या नीचे वाले गेट पर बजें जोकि हमेशा होता रहा, सारे प्रदर्शन जितने भी होते हैं वे सारे वहां पर रोके जाते हैं।

27.03.2018/1210/SS-HK/2

यह पहली दफा हो रहा है कि सारे लोग ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं और उनसे नारे लगवाए जा रहे हैं। झंडे लेकर लोग ऊपर आ रहे हैं। यह सदन की सिक्योरिटी का भी सवाल है। एम0एल0ए0 की सुरक्षा का भी सवाल है और यहां की मान्यताओं और परम्पराओं का भी सवाल है। मुख्य मंत्री जी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं चलेगी। मुख्य मंत्री जी अगर इसको जस्टिफाई करते हैं तो हम इसकी घोर निन्दा करते हैं कि आप सदन के अंदर ऐसी परिपाटी डाल रहे हैं।

27.03.2018/1210/SS-HK/3

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम नहीं कि क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं। इस विषय पर कम-से-कम इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। लोग मिलने आते हैं, पहले भी आते थे, अब भी आते हैं और आगे भी आयेंगे। लेकिन आप आखिरकार इन सारी बातों पर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं! सरकार लोगों की है। लोगों को हमसे मिलना है और हमें लोगों से मिलना ही है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि पहले तो एक बात स्पष्ट कर रहा हूं कि कल जो लोग आए थे, न किसी के पास झंडा था और न ही कोई पार्टी का नारा लगा। मुख्य मंत्री का नारा लगा तो मुझे लगता है कि इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि ये सारी परम्पराएं कहां से बिगड़ी हैं? जब लोगों ने पिछली बार देखा है कि यहां झंडा लेकर भी जा सकते हैं, यहां बाजे लेकर भी जा सकते हैं, यहां अंदर नाटी भी डाली जा सकती है और एक नेता को उधर गेट से कंधे पर

ले करके यहां तक पहुंचाया और एक नेता को कंधे पर उठा करके यहां से वहां तक पहुंचाया और मेरे ही विधान सभा क्षेत्र का था और मुख्य मंत्री जी ने उनको यहां पर सम्बोधित किया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैंने वह सारा कार्यक्रम अपनी आंखों से देखा हुआ है। उसकी वीडियो हमारे लोगों के पास है। हम तो उस हद तक नहीं जा रहे हैं। कोई हमसे मिलने आए और उन्होंने मुख्य मंत्री का नारा लगा दिया तो इस पर इतनी घोर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके कारण कोई अव्यवस्था का माहौल हो गया, अशांति का माहौल हो गया, आपकी सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो गया, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को उस तरह से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप राजनीति करो, उसमें कोई मना नहीं है लेकिन इन सारी चीज़ों के लिए थोड़ा खुला मन रखिये।

27.03.2018/1215/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री जारी----

अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगें कि जो बड़े डेलिगेशन्ज़ आते हैं, वे व्यवस्थित ढंग से आएं लेकिन हमारी मुश्किल यह है कि पूरे देश में हिमाचल की मात्र एक ऐसी विधान सभा है जहां पर हमारे पास इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वहां पर एक बड़ा डेलिगेशन आ सके। यहां लोग जब मंत्रियों से मिलने आते हैं तो बेचारे गली में खड़े होते हैं, आपके समय में भी और हमारे समय भी ऐसा ही है। हमारे पास जगह ही नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जब लोग बड़ी तादाद में आए तो उनके कारण रास्ते में गाड़ियों को असुविधा हो, विधायकों व मंत्रियों को आने-जाने में असुविधा हो लेकिन समस्या यह है कि विधान सभा कम्पलैक्स में लोगों को मिलने के लिए स्थान ही नहीं है। यही स्थिति सचिवालय में भी है। वहां भी लोग मिलने आते हैं तो सड़क से हो कर पूरी गैलरी से होकर मुख्य मंत्री के कार्यालय तक खड़े होते हैं। यह हमारी भौगोलिक परिस्थिति के कारण है। इस दौर से हमें गुजरना है। आप लोगों को असुविधा हुई, इसका हमें खेद है लेकिन उसके बावजूद हमारी बिल्कुल भी मन्शा नहीं थी, जो आप लोग उसमें से कारण निकालने की कोशिश कर रहे हैं वह नहीं निकालना चाहिए। हालात ऐसे हैं, परिस्थिति है। लोग यहां मिलने आएंगें उनसे मिलने के लिए या तो हमें गली में खड़ा होना पड़ेगा या बाहर जा कर

मिलना पड़ता है। आप मुझे स्थान बताएं, मैं उनसे वहां मिल लूंगा लेकिन कम से कम इतना तो हमको सोचना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में क्या व्यवस्था है ?उस व्यवस्था को हम ठीक प्रकार से संचालित करने की दृष्टि से सहयोग दें। इतना मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय नेता, कांग्रेस दल ने विषय बखूबी उठाया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इन्टरवीन किया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी व्यथा भी बताई और उससे आगे बढ़ कर आपको आश्वासन भी दिया कि हम इस बात को एन्श्योर करेंगें कि किसी को कोई परेशानी न हो और इससे भी आगे बढ़कर इन्होंने यह तक कह दिया कि किसी को असुविधा हुई होगी तो उनको खेद है । मैं एक बात सभी सदस्यों और सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हम सभी मिल कर परिसर की व्यवस्थाओं को और परिसर की जो गरिमा है, उसकी व्यवस्थाओं और उसकी परिपाटी को मेंटेंन करने में सहयोग करें और इतने पर ही इस विषय को हम समाप्त करना चाहेंगें।

27.03.2018/1215/केएस/एचके/2

प्रश्नकाल के बाद कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखे जाने हैं, उससे पहले मैंने व्यक्तिगत तौर पर सभी माननीय सदस्यों को पत्र भी लिखा और उसके बाद निमंत्रण पत्र भी भेजा है और पुनः एक बार समृति के लिए याद करवा रहा हूं कि आज सांयकाल पीटरहॉफ में वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक परिचर्चा है और माननीय मुख्य मंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के नाते रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के नाते मुकेश अग्निहोत्री जी रहेंगे और हम सभी विधायकगण और कुछ चिन्हित अधिकारीगण, मिडिया के साथ उसमें रहेंगे। तत्पश्चात् डिनर का आयोजन है। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वाटर कंजर्वेशन के दो विशेषज्ञ एक राजस्थान और एक महाराष्ट्र से बुलाए गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि सदन के बाद हम सभी लोग पीटरहॉफ पधारने का कष्ट करें।

27.03.2018/1215/केएस/एचके/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि औद्यानिकी एवं वानिकी अधिनियम, 1986 की धारा 45(4) के अन्तर्गत डा0 वाई0एस0 परमार, औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब माननीय शिक्षा मन्त्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

शिक्षा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, आचार्य, (संस्कृत, महाविद्यालय संवर्ग) वर्ग-।(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःई.डी.एन.-ए-ख(2)/32/2014 दिनांक 21.02.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.02.2018 को प्रकाशित;
ii. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 15(1) और (4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2016-17 (1.4.2016 से 31.3.2017 तक);

iii. हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग अधिनियम, 2010 की धारा 13(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17; और

27.03.2018/1215/केएस/एचके/4

iv. हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 3 के साथ पठित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 की उप-धारा (1) और (2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन ब्यौरे की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वर्ष 2016-17 (01-04-2016 से 31-03-2017 तक) ।

अध्यक्षः अब माननीय उद्योग मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अधिनियम, 1966 की धारा 27(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित);
ii. हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम (SFCs Act) अधिनियम, 1951 की धारा 37(7) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय निगम का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2016-17

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, संयुक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017

जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-3/2016 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 01. 12.2017 को प्रकाशित;

27.03.2018/1215/केएस/एचके/5

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(औद्योगिक), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(बी)2-4/2009-। दिनांक 28.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03. 01.2018 को प्रकाशित;

iv. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(रसायन), वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(बी)15-3/2010 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.12.2017 को प्रकाशित;

v. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, तहसीलदार, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-2/2017 दिनांक 12.10.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.11.2017 को प्रकाशित;

vi. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, निजी सचिव, वर्ग-। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-2/2016 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 13.03.2018 को प्रकाशित;

vii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, प्रोग्रामर, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-1/2016 दिनांक 04.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11. 07.2017 को प्रकाशित;

27.03.2018/1215/केएस/एचके/6

viii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अधीक्षक, ग्रेड-1, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःइण्ड-ए(ए)3-4/2017 दिनांक 30.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.03.2018 को प्रकाशित; और

ix. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्ते विनियमन) संशोधन नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःश्रम(ए)2-1/2013-भाग-II बी.ओ.सी.डब्ल्यू. दिनांक 19.01.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.02.2018 को प्रकाशित ।

अध्यक्षः अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 23(2) के अन्तर्गत बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

27.3.2018/1220/av/yk/1

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2017-18) के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति (वर्ष 2017-18) के कुछ प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करती हूं तथा सदन के पटल पर रखती हूं :-

i. समिति का अष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 124वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित है;

ii. समिति का नवम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 138वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा मत्स्य विभाग से सम्बन्धित है;

iii. समिति का दशम् कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 191वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है;

iv. समिति के 61वें मूल प्रतिवेदन (षष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 36वां कार्रवाई प्रतिवेदन (सप्तम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि परिवहन विभाग से सम्बन्धित है;

27.3.2018/1220/av/yk/2

v. समिति के 154वें मूल प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 56वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

vi. समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 61वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि उद्योग विभाग से सम्बन्धित है;

vii. समिति के 33वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 70वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है; और

viii. समिति के 272वें मूल प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 90वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है ।

27.3.2018/1220/av/yk/3

अध्यक्ष : अब श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2017-18) समिति का द्वितीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या 3:1 व 3:2 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

श्री नरेन्द्र बरागटा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2017-18) का द्वितीय मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के ऑडिट पैरा संख्या 3:1 व 3:2 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं।

27.3.2018/1220/av/yk/4

<u>वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान</u>

अध्यक्ष : अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों का प्रस्तुतीकरण, चर्चा एवं मतदान जारी रहेगा।

अब वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान होगा। मैं मांग संख्या 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई को चर्चा एवं मतदान हेतु लेता हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त आर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई धनराशियां क्रमश :

25,30,55,93,000/- रुपये (राजस्व) 5,59,74,27,000/- रुपये (पूंजी) सम्बंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

इस मांग पर श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्री अनिरुद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, सर्वश्री हर्षवर्धन चौहान, राम लाल ठाकुर, राजेन्द्र राणा, नन्द लाल, डॉ (कर्नल) धनी राम शांडिल, श्री राकेश सिंघा, श्री पवन काजल, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायजादा की ओर से सात कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। क्या आप इन्हें प्रस्तुत करना चाहते हैं या इन्हें प्रस्तुत हुआ समझूं?

सदस्यगण : प्रस्तुत हुआ समझा जाए।

अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गये जो इस प्रकार से हैं :-

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्रीमती आशा कुमारी,

27.3.2018/1220/av/yk/5

4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री जगत सिंह नेगी,
6. श्री राम लाल ठाकुर,
7. श्री राजेन्द्र राणा,
8. श्री नन्द लाल,
9. डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल,
10. श्री राकेश सिंघा,
11. श्री पवन कुमार काजल,
12. श्री विक्रमादित्य सिंह,
13. श्री आशीष बुटेल,

14. श्री सतपाल सिंह रायजादा।

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

2. सांकेतिक कटौती

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
चसिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाईछ
की राशि में सौ रूपये की कमी की जाए।

श्री हर्षवर्धन चौहान:

1. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के मण्डल पांवटा के अन्तर्गत विभिन्न उठाऊ सिंचाई योजना व उठाऊ पेय जल योजना को पूर्ण न कर पाने में सरकार की असफलता ।
2. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत शिलाई के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में उठाऊ सिंचाई योजना व उठाऊ पेय जल योजना की पंपिंग मशीनरी को न बदल पाने में सरकार की असफलता।
3. मांग संख्या-13 के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र शिलाई में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पम्प ऑपरेटरों की पदपूर्ति न कर पाने में सरकार की असफलता ।

27.3.2018/1220/av/yk/6

मांग तथा कटौती प्रस्ताव विचारार्थ उपलब्ध है। अब मैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को (---व्यवधान---) आपका (श्री राजेन्द्र राणा) नम्बर आयेगा। आपका नम्बर इसमें आने वाला है और आपका नाम उच्चारण किया जायेगा।

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था और आज यह स्टोरी 'द टिब्यून' में भी छपी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने लॉ-ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट में राज्य के एडवोकेट जनरल के विरुद्ध सांसद अनुराग ठाकुर और हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसएशन को डिफैंड करने के लिए नियुक्त किया है। पिछली सरकार में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसिएशन के विरुद्ध केस रजिस्टर हुआ था और उसकी वजह यह थी कि सरकारी जमीन हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसिएशन के नाम (---व्यवधान--)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इस विषय से सम्बंधित नोटिस दे दीजिए। हम किसी नोटिस के अंतर्गत आपको अलाउ कर देंगे।

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं आपके ध्यान में अपनी बात ला रहा हूं। यह एक जरूरी विषय है और मुझे केवल एक मिनट में अपनी बात रखनी है। आज ट्रिब्यून में यह स्टोरी छपी है कि सरकार का लॉ-ऑफिसर अनुराग ठाकुर की ओर से राज्य के एडवोकेट जनरल के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहा है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश और इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में यह पहली दफ़ा हो रहा है कि सरकार को डिफैंड करने के लिए सरकार का ही लॉ-ऑफिसर (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : मैं मांग संख्या : 13 को शुरू कर रहा हूं।
अब माननीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी कटौती प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेंगे। (व्यवधान-) माननीय सदस्य नोटिस दे दें और इस पर पूरी चर्चा हो सकती है। क्योंकि Government should be ready to reply. (---व्यवधान---)

27.3.2018/1220/av/yk/7

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कमैंट किए हैं कि आपको हमें यह बताना पड़ेगा कि इस प्रकार के केसिज में कैबिनेट का निर्णय अप्लाई होता है। (---व्यवधान---) यह केस इसलिए बना था कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट ऐसोसिएशन को सरकारी जमीन दी गई है। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप नोटिस दीजिए। उस नोटिस के अंतर्गत बात हो सकती है। Please, there is no Zero Hour. माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, आप बोलिए।

27.03.2018/1225/TCV/YK-1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, श्री राजेन्द्र राणा जी अपनी बात रख रहे थे। वैसे यह बहुत अनप्रेसिडैटिड बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि एडवोकेट जनरल के सामने अडिशनल एडवोकेट जनरल उसी सरकार का अपीयर हो रहा है, जिसको आप पे कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि एडवोकेट जनरल के सामने अडिशनल एडवोकेट जनरल, जो दोनों एक ही जगह से हैं, जिनको आपने अप्वाइंट किया है, वे एक दूसरे के आमने-सामने अपीयर हो रहे हों । ---(व्यवधान)--- कोर्ट ने कहा है कि क्या कैबिनेट का फैसला उन पर अप्लाई होता है, जहां चार्जिज़ फ्रेम हो रखे हैं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुकेश जी, प्लीज आप विषय पर आएं। मुकेश जी प्लीज़ विषय पर । ---(व्यवधान)---

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 13 'सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई' पर मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जो कि 7वीं दफ़ा इस सदन में पहुंचे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आजकल बहुत लम्बे-लम्बे जवाब देते हैं। ---(व्यवधान)---

अध्यक्षः आज मांग संख्या पर मूवर को 10 मिनट और उसके बाद प्रत्येक माननीय सदस्य को 5 मिनट से अधिक का समय नहीं दिया जाएगा। आपका ही समय है, यदि अलग-अलग विषय चलते जाएंगे, तो आपकी ही ज्यादा मांग कवर हो पाएगी।

27.03.2018/1225/TCV/YK-2

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, 'सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई' एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन आपने समय निर्धारित कर दिया है, तो मैं सीधे मसले को लेकर मंत्री जी के पास जा रहा हूं। आज रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग पर भी चर्चा होनी है और आपने 4750 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट भी बनाकर हाल ही में मंजूरी हेतू भेजा है। माननीय मंत्री जी आप सदन में यह स्पष्ट कर दें कि क्या यह 4750 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट मंजूर भी होगा या ये बड़े-बड़े दावे ही है? आपकी सरकार बनी और 100 दिन के अंदर आपने एक प्रोजैक्ट दिल्ली को भेज दिया है। लेकिन क्या फंडिंग के लिए इसे वर्ल्ड बैंक को भेज रहे हैं, फंडिंग की क्या गुंजाईश है और किस स्तर पर आपकी क्या बात हुई है?

दूसरा मसला हमारे पास 'ब्रिक्स' का है, हमारे समय में ये मसला उठा और आपने ये भी 3257 करोड़ रुपये अपने खाते में लिख दिए। बजट बुक में भी 36 नम्बर पेज़ पर आपने अपना पूरा गुणगान कर लिया है। ये जो 31 डी0पी0आर्ज़ की बात आपने की है, ये सारी हमारे समय में हो गई थी। आप हमें स्पष्ट बता दें कि 3257 करोड़ में से जो 650-700 करोड़ रुपये की पहली किस्त आने वाली है, ये कब तक आ रही है? क्या इसके बारे में कोई कमिट्मेंट हुई है?

27-03-2018/1230/NS/AG/1

श्री मुकेश अग्निहोत्री ------जारी

अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आप यहां पर ए0आई0बी0पी0 स्कीमों की बात कर रहे हैं और "प्रधानमंत्री खेत योजना" के अनुसार हर खेत को पानी मिलेगा। मैं जानना

चाहता हूं कि हर खेत को पानी कहां से मिलेगा? क्योंकि ए0आई0बी0पी0 में हिमाचल प्रदेश की कोई स्कीम नहीं है। इसमें हिमाचल प्रदेश को कोई स्कीम नहीं मिली है। प्रधानमंत्री जी ने 99 स्कीमें जो शोर्टलिस्ट की हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश की कोई स्कीम नहीं है। आप भी परमार साहब की तरह कहेंगे कि पिछली सरकार, यह आपका तकिया कलाम हो गया है। लेकिन माननीय मंत्री जी ए0आई0बी0पी0 में क्या हिमाचल की कोई भी स्कीम डिज़र्व नहीं करती है और क्यों नहीं आ रही है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, हर खेत को पानी देने की बात है। इसमें पूरे हिन्दुस्तान के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। आप बताईये कि प्रधानमंत्री हर खेत को पानी देने की बात कर रहे हैं और इसके लिए इतनी ही राशि रख रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी तो इसमें और भी आगे चले गये और कहा कि हम किसान की आय दोगुनी कर देंगे। आप किसान की आय दोगुनी कैसे करेंगे? यहां पर उसको पानी देने के लिए तो पैसा नहीं है। ए0आई0बी0पी0 में कोई स्कीम नहीं आ रही है और खेत के लिए लगभग 300 करोड़ रुपये की राशि की सीलिंग लग गई है और यह पूरे देश में लगी है। अध्यक्ष महोदय, कुछ मसले ऐसे हैं, जो आपने इसमें मैन्शन किये हैं। आपने कहा कि आप कमांद एरिया के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेंगे। पहले वर्ष में लगभग 130 करोड़ रुपये बज़ट का प्रावधान होगा। यह आपका पैसा नहीं है। अगर दिल्ली से यह पैसा नहीं आया तो आपने जो बज़ट प्रपोज़ किया है, यह तो गिर जायेगा। आपने अपने बज़ट में किस ढंग से रिफलैक्शन किया है? आपने "लघु सिंचाई योजना" के लिए लगभग 277 करोड़ रुपये की दर्शायी है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यह आपके अपने बज़ट की स्कीम है या दिल्ली से आ रही है? जब उनके पास टोटेलिटी में पैसा नहीं है तो आपने कहां से लिख दिया कि आप 277 करोड़ रुपये की राशि लघु सिंचाई योजना में लगायेंगे? आपने कहा है कि मध्य सिंचाई योजना के लिए लगभग 85 करोड़ रुपये की राशि फिना सिंह और नदौन को लगायेंगे। आप बतायें कि क्या आपने इस राशि का अपने बज़ट में प्रावधान किया है या यह भी दिल्ली से आयेगा? एक प्रोजेक्ट लगभग 150 करोड़ रुपये का था और इस प्रोजेक्ट की आज की कोस्ट कहां पहुंच गई है? ऐसे ही नदौन की वाटर सप्लाई स्कीम कितने की थी और आज इसकी लागत कहां पहुंच गई है?

27-03-2018/1230/NS/AG/2

आप अभी भी 85 करोड़ की ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपने दो-तीन योजनायें और लिख दी है। "जल से कृषि को बल" के तहत लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। आप मुझे बताईये कि यह 250 करोड़ रुपये की राशि कहां से आयेगी? आप इसके लिए कोई सोर्स तो बतायें? आपने आगे लिखा है कि "FLow Irrigation Scheme" के अन्तर्गत लगभग 150 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यह पैसा कहां से आयेगा? फिर आपने "सौर सिंचाई योजना" के बारे में लिख दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूरे हिन्दुस्तान में कहीं पर "सौर सिंचाई योजना" है, आपने पता नहीं कहां से उठाई है? आपने कहा है कि आप 5 सालों में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेंगे और प्रति वर्ष लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि व्यय करेंगे। आपने जो यह उम्मीदों को महल यहां पर खड़ा कर दिया है। इसके लिए दिल्ली से पैसा नहीं आयेगा तथा आपने इसकी प्रोजैक्शन बड़े हायर लेवल पर दे दी है। मैं यहां पर स्वां चैनलाइजेशन की बात करना चाहता हूं। आज इस पर प्रश्न भी लगा था। मंत्री जी आप अनैतिक काम मत किया करें। हमने सवाल लगाया और आपने दो ओर सदस्यों को इसमें ऐड करवा दिया। प्रश्न का एक भी शब्द नहीं बदला गया है। (***) करनी हो तो थोड़ी इन्टैलीजेंटली करनी चाहिए।

अध्यक्षः (***) शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः यह काम अनैतिक है। अध्यक्ष महोदय, यह पूरी तरह अनैतिक है और यहां पर मंत्री लोग फिक्सिंग कर रहे हैं कि हमने सवाल 'क','ख', 'ग' और 'घ' दिया है। अध्यक्ष महोदय, आप इनको याद करवायें कि क्या मुकेश अग्निहोत्री के लिखे सवाल में एक अक्षर का भी बदलाव है? आपने सिर्फ यह किया कि दो विधायक ओर ऐड करवा दिये और मुकेश अग्निहोत्री को नम्बर-2 पर डाल दिया। मंत्री जी आप यह क्या कर रहे हैं? यहां पर किस ढंग से फिक्सिंग हो रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह विधान सभा की गरिमा का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय, आपने सारे विधायकों के लिए नाबार्ड में लगभग 90 करोड़ रुपये की सीलिंग लगवा दी है। पहले यह सिलिंग लगभग 70 या 80 करोड़ की लगती थी। हम बार-बार कह रहे हैं कि यह सीलिंग वर्तमान सदन की सीलिंग होनी चाहिए।

—————————————————————————————————

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

27-03-2018/1230/NS/AG/3

इस बार चुन करके जो विधायक आये हैं, आप उनकी सीलिंग 90 करोड़ की करवाओ। हम लोग जो आपको विधायक प्राथमिकता की स्कीमें दे रहे हैं,वे स्कीमें तो आएंगी नहीं। आप कहेंगे कि कोई 70 करोड़ पर और कोई 80 करोड़ और कोई 90 करोड़ पर बैठा है। तो नये एम.एल.ए. क्या करेंगे? उनके लिए सीलिंग हटा करके इन 5 सालों की बनाएं ताकि जो एम.एल.एज. प्राथमिकताएं दे रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं ली जाएं।

27.03.2018/1235/RKS/AG-1

श्री मुकेश अग्निहोत्री.. जारी

मैं माननीय मंत्री जी को DPRs के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। इस सदन में सत्ता पक्ष के भी 23 विधायक नये चुनकर आए हैं। इन विधायकों ने भी DPRs बनवानी है परन्तु DPRs बहुत देर से बन रही है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी भी विधायक प्राथमिकताएं हैं, उन्हें आप आउटसोर्स करें ताकि समयावधि में यह सारी DPRs बन जाएं। प्रथम वर्ष में ही ये DPRs फंडिंग के लिए लग जानी चाहिए अन्यथा इन स्कीमों को बनने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से बहुत हैरान हूं। माननीय मंत्री जी ने एक्सिअन, होम डिवीजन में ही लगा दिए हैं। आपने एस.ई., चीफ इंजीनियर अपने ही सर्कल में लगा दिए। यह व्यवस्था का सवाल है। आप किस ढंग से एस. ई., एक्सिअन को उन्हीं के घर में लगा देंगे? आप चपरासी और लिपिक को तो लगा नहीं सकते। आपने अधिकतर अधिकारी ऐसे ही लगा दिए हैं। आपने अधिकतर अधिकारी होम डिवीजन, होम सर्कल में लगा दिए हैं। क्या यह बात आपके संज्ञान में है या ऊपर से ही कुछ हो रहा है?

अध्यक्ष महोदय, आपने जल संग्रहण के लिए शाम को एक कार्यक्रम रखा है। पानी की एक-एक बूंद हमारे लिए कीमती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो 4750 करोड़ रुपये की प्रोजैक्शन दी जा रही है, इसको आप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में किस ढंग से डिवाइड करेंगे? माननीय मंत्री जी ऐसा मत करना कि आप सब कुछ धर्मपुर ही ले जाएं। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में इस समय सबसे बड़ी समस्या कर्मचारियों की है। यह बात ठीक है कि जब आप जवाब देंगे तो आप यह कहेंगे कि यह काम आपके समय से होता आ रहा है। लेकिन यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इन स्कीमों में इम्पलॉईज रखना बहुत जरूरी है। जब स्कीम की मरम्मत की जाती है तो स्कीम जल जाती है। क्योंकि एक आदमी के पास 3-3, 4-4 स्कीम्ज हैं। बजट में आपने नई भर्ती का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। आप कैसे लोगों को भर्ती करेंगे? आउटसोर्स में जितने कर्मचारी लगे हैं उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप उनको कैसे आगे

27.03.2018/1235/RKS/AG-2

ले जाएंगे। स्वां तटीयकरण की जो स्कीम बंद हुई, आज हिन्दुस्तान में कोई ऐसा प्रोजैक्ट नहीं है जोकि आधे-अधूरे में बंद हुआ हो। इस चैनेलाइजेशन में 450 करोड़ रुपये खर्च किया जा चुका है और उसके बाद इसके लिए कोई फंडिंग नहीं हुई। वित्त विभाग ने भी इसमें बंगलिंग की है। इस प्रोजैक्ट के लिए 290 करोड़ रुपये नाबार्ड से लिया गया था। लगभग 210 करोड़ रुपये इस प्रोजैक्ट के लिए दिया गया और बाकी पैसा वित्त विभाग के पास है। आप वह पैसा नहीं दे रहे हैं। इसके लिए पहले 55 करोड़ रुपये की किस्त दिल्ली से आई, वह पैसा भी वित्त विभाग ने अपने पास रख दिया। इस बार आपने 33 करोड़ रुपये का उल्लेख किया है परन्तु मैं दावे के साथ कहता हूं कि वित्त विभाग फिर इस पैसे को नहीं देगा। जो पैसा वित्त विभाग अपने पास रखता जा रहा है, किसी प्रोजैक्ट का पैसा आप किसी और काम मे लगा रहे हैं, इसकी पूरी तरह जांच होनी चाहिए। दिल्ली वाले तभी पैसा देंगे जब आप पिछले पैसे को स्कीम्ज में लगाएंगे। जो पैसा प्रस्तावित है यदि वह खर्च नहीं होगा तो दिल्ली से पैसा नहीं आएगा। स्वां प्रोजैक्ट को लटकाने में वित्त विभाग का बहुत

बड़ा रोल है। वित्त विभाग इसकी फंडिंग को लटका रहा है। इसी तरह रोहड़ू चैनेलाइजेशन और अन्य जगह के मामले भी हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये सारे तटीयकरण के मामले फंसे हुए हैं। इसके के लिए दिल्ली से कैसे पैसा लाना है? यह कहा जा रहा था कि इन प्रोजैक्टों के लिए दिल्ली में 8 हजार करोड़ रुपये की राशि है। उसमें से अपना हिस्सा कैसे लाना है, इस बात पर विचार किया जाए। (..घंटी..) अध्यक्ष महोदय, आप जल्दी में हैं।

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य, मैं जल्दी में नहीं हूं लेकिन आपका समय ज्यादा हो रहा है।

27.03.2018/1235/RKS/AG-3

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 2572 करोड़ रुपये की प्रोजैक्शन दी है। उसमें एक ऐसा महल खड़ा कर दिया गया है लेकिन वह पैसा इनके पास है ही नहीं। वह पैसा अभी बाहर से आना है। दो बड़े प्रोजैक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग और BRICS के दिखाए जा रहे हैं। अब शंघाई चाइना से यह पैसा आना है। चाइना से कुल मिलाकर 3257 करोड़ रुपये आप कब लेने जा रहे हैं और कैसे-कैसे ला रहे हैं? यह सब्जबाग हमें न दिखाए जाएं। हमारा कहना तो यह है कि पाइपें खरीद लो और इन पाइपों को जनता तक पहुंचाया जाए। अगर आप इन पाइपों को मार्च, अप्रैल तक खरीद कर जनता तक पहुंचाएंगे तब यह ठीक हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए बस यही बातें यहां पर रखना चाहता था। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी। माननीय सदस्या, जिस समय यह नाम पढ़े गए, उस समय आप उपस्थित नहीं थीं परन्तु आपको इस चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया जाएगा।

27.03.2018/1240/बी0एस0/डी0सी0-1

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः -13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई, इसके कटौती प्रस्ताव पर आपने बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद। ऐसे तो माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी ने टोटैलिटी की पिक्चर रख दी है, इसलिए दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जो आंकड़े आपने पेश किए हैं उसकी फंडिग कहां से आएगी? जैसा मुकेश जी ने कहा कि आपके सपनो का महल कैसे बनेगा? उसका जवाब मंत्री जी देंगे। मंत्री जी, बड़े पुराने मंत्री हैं। आई.पी.एच. का विभाग इनके पास पहले भी रहा है। बहुत जिम्मेवार मंत्री हैं, अपने दल के सबसे वरिष्ठ विधायक भी हैं और इनसे हमें उम्मीदें भी हैं कि ये विभाग के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन आज चम्बा सर्कल के बारे में आदरणीय बिक्रम जरयाल जी का एक प्रश्न भी लगा हुआ था। मैं उसका उत्तर देख रही थी । मंत्री जी, आश्चर्यजनक बात है, आदरणीय मुकेश जी तो कह रहे हैं कि आपने होम डिविजन में अधिशाषी अभियंता लगा दिया। लेकिन आपने डलहौजी में तो उससे भी ज्यादा कमाल कर दिया, एक डिविजन में दो-दो अधिशाषी अभियंता लगा दिए। मेरा सुझाव रहेगा कि उनको क्षेत्र बांट दीजिए या कार्य बांट दीजिए। आई.पी.एच. का कार्य डलहौजी क्षेत्र में ठप्प पड़ चुका है। दोनों में से यही नहीं पता की अधिशाषी अभियंता है कौन? मैं आपको बता रही हूं कि एक ही डिविजन में दो अधिशाषी अभियंता है और दोनों ही कार्यालय में बैठ रहे हैं। कौन किसी सुने, स्टाफ किसकी सुने, काम कौन करे? मुझे इससे मतलब नहीं कि कौन रहे और कौन नहीं। अगर एक को स्टे दिया है तो दूसरे को भेज दो। अगर दूसरे को लगाना है तो पहले वाले को भेज दो। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि आप किसको रखते हैं और किसको हटाते हैं। मुझे व्यवस्था से दिलचस्पी है।

मुख्य मंत्रीः जो आपको उचित लगता है।

श्रीमती आशा कुमारीः मुझे तो आदरणीय महेन्द्र सिंह जी उचित लगते हैं।

अध्यक्षः तो आप श्री महेन्द्र सिंह जी को अधिशाषी अभियंता लगवाना चाह रहे हैं?

27.03.2018/1240/बी0एस0/डी0सी0-2

श्रीमती आशा कुमारीः महेन्द्र सिंह जी को अधिशाषी अभियंता मैं नहीं बोलना चाहती। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं अपने क्षेत्र की ही बात करना चाहती हूं। एक तो हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है। वैसे ही दुर्भाग्य की बात है कि इस वर्ष वर्षा भी कम हुई है। बर्फ भी कम पड़ी, इसलिए सूखे के बहुत ज्यादा चांसिज हैं और अभी से पानी की किल्लत आनी शुरू हो गई है। हमरी एक बहुत महत्वाकांक्षी स्कीम है जो नाबार्ड के अधीन स्वीकृत हुई है। इस स्कीम का नाम है 'Water Supply Scheme for drought affected areas of Deur, Manjir and Saluni' और यह नाबार्ड के अन्दर पहले ही एप्रूवड है। इसमें बजट इस वजह से सिरेंडर हो गया क्योंकि इसको BRICS में ले लिया। मगर अब सूचना दी गई है कि जब सरकार बदली तो उसको BRICS से निकाल दिया गया। अब न तो वह नाबार्ड की फडिंग उसमें काँटीन्यू हुई, आपने एक करोड़ रुपया इस वर्ष रखा है, लेकिन 35 करोड़ रुपये की यह स्कीम है। BRICS में आप भेज रहे थे, आप देखिए जहां से फंड उपलब्ध हो वहां इसे डाल दें । हमें स्कीम से मतलब है। वह एरिया बहुत सूखा है। वहां कोई भी पानी का स्त्रोत नहीं है। Flow Irrigation scheme, वहां पीछे से ही स्कीम बनाई जा सकती थी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक बनीखेत के लिए स्कीम बन रही है। इका शिलान्यास माननीय पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने किया था। उसका टेंडर भी हो गया है परंतु अभी काम शुरू नहीं हुआ। बनीखेत की जो जरूरत है वह 6 लाख गैलन की है इस वक्त वहां जो उपलब्ध है वह 2 लाख गैलन हैं। इसका कारण पानी के स्त्रोतों में पानी की कमी है। बर्फ पड़ी नहीं है। अगर यह स्कीम जल्दी नहीं बनेगी तो बनीखेत में सूखे की स्थिति बन जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि जो-जो सूखा पड़ने वाले एरियाज हैं आप उनकी पहचान करके वहां चाहे टैंकर की पानी की व्यवस्था कर दीजिए या पानी की कैसे व्यवस्था करनी है? यह पूर्व में ही निर्धारित कर लीजिए। किल्लत की स्थिति ही उत्पन्न न होने दें। क्योंकि यह मालूम है कि कहां पानी की कमी होती है। कहां ऐसे स्त्रोत हैं जिनका संवर्धन हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने फिल्ड स्टाफ को कहेंगे तो इस समस्या का हल ढूंढा जा सकता

है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, माननीय जरयाल साहब के उत्तर में ही यह बात आई कि सलूनी डिविजन और डलहौजी डिविजन में फिटर्स की बहुत कमी है। एक तो हमारा एरिया पहाड़ी एरिया तो है ही परंतु स्नोबाउंड एरिया है और स्नोबाउंड एरिया में जब लाइन टूटती है और एक ही फिटर 10-10 स्कीमों को देख रहा है।

27.3.2018/1245/DT/DC/-1

श्रीमती आशा कुमारी.... जारी

किसी भी स्कीम की लम्बाई 25 किलोमीटर से कम नहीं है। इसलिए उसमें फिटर की भी क्या गलती मानें। He is also a human being. अध्यक्ष महोदय, डलहौजी की जो सीवरेज़ स्कीम है, डलहौजी शहर की सीरवेज़ स्कीम के लिए जो ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, उसके लिए जगह का चयन हो चुका है। शायद टैंडर भी हो चुका है, उसको एक्सपीडाइट करवा दें। पाईप्स उसकी खरीद के रखी हुई थीं, क्योंकि उसका काम नहीं लग सका था, वह कहीं को शिफ्ट हो गई है। सीवरेज़ और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए जो भी पाईप्स की जरूरत है उसको आप पूरा करवा दे। इसके इलाव डलहौजी की जो वाटर सप्लाई की मेन स्कीम है, वह रावी से लिफ्ट स्कीम है। उसमें पंप्स जो लगे हुए है, वह पंप्स चलते नहीं है पता नहीं किस कारण से विभाग ने यह फैसला लिया और इन स्कीमों को चलाने के लिए प्राईवेट ओपरेटर्ज़ को दे दिया । मेरा आपसे निवेदन है, मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं, क्यों किया गया और किसने किया और क्या किया गया? लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप इसको ठीक करें जो पंप्स है, यहां चोरी नहीं हुए है, रामलाल जी की तरह। जबकि राम लाल जी के इलाके में तो पंप्स चोरी हो गए हैं। पंप्स है लेकिन आपका विभाग बिजली विभाग को पैमेंट्स नहीं करता है। इसलिए समय पर पैमेंट्स न होने की वजह से आपका और बिजली विभाग का यह डिसप्यूट रहता है और पंप्स के लिए बिजली उपलब्ध नहीं होती है। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि Dalhousie Water Supply Scheme and any other schemes जो कि पंप्स के द्वारा या बिजली के द्वारा

चल रही हैं उनको आप सुचारू रूप से चलवायें। आपका बहुत-बहुत धन्यावद । Thank you.

27.3.2018/1245/DT/DC/-2

अध्यक्षः श्री अनिरूद्व सिंह जी ।

श्री अनिरूद्व सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्याः 13 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं आपका धन्यावद भी करना चाहूंगा और साथ ही आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में कुछ चीज़ें भी लाना चाहूंगा । पानी जो है, हर विधान सभा क्षेत्र में, मैं पूरे हिमाचल की बात करूंगा एक ड्राउट के हालात पैदा हो रहे है और हर विधायक इस साल इस बात को फेस करने जा रहा है । क्योकि मैं कोई टिपप्णी नहीं करना चाहूंगा कि क्या कारण है। मंत्री जी आप बहुत सीनियर मंत्री है और पहले भी आपके पास ये विभाग रह चुका है। लेकिन आई0पी0एच0 विभाग लोअर लेवल पर शुन्य होता जा रहा है। इस विभाग के जो फिटर है, सभी यह दिक्कतें फेस करते होगें। उनका केवलमात्र ताश खेलने का काम हैं और कोई काम नहीं है। उनके उपर कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती है। एक तो इनके उपर जिम्मेदारी फिक्स करें ताकि लोगों को जो कुछ थोड़ा-बहुत पानी हैं, उनको पानी समय पर मुहैया हो पाएं। पानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है, वह एक व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। कुछ Automated Pump Houses अभी कुछ पिछले वर्षों में किये हैं, क्योंकि इनको अपने हिसाब से फिटर्ज़ चलाते हैं। मैं आप से गुज़ारिश करूंगा कि सभी टाइम फिक्स करके सभी पंप हाऊसिज़ को धीर-धीरे चरणबद्ध तरीके से Automated Pump House बनाए जाएं ताकि उसमें किसी की मानमानी न चले। ये अपने आप टाईम से चले और टाईम से बन्द हो। ऐसा न हो कि कहीं दो पंप लगे हैं, एक पंप में ज़्यादा पानी चल रहा है और दूसरे पंप में कम पानी चले। कुछ पंप्स जो हैं, मैं समझता हूं कि वे इतने पुराने हो चुके हैं कि वे आधे डिज़ाईन के हैं, दो इंच में उसमें लास्ट तक एक इंच पानी भी नहीं पहुंचता हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र कसुम्पटी की बात करूंगा, कई हमारे एसे पंप्स हैं

जहां अढ़ाई इंच के डाया के हिसाब से पंप्स लगे हैं अंत में उनमें ऊपर तक एक इंच पानी भी नहीं पहुंचता है। इसके लिए अगर हम नये पंप्स मुहैया करायें तो लोगों को सहुलियत रहेगी। एक बड़ी अहम बात है क्योंकि हम लोग एम0एल0ए0 प्रायोरिटिज़ में एल0आई0एस0 और एल0डब्लयू0एस0एस0 डालते हैं, परन्तु उसमें अब एल0आई0एस0 कमेटिज़ बनाने का प्रावधान हैं। एम0एल0ए0 प्रायोरिटिज़ में यह मांग रहती है कि पहले

27.3.2018/1245/DT/DC/-3

कृषि विकास समूह बनाये जाये। तभी काम शुरू होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसके नार्मज़ बदले जायें। हमें 2 साल के बाद पता चलता है कि स्कीम इनफिजिबल है या पानी खराब है। इसके नॉर्मज़ बदले जाये। विधायक विभागों को लिखकर दें कि हमारी फ्लां स्कीम है, विभाग पहले ही उस वॉटर को टैस्ट करवायें किवह पीने के लायक है या नहीं है और इस बारे में विधायकों को भी बतायें। इसके अलावा इसका सर्वे भी साथ-साथ करें। उसमें एन0ओ0सीज0 ले, फिर विधायक उसको अपनी एम0एल0ए0 प्रायोरिटीज़ में डालें ताकि उस काम में तेजी लाई जा सके।

27.03.2018/1250/SLS-HK-1

श्री अनिरूद्ध सिंह ...जारी

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करूंगा। मंत्री जी, पिछले 5 सालों में हमारी एक भी डी.पी.आर. नहीं बनी है।...(व्यवधान)... मैं दोष नहीं दे रहा हूं। आप अब खुद महसूस करेंगे। ...(व्यवधान)...आपकी भी नहीं बनी होंगी; आप मुझे अपनी बता दें। ...(व्यवधान)...अगले 5 साल भी नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें नार्मज बदलने की ज़रूरत है। इसमें कागज़ी कार्रवाई ही इसमें इतनी ज्यादा है कि विभाग उसको पूरा ही नहीं कर पा रहा है। कभी वह कहते हैं कि हमारे पास एन.ओ.सी. ही नहीं है या इसका सर्वे नहीं है या सर्वे करने वाले लोग ही नहीं हैं। इसलिए इसमें नार्मज बदलने की ज़रूरत है ताकि हम

काम को स्पीड-अप कर सकें।...(व्यवधान)... मैं बोल लूं, जब आपकी बारी आएगी तो आप बोल लेना। ...(व्यवधान)... मैं हकीकत की बात कर रहा हूं जिसे हम सब लोग फेस कर रहे हैं; यह कोई टिप्पणी करने वाली बात नहीं है।

मंत्री जी, एक हमारी पुजारली डमेची स्कीम है जिसकी डी.पी.आर. लगभग तैयार है, इसलिए उसको नाबार्ड में भेजने की बात है। आपसे गुज़ारिश करूंगा कि विभाग से कह कर इसको भिजवाएं क्योंकि इसमें हैड ऑफिस से ही बार-बार ऑब्जैक्शन लग रहे हैं। इसके एन.ओ.सीज. पूरे हैं, इसलिए इसको कंपलीट करवा कर इंजीनियर-इन-चीफ ऑफिस से प्लानिंग में भिजवाएं ताकि इसको नाबार्ड में फौलो-अप किया जा सके। यह एल.आई.एस. स्कीम है।

एक और सुझाव देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे फिल्टर टैंक्स हैं उनमें से कुछेक ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी तक ढक्कन नहीं लगे हैं। मैंने प्रश्न लगाया था और मुझे आश्वासन भी मिला है। क्योंकि यह मैंडेटरी है इसलिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन फिल्टर टैंक्स के ऊपर जल्दी से ढक्कन लगवाए जाएं।

27.03.2018/1250/SLS-HK-2

मैं ट्रांसफार्मज की भी बात करना चाहूंगा। मैं यह बात अपने पिछले अनुभव से बता रहा हूं कि आई पी.एच. विभाग बिजली बोर्ड के पास ट्रांसफार्मर के लिए पैसे जमा करवाता है परंतु एक-एक साल तक बोर्ड ट्रांसफार्मर नहीं लगाता। आप इस बात को टेक अप करें क्योंकि जमा करवाई गई यह आपकी रकम है जिसके ऊपर ब्याज भी लगता है। बिजली बोर्ड पैसे अपने पास रखकर उसका ब्याज खाता है जो कि अनअकाऊंटेबल है। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में शीघ्र मीटिंग लें क्योंकि हमारी भी ऐसी कई स्कीम्ज हैं जिनके ट्रांसफार्मर के पैसे ऑलरेडी जमा हो चुके हैं।

विभाग ट्रांसफार्मर के लिए एक बार पैसे जमा करवाता है और बिजली बोर्ड ट्रांसफार्मर लगा देता है। फिर अगर कोई ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, उसका क्या प्रावधान है? हमने धरेच में एक ट्रांसफार्मर लगवाया और वह चोरी हो गया। अब बिजली बोर्ड वाले बोलते हैं कि हम तो दोबारा नहीं लगाएंगे और अगर लगवाना है तो आप दोबारा पैसे जमा करवाओ। आई.पी.एच. बोलता है कि हमारे पास तो ट्रांसफार्मर के पैसे केवल एक बार ही आते हैं जो हमने जमा करवा दिए हैं। ...(व्यवधान)... सर, यह आवश्यक है क्योंकि ट्रांसफार्मर कहीं भी चोरी हो सकता है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस मामले में देखें कि ट्रांसफार्मर दोबारा बिजली बोर्ड ही लगाएगा या आई.पी.एच. इसके लिए दोबारा पैसे जमा करवाएगा।

मैं पाईप्स के बारे में बात करूंगा। हमारे डिविजन में कुछ पाईप्स आ चुकी हैं। पहले थोड़ी जी.एस.टी. की दिक्कत थी जो अब दूर हुई है लेकिन अभी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। क्योंकि हर डिविजन में यह दिक्कत आ रही है, इसलिए इसको देखने की आवश्यकता है। यह समस्या हर डिविजन में है। कभी पूछें तो कहते हैं कि हमारे पास पाईप्स ही नहीं हैं।

एक बात और है। जब भी कोई लाईनमैन किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में, किसी भी जगह, रिपेयर के लिए जाता है; मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, वह लोगों से कहता है कि आप पाईप जोड़ने के लिए टी या एलबो ले आओ और लोग पैसे इकट्ठे करके

27.03.2018/1250/SLS-HK-3

उसको सामान लाकर देते हैं। इस तरह कई बार सब-स्टैंडर्ड सामान आ जाता है। इसके ऊपर भी चैक रखा जाए कि लाईंजमैन लोगों से सामान न मांगे। अभी एम.सी. शिमला शहर को 24 घंटे पानी देने का दावा कर रही है जिसकी कुछेक डी.पी.आर. भी बन चुकी हैं। यह वर्ल्ड बैंक का प्रोजैक्ट है इसलिए इसको आप टाईम से फौलो अप करवाएं। ऐसा न हो कि वह कागज़ों में ही रह जाए। यह बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। मुझे पता चला है कि अभी वर्ल्ड बैंक ने विभाग को एक नया निगम बनाने के लिए कहा है, तभी वह डी.पी.आर. की

मंजूरी देंगे। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग म्यूनिसिपल कार्पोरेशन है, उसमें ऑडिट आदि को लेकर बहुत हौच-पौच है। उसमें जो स्कीमों के लिए पैसे आते हैं वह वेतन देने के लिए ही निकाले जा रहे हैं।

27/03/2018/1255/RG/HK/1
श्री अनिरूद्ध सिंह-----जारी

तो इसको आप प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। क्योंकि इस साल शिमला शहर और इसके आस-पास पीने-के-पानी के लिए बहुत हा-हाकार मचने वाला है और लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। यह मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैंने एक प्रश्न यहां लगाया था, लेकिन वह लग नहीं सका। मैंने आपको लिखित रूप में भी दिया है ---(घण्टी)----कि हमारे यहां से ठियोग से जो चार पंचायतें कटकर कसुम्पटी में आई थीं, उनका डिवीजन मतियाणा में शिफ्ट कर दिया गया था और मतियाणा बहुत दूर पड़ता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वह शिमला डिवीजन नंबर-1 में शीघ्रातिशीघ्र शिफ्ट किया जाए। अभी हमें यह समस्या आ रही है कि ठियोग एक बहुत बड़ा चुनाव क्षेत्र है और हमारी केवल चार पंचायतें उस डिवीजन में हैं। उनको नजरन्दाज़ किया जाता है। क्योंकि ठियोग चौपाल तक है। अब अधीक्षण अभियन्ता तो एक ही हैं और वह पूरा चुनाव क्षेत्र घूमने में भी असमर्थ होते हैं। एक हफ्ते के अन्दर भी पूरा चुनाव क्षेत्र नहीं घूम सकते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको जल्द-से-जल्द से किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी स्कीम स्वीकृत होती है, तो इसके लिए लोक निर्माण विभाग के पास पैसे जमा होने हैं। कई स्कीम्ज हमारी ऐसी हैं जैसे 40,00,000/-रुपये की कोई स्कीम है, उसका पाईप बिछाने का काम है, तो 40,00,000/-रुपये सड़क के लिए लोक निर्माण विभाग मांग रहा है। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो भी प्राक्कलन बनें, इस प्रावधान को ध्यान में रखकर वे बनाएं ताकि जब हम उस स्कीम को क्रियान्वित करते हैं या उसका टैण्डर करते हैं, तो हमें कभी इस प्रकार की दिक्कत न हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

27/03/2018/1255/RG/HK/2

अध्यक्ष : अब श्री हर्षवर्धन चौहान जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हर्षवर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-13 पर जो मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं, मैं उनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं संक्षेप में ही बोलना चाहूंगा। मेरा चुनाव क्षेत्र पांवटा डिवीजन में पड़ता है और पांवटा डिवीजन हिमाचल प्रदेश का शायद सबसे बड़ा डिवीजन है जिसमें पूरा पांवटा चुनाव क्षेत्र आता है, शिलाई चुनाव क्षेत्र आता है, आपके चुनाव क्षेत्र का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है और रेणुका का भी आता है। इसलिए विशेषकर शिलाई चुनाव क्षेत्र में सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य के एक नए डिवीजन को खोलने की जरूरत है। जैसा कि मैंने एक तारांकित प्रश्न संख्या 129 किया था जिसका उत्तर भी माननीय मंत्री जी ने यहां था। इसमें 21 स्कीम्ज बहुत लंबे समय में लम्बित पड़ी हैं और 12 स्कीम्ज ऐसी हैं इनमें से कोई वर्ष 2008, वर्ष 2009 या कोई वर्ष 2010 की है, आपने इसमें तिथि भी दी है कि ये स्कीम्ज कोई वर्ष 2018 या कोई वर्ष 2019 में कम्पलीट होंगी। मैं आपके माध्यम से विभाग से भी अनुरोध करुंगा कि कम-से-कम जो तिथि आपने इनके लिए निर्धारित की हैं, उसमें ये पूर्ण हो जाएं ताकि लोगों को इनका लाभ मिल सके। क्योंकि ये लम्बित स्कीम्ज हैं जोकि 21 हैं।

अध्यक्ष महोदय, शिलाई जो मेरे चुनाव क्षेत्र का मुख्यालय है, वह शहर का रूप ले रहा है और वहां पानी की गंभीर समस्या है। अभी भी जो पीने-के-पानी की पुरानी स्कीम हैं, उनकी राईजिंग मेन समय-समय पर टूट जाती है, फट जाती है और कई दिनों तक पानी नहीं आता। इसलिए शिलाई के लिए भी एक नई पीने-के-पानी की स्कीम को बनाने की जरूरत है और इसके लिए लगभग 24 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनाई है। तो मेरी प्राथमिकता भी रहेगी क्योंकि वह केवल शिलाई के लिए नहीं बल्कि शिलाई के आस-पास लगभग 20-25 हजार की आबादी को कवर करेगी। इससे शिलाई का विकास रुक रहा है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि गर्मियां आने वाली हैं, तो सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को भी सूखे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।अध्यक्ष महोदय, अब तो बहुत सारी स्कीमें बन रही हैं और लिफ्ट स्कीमें बन रही हैं। जैसा समय-समय पर यहां

जिक्र किया गया कि आपके पास पम्प ऑपरेटर्ज नहीं हैं और निजी ठेकेदारों को आपने ये स्कीम्ज दी हुई हैं और वे उनका रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं। समय पर पानी नहीं देते। इसलिए आपको पम्प ऑपरेटर्ज की भी नियुक्ति करने की जरूरत है। वैसे

27/03/2018/1255/RG/HK/3

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की स्कीमें विभाग के माध्यम से ही सुचारू रूप से चल सकती हैं। पम्प ऑपरेटर्ज लगाने की जरूरत है। कुछ समय पहले पिछले साल मैंने कोटगा-कांडो स्कीम का उद्घाटन किया। आप यह देखें कि ठेकेदार के माध्यम से स्कीम में जो मशीनरी, पम्प या जो मोटर लाई गई थी, वह सैकण्ड हैण्ड लाई गई थी। उसको बाइंडिंग करके ले आए, उस पर पेंट कर दिया और उसको लगा दिया। इसलिए सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में विशेष करके जो स्कीमें लम्बित रहती हैं, वे ठेकेदारों की कमी के कारण रहती हैं। वे काम ले लेते हैं, परन्तु काम नहीं करते। सबसे बड़ी बात है कि जो लिफ्ट इरीगेशन या वाटर सप्लाई की स्कीम हैं इनमें मैज्योरिटी कम्पोनेंट राईजिंग मेन की पाईप का होता है। अब क्या होता है कि आपके विभाग में जो सिस्टम चला हुआ है कि जो ठेकेदार राईजिंग मेन का काम ले लेगा, उसको 80% प्रतिशत पेमेंट पहले दे दी जाएगी। वह पाईपें खरीदकर साईट पर छोड़ देता है और फिर उसको फिट भी नहीं करता। मैंने स्वयं देखा है कि राइजिंग मेन की पाइपों की जो क्वालिटी है, तो उसमें भी कई जगहों पर कम्प्रोमाईज होता है। क्योंकि वे ठेकेदार क्रय करते हैं। वे ऐसी कमजोर पाइपें ले आते हैं जो 2-4 या 6 सालों में नीचे गिरनी शुरू हो जाती हैं और फटनी शुरू हो जाती हैं।

27.03.2018/1300/जेके/वाईके/1

श्री हर्ष वर्धन चौहानः------जारी------

इस बारे भी मैं विभाग से चाहूंगा कि राइजिंग मेन की पाइपें भी आप डिपार्टमैंट के माध्यम से खरीद करके दो क्योंकि आपकी जो डिस्ट्रिब्यूशन की पाइपें हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि डिपार्टमैंट उनको खरीदता है। राइजिंग मेन की पाइपें अगर डिपार्टमैंट खरीदेगा तो वह ज्यादा बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। कई जगह आपको छोटे-छोटे पाट्र्स नहीं मिलते। स्कीमों में क्या होता है कि ठेकेदारों द्वारा पाइपों को दबाया नहीं जाता । आप ढाई फिट दबाने के लिए ठेकेदार को पेमेंट करते हैं लेकिन बहुत सी जगह पर जमीन के ऊपर ही पाइपें होती हैं और वे समय-समय पर पत्थर से या किसी अन्य चीज़ से टूट जाती हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। महेन्द्र सिंह जी, आप तो तुजुर्बेकार मंत्री हैं, आपमें क्षमता है इसलिए इस विभाग का सुधार करिए। आज तो कहते हैं कि जल ही जीवन है और यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो तीसरा विश्व युद्ध होना है वह भी पानी के लिए होगा इसलिए इस ओर हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें स्टाफ की बहुत कमी है। मेरे शिलाई चुनाव क्षेत्र में कोफटा में अगर आप एक डिविज़न खोल दें तो उससे पांवटा का वर्कलोड कम हो जाएगा। रोहनाट वाले एरिया में आई.पी.एच. के दो सैक्शन हैं। उसके दोनों सैक्शन नौहराधार डिविज़न में हैं। मैं चाहूंगा कि उनको पांवटा डिविज़न में लाया जाए। इस तरह की कई छोटी-छोटी बातें हैं, मैं आपको लिखकर भी दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं मंत्री जी को समय-समय पर बताऊंगा । आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोवकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।

27.03.2018/1405/SS-AG/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2:05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री जगत सिंह नेगी जी।

श्री जगत सिंह नेगीः माननीय अध्यक्ष महोदय, डिमांड नं0-13 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इरिगेशन एंड पब्लिक हैल्थ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हिमाचल प्रदेश में इस विभाग के द्वारा काफी अच्छा काम भी हुआ है। परन्तु समय के साथ इसमें बहुत सारे

परिवर्तन की ज़रूरत है। बहुत सारी नई सोच की आवश्यकता है। जिस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में इरिगेशन डिपार्टमैंट में पेयजल के लिए या अन्य जो हमारा सीवरेज सिस्टम है उसके लिए पाइपें बिछाई गई हैं शायद मैं समझता हूं कि हम चांद तक पहुंच जायेंगे, इतनी पाइपें बिछी हैं। परन्तु अब समय के साथ इस विभाग, पी0डब्ल्यू0डी0 और अन्य विभागों में भी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला है। आप सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार जितना आज हमारे इन विभागों में है उससे हमारा आई0पी0एच0 विभाग अछूता नहीं है। जे0ई0 से लेकर एस0डी0ओ0, फिर एक्सियन, फिर उसके ऊपर एस0ई0 और फिर उससे ऊपर के अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बगैर कमीशन के काम नहीं होता है और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे वर्कस की क्वालिटी में कमी आ रही है। अभी पाइपें बिछाने के लिए दो-ढाई फुट खोदने का आपका नियम है परन्तु केवल 5-5 या 6-6 इंच खोदकर पाइप बिछाकर उस पर मिट्टी डालकर दो-ढाई फुट के पैसे लिये जाते हैं। वहीं से भ्रष्टाचार की शुरूआत होती है। अब सरकार ने नियम बनाया है कि दो से ज्यादा टैंडर एक ठेकेदार एक समय नहीं लेगा। परन्तु आपने देखा होगा कि ज्यादातर ठेकेदार 10-11 टैंडर लेकर बैठ जाते हैं, इसीलिए समय-सीमा पर काम नहीं होता है क्योंकि ठेकेदारों के पास काम की कोई कमी नहीं है। आज अगर आप इधर तकाजा करेंगे तो वे थोड़े से आदमी इधर लगा देंगे और फिर दूसरी जगह पर भेज देंगे। इस तरह से जो काम समय-सीमा में पूरा होना चाहिए, उसको पूरा करने में कई-कई साल लग जाते हैं। तो इस भ्रष्टाचार को रोकने की ज़रूरत है। यह नहीं है कि आप कहेंगे कि आपको दो-तीन महीने हुए हैं और आपके टाइम में यह भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। आपकी भी तीन बार सरकारें रहीं। बड़े लम्बे अर्से तक आपको भी मौका मिला तो यह बीमारी चाहे वह हमारे समय में रही या चाहे आपके समय में रही या अभी रहेगी तो इसको दूर करने की सबसे बड़ी ज़रूरत

27.03.2018/1405/SS-AG/2

है। तभी जाकर जो हमारा आई0पी0एच0 विभाग है इसका पानी जन-जन तक पहुंचाना है, सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए करनी है तभी ठीक हो सकता है। ठेकेदार जो टाइम पर अपना टैंडर का काम पूरा नहीं करते हैं उनको ब्लैकलिस्ट करने की ज़रूरत है। विभाग के अधिकारी किसी भी ठेकेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करते। हम कहते हैं कि इस

ठेकेदार का काम दो साल का था लेकिन 10 साल में भी पूरा नहीं कर रहा है, टैंडर rescind करने की बात करते हैं तो उसको रिसाइंड नहीं किया जाता क्योंकि उन अधिकारियों की ठेकेदार को कहने की हिम्मत कहां रहेगी जबकि उन्होंने पहले ही कमीशन ले रखा है। अब तो ऐसा है कि कमीशन एडवांस में लिया जा रहा है क्योंकि पता नहीं कब उसका ट्रांसफर हो जाए। इसलिए कहता है कि टैंडर लग गया, पैसे भी साथ ही ले आओ। आप जानते हैं कि सब एडवांस में चल रहा है। आपसे यह छुपा नहीं है। --(व्यवधान)-- इस प्रथा को आप किस तरह से कर्व करेंगे यह देखने की ज़रूरत है। यह सही समय पर होना चाहिए। अभी यहां पर आउटसोर्स पर काम चला हुआ है खासकर पानी का, पम्पों का। अब इस प्रक्रिया को भी देखने की ज़रूरत है। आप कहेंगे कि इसके ऊपर कोशिश करेंगे। परन्तु आपको भी समय लगेगा जब तक आप नए पम्प ऑपरेटर लायेंगे, तब तक जो बीच का गैप है वह बिना आउटसोर्स के आपका काम होने वाला नहीं है। इस बार बारिशें भी कम पड़ी हैं और इस बार दिक्कत ज्यादा होगी तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। किस तरह से यह काम होगा उसको आपको देखना पड़ेगा। अब एक समस्या जो खासकर हमारे जनजातीय क्षेत्रों में है कि हमारा जो इलाका है वहां पर टैरेन ऐसा है कि बिना ब्लास्टिंग के कूहलें नहीं बनती, पाइपें नहीं बिछाई जाती हैं परन्तु मेरे दो डिवीजन आई0पी0एच0 के हैं, एक रिकांगपिओ और दूसरा पूह का है। दोनों के पास एक्सप्लोसिव के लाइसैंस नहीं हैं। हमने पिछली सरकार के समय लाइसैंसिज़ को लेने की शुरूआत की थी लेकिन प्रक्रिया बहुत लम्बी है तो

27.03.2018/1410/केएस/एजी/1

श्री जगत सिंह नेगी जारी---

मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये लाइसैंसिज़ दोनों डिविज़नों के पास हो ताकि हमारा जो काम बाधित हो रहा है, उससे बचा जाए। साथ में जो आपके टैंक बनते हैं, इनकी क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। टैंक बनने के कुछ ही हफ्तों में लीकेज शुरू हो जाती है। बनाने को तो आजकल हम सभी आर.सी.सी. के टैंक बना रहे हैं परन्तु जब सरिया लगाया जाता है या सीमेंट लगाया जाता है तो जे.ई. ही मौके पर नहीं होते। आई.पी.एच. विभाग में

सुपरविज़न की बहुत आवश्यकता है इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जब आप विपक्ष में थे तो आप बड़ी-बड़ी बातें रखते थे और हमें आपकी कई बातें अच्छी भी लगती थी परन्तु पता नहीं क्यों उधर जाने के बाद आपकी आवाज भी कम हो गई है, जोश भी कम हो गया है। मुझे लगता है कि शायद आप बजट से खुश नहीं है। आप जो जवाब देते हैं वह बहुत विस्तार से देते हैं परन्तु सही प्वाइंट पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। शायद आप भी बजट से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि आपको भी बजट में पैसा बहुत चाहिए था परन्तु उस हिसाब से आपको बजट नहीं मिला है। एक स्टेटमैंट आपका आया कि तीन हजार करोड़ रुपये में आप पूरे हिमाचल की प्यास बुझा देंगें। पता नहीं कौन सा फार्मुला आपके पास है कि तीन हजार करोड़ रुपये में पूरे हिमाचल की प्यास बुझा देंगे? आपने शायद भागीरथी का कोई नुस्खा देख लिया होगा। कहा जा रहा है कि शिमला के पानी की योजना के लिए दो हजार करोड़ से भी ऊपर लगने वाला है। अगर दो हजार करोड़ यहीं पर लग जाएंगें तो तीन हजार करोड़ में पूरे हिमाचल की प्यास कैसे बुझेगी ? मंत्री जी जब आप जवाब देंगें तो कृपया इस बारे में स्पष्टीकरण दें क्योंकि हमारे इलाके में भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वगैर सिंचाई के कोई काम नहीं होता क्योंकि वहां पर बारिश बहुत कम होती है। हमारी कूहलें हार्ड टैरेन में है और उसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है। हमने प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के तहत करीब 15 से ज्यादा स्कीमें बनाकर डी.पी.आर्ज़. आपको भेजी है । केन्द्र सरकार ने बहुत शोर मचाया है कि हम तो पैसा ही पैसा दे रहे हैं लेकिन उन 15 में से एक स्कीम के लिए पैसा आया है। ये जो 14 और स्कमें मेरी पड़ी हैं, मैं चाहूंगा कि

27.03.2018/1410/केएस/एजी/2

आप उनका ध्यान रखें। इस बार हमारे वहां बर्फबारी भी कम हुई है। हमारा एक पूह गांव है और जब बर्फ कम पड़ती है तो वहां पर हमेशा बहुत नुकसान होता है। इस बार बर्फबारी न होने के कारण टैम्परेरी अरेंजमैंट के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ पम्पों का

प्रावधान करें और पानी को लिफ्ट करके हमको पानी दें। पिछली बार तो ट्रैक्टरों के माध्यम से ड्रमों में डालकर हमें पानी वहां पर लोगों को पहुंचाना पड़ा था। उससे भी बदत्तर स्थिति इस बार है। पूह की तरह और भी गांव हैं और इस बार सेब की फसल को बचाने के लिए आप कुछ प्रयास करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

रीवर या खड्डों की चैनेलाइजेशन के लिए भी हमने डी.पी.आर. बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक में हमने प्रक्रिया कम्पलीट भी कर दी है जिसमें रूशकलंग गांव, रिस्पा गांव, खदरा गांव और कानम नाला है । डी.पी.आर. रूढ़की के इंस्टीट्यूट से बन कर तैयार भी हो गई है । ऐस्टिमेशन भी कम्पलीट हो रही है तो इसको भी आप सिरे चढ़ाएं और साथ में सांगला घाटी में बस्पा नदी के कारण हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वहां पर जैसे हमारा थैमगारंग है, बड़सेरी है, सांगला गांव है और वहां पर 300 मैगावाट का एक प्रोजैक्ट भी है जिसका 20 करोड़ का कैट प्लान का पैसा भी था वह भी लगभग खत्म है क्योंकि कैट प्लान आपके माध्यम से नहीं हुआ कैट प्लान तो फोरैस्ट के माध्यम से हुआ परन्तु उसका मौके पर कोई फायदा नहीं हुआ है तो इसकी भी हम डी.पी.आर. बना रहे हैं। उसके लिए केवल 10-15 लाख रु0 की बात थी और उसके लिए भी आपने कहा कि धन की उपलब्धता पर है। अगर 10 लाख रुपये भी आप का विभाग मेरे इलाके के लिए न दे पाए तो फिर हमारी डी.पी.आर. कब तैयार होगी?

27.3.2018/1415/av/dc/1

श्री जगत सिंह नेगी-------- **जारी**

अतः इस ओर भी ध्यान देने की जरुरत है। बाकी अगले बजट में देखेंगे क्योंकि तब तक आपका सौ दिन का कार्यकाल पूरा होने के साथ-साथ 365 दिन का कार्यकाल भी पूरा हो जायेगा। धन्यवाद।

27.3.2018/1415/av/dc/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राम लाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राम लाल ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः13 के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं मैं उस पर हो रही चर्चा में अपने आपको शामिल करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि आपने मीटिंग में कहा था कि पिछले वर्षों में पाइप्स नहीं खरीदी गई थी। पिछली सरकार के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में पाइप्स नहीं खरीदी गई। लोगों को जरुरत थी मगर जब पाइप्स के लिए टैंडर ही नहीं हुए तो शायद वह पैसा भी लैप्स हो गया। अभी आपने पाइप्स के लिए आर्डर किए हैं और शायद कुछ पाइप्स आ भी गई हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में जहां गर्मी के मौसम में पानी की ज्यादा दिक्कत आयेगी वहां के लिए कृपा करके आप ई0एन0सी0 साहब और नीचे के अधिकारियों से यह कहें कि पहले पाइप्स वहां पर पहुंचा दी जाए जहां पर लोगों को पानी की ज्यादा दिक्कत आने वाली है। मैं मंत्री जी का ध्यान अखबारों में छपी खबर और यह इलैक्ट्रोनिक मीडिया में भी आया कि कुछ साईंटिस्टों ने यह भविष्यवाणी की थी कि वर्ष 2025 तक पूरे भारतवर्ष में 2/3 पानी सूख जायेगा और केवल पानी का चौथा हिस्सा रह जायेगा। साथ में, उन्होंने यह भी कहा था कि इसका असर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसलिए सरकार को वर्ष 2025 के लिए की गई इस भविष्यवाणी/चुनौती का सामना करने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। गांव में हैण्ड-पम्प्स और बावड़िया अभी से सूखनी शुरू हो गई है। अगर हम हैण्ड-पम्प्स के ऊपर ही निर्भर हो जायेंगे और बावड़ियों में पानी नहीं रहेगा तो आने वाले दिनों में पानी की बहुत ज्यादा प्रोब्लम हो जायेगी। मुझे लगता है कि नदियों में पानी ज्यादा दिन रहने की सम्भावना है। इसलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है कि पूरे प्रदेश के अन्दर जहां-जहां पर भी नदियों से पानी उठाया जा सकता है, उठाया जाए। उसके लिए वर्ष 2025 तक हम ऐसा इन्तजाम करें कि अगर पानी सूख जायेगा तो जो स्कीमें हम नई प्रपोज करेंगे उन स्कीमों से हमारी पुरानी स्कीमों में पानी मिल जायेगा। आने वाले वर्षों में जो पानी को लेकर

दिक्कत आने वाली है ऐसा करने से लोगों को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। साथ में, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा क्योंकि सुबह भी इस बारे में प्रश्न लगा था। आपने बहुत सारी

27.3.2018/1415/av/dc/3

स्कीमों के बारे में चर्चा की है और उनके लिए आदेश भी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ठेकेदारी प्रथा है। ठेकेदार ठेका ले लेते हैं और यह सब कुछ अब ऑन लाइन हो रहा है। मान लो कोई कांगड़ा में ठेका लेता है उसका हिमाचल के ऊपर वाले एरिया में पता नहीं होता। कई बार ब्लैक लिस्ट ठेकेदार दूसरी जगह जाकर ठेके ले लेते हैं। कई ठेकेदार काम ले लेते हैं मगर वे उस काम को समय पर पूरा नहीं कर पाते हैं। मैंने यह बात आपके ध्यान में पहले भी लाई है। कई जगह ठेकेदार को ठेका लिए हुए 6-6 साल हो गये हैं, वहां पाइप्स की सप्लाई भी हो गई है और पाइप्स के ढेर लगे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तनबोल-जगातखाना में सिंचाई की योजना के काम को शुरू हुए 6 साल हो गये हैं।

27.03.2018/1420/TCV/DC-1

श्री राम लाल ठाकुर... जारी।

लेकिन ठेकेदार का यही पता नहीं है कि वह कब उस काम को पूरा करेगा। गम्बर नदी से पानी उठा करके, आगे ग्रेविटी में वह पानी दो पंचायतों को जाना है और उससे लोगों के खेतों को पानी मिलेगा। हमारी सरकार कह रही है कि हम किसानों की दोगुनी इनकम करेंगे। लेकिन वह पानी के बिना नहीं हो सकती है। पानी के लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, मैंने आज सुबह भी आपसे चंगर एरिया के बारे में बात की थी। आप जानकारी ले लें कि वहां पर ठेकेदार कौन-कौन है, कहां के हैं और किसके रिश्तेदार हैं? जो ठेकेदार ऊना जिला के हैं, उनकी रिश्तेदारी पंजाब में है। आन्नदपुर में एक नेता का रिश्तेदार है, उसको ठेका आगे चला गया। उसने अपना कोई और नज़दीकी ढूंढ लिया और उसको काम आगे दे दिया। मैंने जब डिपार्टमैंट से पूछा तो जे0ई0 और एस0डी0ओ0 स्वयं बोल रहे हैं कि फ्लां

ठेकेदार है, वह नहीं आता है। फिर उसका अगला रिश्तेदार है, उसके बाद उसका और आगे रिश्तेदार है। इस तरह से आगे 5-5 जगह पर सब-लैटिंग हो गई है। अब किसको पूछें कि कौन कसूरवार हैं? मेरा निवेदन है कि हमें इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि जो यहां पर हमारी स्कीमें हैं, उन स्कीमों के ऊपर मैनपॉवर अगर नहीं होगी तो आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो, ये नहीं होगा। आप इन स्कीमों को आउटसोर्स पर चलाना चाहते है। मैं मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहूंगा, मैं पिछली सरकार में भी माननीय वीरभद्र सिंह जी से यही निवेदन करता था कि ये जो आउटसोर्स पर रखे हुए हैं, इससे सरकार किसी की भी हो, गालियां ही पड़ती है। ये कर्मचारी काम नहीं करते है। जहां पर 15-15 आदमियों की सैलरी निकल रही है, वहां पर 7 या 8 आदमी रखे हुए हैं। They are not trained. कई जगह पर तो 4-4 आदमी रखे हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके ये जो हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आई0पी0एच0 भी आता है, जब तक इन विभागों में मैनपॉवर

27.03.2018/1420/TCV/DC-2

नहीं होगी, तब तक आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, इनमें सुधार आने वाला नहीं है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है कि इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखें। एक पूरे प्रदेश का मसला मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जितनी हमारी पुरानी स्कीमें बनी है, उन स्कीमों के ऊपर जो स्टोरेज़ टैंक बने हुए हैं, वे खुले पड़े हुए हैं, उनमें कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है। जब हवा चलती है तो सारा कचरा उड़कर उसमें जाता है। उसमें बन्दर भी पानी पी रहे हैं, कई बार मरे हुए बन्दर/गीदड़ टैंकों में पड़े होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके ये जो टैंक्स बने हैं, इनको कवर करवाने की जरूरत है। इनमें कभी भी कोई अन-टू-डू इनसीडैंट हो सकता है। क्या पता कोई टैंकों में ज़हर डाल दें, तो उससे कितने लोगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन टैंकों पर ढक्कन लगा दिए जायें।

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ के कारण ज़मीन बह रही है, बहुत सारी खडडें ऐसी हैं, जिनमें खन्न माफिया सक्रिय हैं। इनके पहले से भी और ज्याद सक्रिय होने की उम्मीद है। आप खड्डों को देख लीजिए। मैं आपको अपने बिलासपुर जिला की बात बताना चाहूंगा। सीर, सुकर और सरयाली खड्डें है (घण्टी) Speaker, Sir, give me two minutes more. वैसे भी जब आप घंटी बजाते हैं तो मुझे इसका म्युजिक बड़ा अच्छा लगता है। मेरी एक अली खड्ड है, जिससे 9 पंचायतों को पीने का पानी जा रहा है,कूहलों का पानी भी इसी खड्ड से जा रहा है।

27-03-2018/1425/NS/HK/1

श्री राम लाल ठाकुर ------जारी

सदर की भी आठ पंचायतें हैं। इन खड्डों से पत्थर उठाने की वजह से ये खड्डें बीस-बीस फुट नीचे चली गई हैं। अगर मान लो चैनलाइजेशन नहीं करेंगे तो खेतों को पानी नहीं जायेगा। जिन लोगों के घराट खड्डों के किनारे पर है, वे बंद हो जायेंगे। कूहलें बंद हो जायेंगी। मेरा आपसे निवेदन है कि अली खड्ड के दोनों किनारों पर जो कटान हुआ है, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे। आपने कूहलों के लिए भी पैसा रखा हुआ है तो कृपया करके इस तरफ भी ध्यान दें। लोगों को कूहलों से ज्यादा फायदा होगा। उठाऊ सिंचाई योजनाओं से पानी उठाना पड़ेगा, बिजली का खर्च आएगा। लेकिन कूहलों से लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इसलिये इनको ज्यादा स्ट्रैंथन किया जाये। मेरा आप से निवेदन रहेगा कि मेरे क्षेत्र की स्कीमों के ऊपर पिछले वर्ष कुछ पैसा आपके विभाग ने दिया है। वे इस प्रकार हैंः- सिंचाई योजना नेरी जामली की स्कीम, इस पर 56.93 लाख रुपये की राशि सैंक्शन हुई है। कोठीपुर की स्कीम में 19.90 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। एक नियाई सारली की हरिज़न बस्ती की सिंचाई स्कीम है, इसमें 24.83 लाख रुपये की राशि सैंक्शन हुई है। मेरे क्षेत्र में एक स्कीम चिल्ला की उठाऊ सिंचाई योजना है और यह बहुत पुरानी है तथा इस पर 29 लाख 18 हज़ार 600 रुपये सैंक्शन हुए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये छोटी-छोटी स्कीमें हैं और इसमें ज़मीन ज्यादा आ रही है, अगर आप इन स्कीमों को जल्दी से बनाने के आदेश देंगे तो इससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं एक ही बात कहूंगा और आपको अब घण्टी नहीं बजानी पड़ेगी। मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मेरा आज एक प्रश्न लगा था। लेकिन आज दो ही प्रश्न चले और आज कुल 57 प्रश्न लगे हुए थे। इनका जवाब सभी माननीय मंत्रियों ने सभापटल पर रख दिया है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसा हो रहा है कि चंद चांदी के टुकड़ों के लिए, मैं barring political affiliation बोल रहा हूं, कुछ लोग इतने बेईमान हो गये हैं कि वे सरकारी सामान से ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं बीस सूत्रीय कार्यक्रम का चेयरमैन था तो मैंने सर्किट हाउस में प्रैस वालों को बुला करके प्रैस कान्फ्रैंस रखी थी। जब मैं वहां पर गया तो चार-पांच प्रैस वाले मेरे पास आये और बोले कि सर, यह सर्किट हाउस हैं and it is most safest place for theft.

27-03-2018/1425/NS/HK/2

मैंने कहा हुआ क्या है? वे कहने लगे आप पिछली तरफ जाओ और देखो। वहां पर लगभग 50 पाइपें मोटे डाई की थीं और ये पाइपें बिल्कुल नई थीं तथा वे इन पाइपों को काट रहे थे। कोई पी0डब्लयू0डी0 विभाग का ठेकेदार था, उसने आई0पी0एच0 की पाइपें ले कर ठेका पूरा करने का काम कर रहा था। मैंने वहां पर खुद देखा है और इसके लिए किसी ऐविडैंस की जरूरत नहीं है। मैंने तुरन्त जिलाधीश, एस0पी0 और एस0एच0ओ0 को कहा। एस0एच0ओ0 मौके पर आ गया और मैंने आपके एक्स0ई0एन0 को भी बताया था। एक्स0ई0एन0 ने कहा कि ये पाइपें हमारी हैं। उन पर मोहरें लगी हुई थीं। साथ में यह कहा कि ये पाइपें नई हैं। जब पुलिस ने इन पाइपों को अपने कब्जे में ले लिया और सुफुर्ददारी पर थीं तो मुझे नहीं पता कि उस केस का क्या हुआ है और कहां चला गया है? मुझे आप ये बतायें अगर आप चोरी को बढ़ावा देंगे और वे चोरी करके सरकारी खज़ाने से आई0पी0एच0 विभाग की पाइपें लगायेंगे और पी0डब्ल्यू0डी0 के ठेके को पूरा करेंगे तो मैं कहूंगा यह दोनों तरफ से बेईमानी होगी। आज मुझे बड़ी हैरानी हुई, जब मैंने आपका दिया हुआ उत्तर पढ़ा और उसमें लिखा है, जी नहीं। अगर जी, नहीं की बात है तो मैं जीवित हूं और माननीय मंत्री जी मेरे सामने सब कुछ हुआ है। प्रैस वाले वहां पर थे। कहां गई वह पुलिस और विभाग, जिन्होंने कहा कि वे पाइपें कबाड़ियों से आईं थी। आप मुझे बताईये कि क्या कबाड़ियों के पास नई/अनफिटिड पाईपें जा सकती हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे-ऐसे केसिज़ को देखें और इसमें कोई कार्रवाई करें। हमारी सारी खड्डें खाली हो

गई हैं। कहीं पर भी कोई क्वायरी नहीं थी। इन खड्डों से फोर लेने के लिए सारा पत्थर चला गया, रोड़ी भी चली गई है। लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है। एम0फार्म0 का पैसा भी गायब हो गया है। सबको पता है कि ये पत्थर और रेत सप्लाई करने वाले कौन लोग हैं? लेकिन क्यों ये सूचना नहीं आ रही है?

27.03.2018/1430/RKS/HK-1

श्री राम लाल ठाकुर...जारी

हम इसके बारे में माननीय उद्योग मंत्री जी से पूछ सकते हैं परन्तु हमारा विधान सभा प्रश्न नहीं लगता है। आज बड़ी मुश्किल से पहले नम्बर पर मेरा विधान सभा प्रश्न लगा हुआ है। हम प्रश्न पूछने के लिए तैयार होते हैं परन्तु हमारे प्रश्नों की बारी ही नहीं आती है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो चोरी करने वाले लोग हैं, चाहे वे सरकार में बैठे हों या बाहर हों, राजनीतिक संबद्ध से किनारे हटकर, जो इस प्रकार के असमाजिक तत्व हैं, आपको उन पर ध्यान रखना चाहिए। इसमें जो हमारे करने लायक होगा, उसके लिए हम आपके साथ हैं। अगर हम इन स्कीमों को ईमानदारी से चलाएंगे तो किसान की आमदनी भी बढ़ेगी। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने भी यही सोचा है कि आमदनी दोगुना हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिना पानी और पैसे के आमदनी दोगुनी हो जाए। किसान के खेत को पानी देना हमारी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए, मैं यह समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय मंत्री जी you are a dynamic Minister. क्योंकि आप जिस काम में लगते हैं उसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो बेईमान ठेकेदार हैं उनके ऊपर आप ध्यान देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.03.2018/1430/RKS/HK-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्याः 13-'सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई' जो कटौती प्रस्ताव आज प्रस्तुत हुआ है, उस पर बोलने के लिए मैं शामिल हुआ हूं। यह ठीक है कि आई.पी.एच. विभाग सीधा पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है। यह एक महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय मंत्री जी बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं और मुझे लगता है कि आप इस विभाग को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। ऐसी उम्मीद हम लोग करते हैं। मैं समाचार पत्र में भी पढ़ रहा था कि आई.पी.एच. विभाग द्वारा लगभग 33 सौ करोड़ रुपये की डी.पी.आर्ज. तैयार की जा रही है। पहले हम पुराने स्त्रोतों बावड़ी, कुएं से पानी भरते थे। लेकिन जब से वाटर सप्लाई का सिस्टम शुरू हुआ है, शुरू-शुरू में हर गांव में एक, दो या तीन नलके होते थे। धीरे-धीरे इन नलकों की संख्या बढ़ती गई। आज गांव में कोई ऐसा घर नहीं है, अमीर-गरीब हर घर में नलका है। एक नहीं बल्कि 3-3 नलके हैं। जो योजनाएं जितनी जनसंख्या के लिए बनाई गई थीं, उन योजनाओं से पानी की पूर्ति करना विभाग के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। हम लोग जब भी गांव में जाते हैं तो सबसे ज्यादा शिकायतें पानी की आती है कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है। अब गांव में 10 नलके हो गए और पाइप आधी इंच की ही है। उन नलकों में पानी नहीं आ रहा है। सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। आप डी.पी.आर्ज. तैयार कर रहे हैं आप निश्चित तौर पर इस बारे में विचार कर रहे होंगे। जिन गांवों में पाइप लाइनें चेंज होनी है, उन पाइपों को चेंज करने के लिए डी.पी.आर्ज. तैयार की जाए। विश्व में आने वाले समय में सबसे बड़ी चिंता पानी की होगी। इसके बारे में कई बार चर्चा हुई है। पानी की कंजम्पशन बढ़ रही है। यह भी कहा जाता है कि यदि अगला कोई विश्व युद्ध होगा तो वह पानी को लेकर ही होगा। आजकल आप देख रहे होंगे कि पंजाब और हरियाणा वाले आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब वाले कहते हैं कि हमने पानी नहीं देना है और हरियाणा वाले कहते हैं कि हमने पानी लेना है। मैंने कहा पानी तो हिमाचल प्रदेश का है। पानी हिमाचल प्रदेश दे रहा है और लड़ आप लोग रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि जहां पर पानी का स्तर नीचे जा रहा है, वहां पर खड्डों में चैक डैम बनाए जाएं। माननीय सदस्य, श्री राम लाल ठाकुर जी कह रहे थे कि जहां खनन हो रहा है वहां पर पानी की स्कीमें भी क्या करेगी। 15-15, 20-20, 50-50 फुट खनन करके खड्डें नीचे चली गई हैं।

27.03.2018/1435/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री राजेन्द्र राणा .....जारी

अब पानी कहां से मिलेगा? आपने देखा होगा, जिन खड्डों में पुराने समय में घराट पानी में चलते थे। जहां पर घराट चला करते थे वहां पानी अब रहा ही नहीं । पानी होता था, लेकिन उसे आई.पी.एच. विभाग ने उठा लिया है। सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये जो खनन किया जा रहा है, जिस खनन से पानी का लैवल नीचे जा रहा है, इसकी सरकार को चिंता करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत गम्भीर समस्या पानी की हो जाएगी। इसके अलावा सुजानपुर चुनाव क्षेत्र 2003-2007 तक जब प्रदेश में माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस समय बमसन के लिए उस समय की सबसे बड़ी स्कीम लगवटी-बमसन के लिए उठाऊ पेयजल योजना लगभग 70 करोड़ रुपये के करीब-करीब की वह योजना थी और लगभग 11 महीने में तैयार करके दी थी। बमसन का जो क्षेत्र है वह माननीय मंत्री जी के क्षेत्र के साथ बिल्कुल लगता है, आप तो बिल्कुल पड़ोसी हैं। वह एक पहाड़ी क्षेत्र है और लोग वहां पर खात्रियों से पानी लाया करते थे। उससे बहुत ज्यादा राहत मिली है परंतु उसके बावजूद मैंने प्रश्न भी किया था कि सुजानपुर में जो टौनी देवी क्षेत्र हैं इसमें पांच पंचायते ऐसी है जिनमें पानी की समस्या आ रही है। टौनी देवी में टपरे, बांरी, सिकन्दर, नार्सी और पटनौण पंचायतें हैं। लोग वहां पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इसलिए विभाग इस बात की चिंता करे, सर्वे करवाए ।

अध्यक्षः कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया है।

अध्यक्षः साढ़े छः मिनट हो गए हैं, पांच मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

श्री राजेन्द्र राणाः यहां पर पानी की बहुत समस्या आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए विभाग कोई नई स्कीम तैयार करे। दूसरा एक जनैहरा ग्राम पंचायत है जो कि हमीरपुर में सर्कट हाऊस के बिल्कुल साथ है। वहां पिछले कुछ वर्षों से पानी की काफी दिक्कत है । पिछली बार एस.सी.कम्पोनेंट से 80 लाख रुपये लाया भी गया, परंतु उससे काम नहीं हुआ, उसका कारण है कि जो झनैरा पंचायत है यह हमीरपुर के बिल्कुल साथ

लगती है और यहां पर आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसका कारण यह है कि बाहर के क्षेत्रों से लोग आ करके वहां घर बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि आबादी बढ़ रही है

27.03.2018/1435/बी0एस0/डी0सी0-2

और पानी की वहां पूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए लगभग साढ़े 3 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बन करके नाबार्ड को गई है। आप इसमें व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप करके इसको जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करें ताकि लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जा सके। अगर हम इजराईल की बात करें, छोटा सा मुल्क है, वहां पर भौगोलिक दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के बराबर होगा। वहां पर एक-एक बूंद बारिश की वे लोग व्यर्थ नहीं जाने देते। वे इसका पूरा इस्तेमाल करते हैं। वे खेतों में जब सिंचाई करते हैं तब भी पानी को बर्बाद नहीं होने देते। हम सभी माननीय सदस्यों को जो यहां बैठे हैं, प्रदेश के लोगों को इस बात को बताना चाहिए कि पानी कहीं बर्बाद न हो। इसके लिए मुहिम छेड़ी जानी चाहिए। सबसे बड़ी चिंता का विषय है जैसा दूसरे माननीय सदस्यों ने भी यह बात रखी है, आई.पी.एच. विभाग जो हर व्यक्ति, हर घर के साथ जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को हर घर को पानी चाहिए। जहां स्टाफ आपके पास नहीं होगा तो विभाग भी क्या करेगा? आपके इस विभाग में फिल्ड स्टाफ बहुत ज्यादा है। इसके लिए विभाग को उचित कदम उठाने चाहिए। हमारी पिछली सरकारों ने जल-रक्षक रखे थे, उन जल-रक्षकों को 1600-1700 रुपया मिलता था अब 2100 रुपया मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 2100 रुपये में जो व्यक्ति सारा दिन काम करेंगा, उसे पार्ट टाइम रखा है परंतु विभाग उससे सारा दिन काम लेता है। क्या कोई नौजवान जब नौकरी लगता है तो 2100 रुपये में अपने परिवार को चला पाएगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि जो कई वर्षों से वाटर-गार्ड कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्राइटिरिया फिक्स करके सरकार उनको अपने विभाग में मर्ज करे ताकि वे लोग भी अपने परिवार का गुजारा कर सकें। विभाग में जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा किया जा सके। इसके अलावा कई जगह पानी भरपूर है परंतु लोगों को पानी फिर भी नहीं मिल रहा है।

27.03.2018/1440/डी.टी./वाई.के.1

श्री राजेन्द्र राणा.. जारी

उसकी वजह यह है कि हमारे वितरण सिस्टम में कमी है। विभाग के लोग ढंग से पानी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी वजह से पानी की समस्या आ रही है। आप अपने फिल्ड स्टाफ एक्सिअन, जे.ई. एस.डी.ओ. को डायरेक्शन दें की पानी भरपूर तरीके से दिया जाए। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, इसके लिए क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। मैंने कई बार यह इश्यू उठाया है कि हमीरपुर शहर के लिए ब्यास नदी से पानी लाया जाए। इसमें 43 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं परन्तु जो भारत सरकार का शेयर बनता है उसकी वजह से काम रूका हुआ है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि इसे परस्यू किया जाए। विभाग ने 43 करोड़ रुपये खर्च कर दिया है और मात्र 10-15 करोड़ रुपये के लिए यह काम रूका हुआ है। इससे प्रदेश की जनता का नुकसान ही नहीं हो रहा है अपितु प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को भी नुकसान हो रहा है। इस परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

27.03.2018/1440/डी.टी./वाई.के.-2

अध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री नन्द लाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लालः अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्याः13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई में जो कटौती प्रस्ताव आया है, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई जलापूर्ति एवं सफाई का मामला जनता से जुड़ा हुआ है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। बजट में जिस तरह से डिपार्टमेंट को एलोकेशन हुआ है, रेशो ऑफ फाइनैंस में ब्रिक्स में जो उनकी डी.पी.आर्ज. गई हैं, कितना वहां से एलोकेशन होना है और किस तरह से काम चलेगा। अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी 100 प्रतिशत लोगों को मिलना चाहिए। सरकारों ने इसके लिए अपने लैवल पर काम किया है। चाहे वे वाटर सप्लाई स्कीम्ज हैं,

लॉकल बावड़ी को मैंटेन करने की बात है या हैंडपंप लगाकर इस तरह के जो प्रयास किए गए हैं, उनके चलते आज हमारी पहचान है। पानी घर-घर पहुंच गया है। बजट सैंसिज यह बताती है कि 89.5 percent people have access to their safe drinking water scheme. This Census was done in 2011 और इसके बाद 24 घंटे पानी की सप्लाई की बात चलती है। आने वाले समय में बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए और जल स्रोतों जो सूख रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत कुछ करना है। चाहे आप हैंडपंप की बात करो, या पीने के पानी की जो सप्लाई आती है उसकी बात करो। इरिगेशन का जो मामला है, इरिगेशन हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 85.67 लाख किलोमीटर एरिया में से मात्र 5.83 लाख एरिया में ही खेती की जा रही है। यह भी एक सोचने वाली बात है। अगर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सिंचाई की सुविधा पर ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारी पीने के पानी और सिंचाई की स्कीम्ज हैं । किसी योजना में काम चल रहा है और किसी में अभी चलना है। मैं उसके भी फिगर बताना चाहूंगा। ग्राम पंचायत दत्त नगर के अंदर एक बहाव सिंचाई योजना है और यह योजना आर.आई. डी.एफ. के अंतर्गत स्वीकृत है। मेरा सरकार से यह आग्रह रहेगा कि इस पर काम तेजी से चल पड़े। इसी तरह ग्राम पंचायत करोगला में बहाव सिंचाई योजना है यह भी ऑगमैंटेशन की स्कीम है। उस पर भी जल्दी से काम चलाया जाए।

27.03.2018/1445/SLS-HK-1

श्री नन्द लाल ...जारी

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ड्रिंकिंग वॉटर की जो हमारी मेन स्कीम है वह काशा पाट से गांव कैन्डी पाट, ग्राम पंचायत काशापाट की है। यह ऑलमोस्ट कंपलीशन स्टेज में है मगर जो उसके नीचे दूर-दराज के एरियाज हैं जो बिल्कुल gorge में हैं, वहां पर भी जो लाईन बिछाई जानी है, उसका काम भी जल्दी से पूरा किया जाए।

इसी तरह से ज्यूरी बधाल ग्राम पंचायत में पानी की एक RIDF के अंडर स्वीकृत स्कीम है। उस पर भी काम जल्दी से शुरू किया जाए।

पुरपन खड्ड से उठाऊ पेयजल योजना पूरे ननखड़ी एरिया की करीब 7 पंचायतों को कवर करती है। उस पर भी आधे से ज्यादा काम हो चुका है। उस पर अक्रौस द रीवर इस तरफ को टैंक बन चुके हैं। उसमें पानी आ चुका है। उसको आगे सप्लाई करने के लिए जो लाइनें बिछनी हैं उनका काम भी चला हुआ है। उसको एक्सपीडाईट किया जाए ताकि इन 7 पंचायतों को लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रिमाडलिंग के बारे में बताना चाहूंगा। जितनी हमारी पुरानी वॉटर सप्लाई स्कीम्ज हैं, जब वह बनीं, उस वक्त लोगों की संख्या कम थी और टैप्स कम लगते थे। आज हालत यह है, जैसा कि बताया गया कि एक ही घर में 4-4, 5-5, 6-6 टैप्स लगे हैं जिसके कारण खपत ज्यादा है। इसलिए रिमाडलिंग की बहुत ज्यादा ज़रूरत है। जितनी भी हमारी ओल्ड स्कीम्ज हैं, उनकी रिमाडलिंग के लिए हर निर्वाचन क्षेत्र से डिमांड रहती हैं। उस ओर तेजी से काम किया जाए। सरकार को सर्वे करके स्वयं यह देखना होगा कि कितनी स्कीमों की रिमाडलिंग होनी है।

हमारे यहां सराहन-बनाउनी में भी एक आगुमैंटेशन की स्कीम है, यह ग्राम पंचायत सराहन में है। यह केस नाबार्ड में गया था। Hopefully it has come back. अगर सैंक्शन होकर आ गया है तो मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी गौर करे। इसी तरह से एक LWSS left out habitation of census village Addu,

27.03.2018/1445/SLS-HK-2

Dwalda GP Baglati, sub-tehsil Nankhari के अंदर स्कीम है। यह भी नाबार्ड से होकर आ गई है। इस पर भी काम शुरू किया जाए।

इसी तरह से एक और स्कीम देव नगर, ग्राम समूह में मछाडा खडड से खनेवली है। इसकी भी under RIDF सैंक्शन हो गई है। इस पर भी काम चालू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अपग्रेडेशन की 2 स्कीम्ज हैं। एक मिनवीं छिलाड़ी पन्द्रह बीस क्षेत्र के अंदर है। इससे पूरे एरिया में पानी की 0 बहाली और सुधार होना है। उस पर भी ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, सभी लोगों ने यहां पर अपनी-अपनी बात रखी। जैसे मैंने बताया कि वॉटर मैनेजमैंट एक बहुत बड़ा चैलैंज है।

अभी हमारे यहां माननीय जितने भी सदस्य हैं, सभी ने अपनी चिंता बताई है कि इस डिपार्टमैंट में करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है। चाहे यह पाईप परचेज करने में हो या वर्क एग्जीक्युशन में हो, इस पर सरकार को खास ध्यान देना होगा ताकि सरकारी धन का सही इस्तेमाल हो।

अभी क्या हो रहा है कि जो हमारे टैंक्स बनते हैं, उनके अंदर क्वैलिटी ऑफ वर्क्स पुअर होता है; उनमें क्रैक्स डवलप होते हैं। फिर जैसे माननीय सदस्य राम लाल ठाकुर जी ने कहा कि उनमें ढक्कन भी नहीं लगे होते हैं और इस तरह जानवर भी उनमें चले जाते हैं। मैंने जो मैजोरिटी ऑफ टैंक्स देखें हैं उनमें जो सैडिमैंटेशन टैंक होता है, उसमें पानी जाता ही नहीं है। For filtration of water, it has to go into that sedimentation tank. उसके न जाने के बावजूद सीधा उसको सप्लाई में जोड़ देते हैं जिसका मतलब है कि हमें फिल्टर्ड वॉटर नहीं मिल रहा है। उस पर भी ध्यान दिया जाए ताकि सैडिमैंटेशन टेंक का इस्तेमाल हो और हमें प्योर वॉटर मिल सके।

दूसरे वैकैंसीज का बड़ा इसु रहा है। जैसे राणा साहब ने वॉटर गार्ड की बात कही, वह सुबह से शाम तक काम करते हैं। उनका वहां पंचायतवाईज

एनरोलमैंट होता है। जब हम पूछते हैं किस-किस पंचायत में हैं तो कहते हैं कि अभी सैंक्शन आनी है। सरकार से आग्रह रहेगा कि जब आपने पंचायतवाईज वॉटर गार्ड लगा रखे हैं तो इनको पंचायतवाईज ही सैंक्शन मिल जाए ताकि वह लोकली डिप्लाय किए जा सकें so that they can take care of the drinking water there.

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस डाक्युमैंट में कहीं भी फ्लड कंट्रोल का ज़िक्र नज़र नहीं आया। मेरा आग्रह रहेगा क्योंकि जब बरसात में पानी से बाढ़ का ख़तरा रहता है तो कई नुक्सान होते हैं, जगह पानी से कटती हैं। मेरा आग्रह रहेगा कि फ्लड कंट्रोल के लिए भी जो यहां स्टेट लेवल से होना है वह यहां से किया जाए and if you have to get something from the Central Government तो उसको भी टेक अप किया जाए ताकि फ्लड कंट्रोल पर भी ज़रूरी ध्यान दिया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी इतनी ही बात कहनी थी। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27/03/2018/1450/RG/AG/1

अध्यक्ष : अब डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल जी चर्चा में भाग लेंगे।

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-13 के अन्तर्गत सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जैसा हम सब भी जानते हैं कि 'जल ही जीवन है।' वह आज इस चर्चा में उभरकर सामने आया है। वैसे तो माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं सैनिक परिवार से संबंध रखते हैं और कर्नल इन्द्र सिंह जी भी यहां बैठे हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि if there is a chance of 3rd World War, it will be for water. तो हम इसी से अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि वाटन मैंनेजमेंट का होना कितना जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि

हमारे बीच Waterman of India आ रहे हैं और हमें उन्हें सुनना है। I have heard him earlier. मैं समझता हूं कि वाटर मैंनेजमेंट के लिए हम जितनी भी चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, जितना भी ज्ञानार्जन कर सकते हैं और जितना भी आने वाली जनरेशन को शिक्षित कर सकते हैं, हमें वह करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे प्रयास किए और I am deeply grateful to the then Chief Minister Raja Virbhadra Singhji कि हमारे चुनाव क्षेत्र में सोलन के लिए आई.पी.एच. सर्कल मिला। मैं समझता हूं कि यहां के बागवानों, किसानों और जनहित में यह बहुत ही अच्छा कदम रहा है। जिससे इन सब चीजों में हमें वाटर मैनेजमेंट करने का भी अवसर मिलेगा। दूसरी अच्छी बात यह हुई है कि ठाकुर महेन्द्र सिंह जी जैसे अनुभवी और कर्मनिष्ठ और एक वाइब्रेंट मिनिस्टर को यह विभाग दिया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह पूर्ण रूप से इसमें सफल होंगे। इनके काम करने का तरीका सभी को मालूम है। ये इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगे। जितने भी अभी तक यहां विचार आए हैं चाहे वे ठाकुर राम लाल जी, श्रीमती आशा कुमारी जी, श्री नन्द लाल जी या श्री मुकेश अग्निहोत्री ने दिए, मैं समझता हूं कि उन सबका समावेश इसमें हो और जो विभाग में गलतियां रही हों, उन्हें हम दूर करने का प्रयास करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में चल रही स्कीमों के बारे में बात करुंगा और उन्हें पूरा करने के लिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस

27/03/2018/1450/RG/AG/2

दिशा में विशेष कदम उठाए जाएं। ग्राम पंचायत शमरोड़ में धरजा ड्रिंकिंग वाटर स्कीम है जो 4,93,00,000/-रुपये की स्कीम है और इससे नौणी क्षेत्र के लगभग एक दर्जन गांव लाभान्वित होंगे। वैसे इस ओर काम चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसे गति पकड़नी चाहिए और मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर विशेष ध्यान देंगे। दूसरी मेजर स्कीम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई की पाटी-कोलियां स्कीम है। यह 118.41 लाख रुपये से बनी हुई है। यह बेसिकली कम्पोनेंट प्लान से बनी है और इसकी ए. एण्ड ई. सैंक्शन इत्यादि की अप्रूवल हो चुकी है। सिर्फ वर्किंग ऐस्टीमेंट बन रहा है। इस ओर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इससे एस.सी. बहुत पॉपुलेशन लुक ऑफ्टर होगी।

मैं माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से भी चाहूंगा कि इसमें भी पैसे का इन्तज़ाम किया जाए। कन्डाघाट में एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम जो दो 2,10,00,000/-रुपये से बनी है। इसकी डी.पी.आर. नाबार्ड को बनने को दी जा चुकी है और approval is awaited.

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं वाटर बॉडीज के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि दो ब्लॉक्ज में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे 105 वाटर बॉडीज का लक्ष्य था जिसमें से 85 पूरी हो चुकी हैं और यह बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं समझता हूं कि आज हम सुनेंगे कि Waterman of India जो बात बताएंगे। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में वाटर बॉडीज का बहुत रोल है और इन क्षेत्रों में अगर वाटर बॉडीज ठीक तरह से बन गईं, तो इससे जल स्तर भी ऊपर उठेगा और हमें सिंचाई एवं अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां लिफ्ट इरीगेशन का ताल्लुक है वह ग्राम पंचायत विशा के अन्तर्गत सैंज से कसौली जो 95,00,000/-रुपये की नाबार्ड की स्कीम है। दूसरी महत्वपूर्ण स्कीम नौहरा-कुरगल-टकराना की है जो 3,30,00,000/-रुपये की स्कीम है।

27.03.2018/1455/जेके/डीसी/1

डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिलः------जारी-------

इसके टेंडर होने ही वाले हैं। सकोड़ी की भी ऐसी ही लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, जो कि 4 करोड़ 23 लाख रूपए की है, इसके भी पूरे पेपर्ज़ तैयार हो चुके हैं और इसमें भी जल्दी से काम शुरू किया जाए। छोटी-छोटी योजनाएं हैं जिनमें काम बहुत चल रहा है। मेरा मानना है कि हम इस दिशा में अपने बच्चों को भी लें, क्योंकि it is a challenge. यह चुनौती भरा काम है। इसमें स्कूलों को, संस्थाओं को और ऑफिसिज़ को, मैं तो समझता हूं कि चाहे वह प्रोग्राम 26 जनवरी का हो, 15 अगस्त का हो, हिमाचल डे हो, हम एक संकल्प जरूर लें, जिससे बच्चे पानी की ओर ध्यान दें। आम जनता पानी पर ध्यान दें कि हम पानी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। They normally keep the tap flowing and when they feel they push it off. ऐसे ही धीरे-धीरे करने से मैं समझता हूं कि इस

तरह अच्छा काम होगा। दूसरी बात बताना चाहता हूं ऑलटरनेटिवज़, मैं जानता हूं कि डी0सी0 सोलन, श्री राकेश कंवर के साथ हमने एक स्कीम बनाई थी कि मान लो बहुत ही सूखा पड़ जाए तब हम क्या करेंगे? कौन-कौन से क्षेत्रों में पानी की सम्भावना है, उन्हें चिन्हित किया गया। ऐसी प्रॉब्लम हो तो हमें कभी-कभी सेना के इंजीनियर्ज़ से भी इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, उनके पास अपनी मशीनरी होती है। इस तरह से हमें बहुत से ऑल्टरनेटिव्ज़ भी देखने होंगे। यह सूखा जो आप देख रहे हैं, न बर्फ पड़ी है, न बारिशें इतनी ज्यादा हुई है उस ओर भी हम ध्यान दें। मैं, इन सुझावों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

27.03.2018/1455/जेके/डीसी/2

अध्यक्षः श्री राकेश सिंघा जी।

श्री राकेश सिंघाः अध्यक्ष महोदय, मैं इस चर्चा में शामिल होता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि यह पानी का मसला ऐसा है जो इस दफ़ा हाहाकार ही नहीं मचाएगा बल्कि यह माहौल को गर्म रखने वाला भी है इसलिए मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इस मसले को प्राथमिकता पर और बहुत ही गम्भीरता से लेने की जरूरत है। आमतौर पर खाद्यान्न वस्तुओं की कमी से भूखमरी होती है लेकिन मैं समझता हूं कि आज हालात प्रदेश में ऐसे हैं कि पानी की कमी से डीहाइड्रेशन की वज़ह से मृत्यु हो सकती है इसीलिए इसे बहुत ही गम्भीरता से लेना है। मैं यह भी समझता हूं कि आपकी सरकार की आदत किसी भी चीज को बहुत खूबसूरत बनाकर पेश करने की है। अच्छी बात है। यह मार्केटिंग का युग है, लेकिन हमें हकीकत भी समझनी है। आपने जो बजट में कहा है मुझे आज भी ऐसा अहसास होता है कि ये कुछ फिगर्ज़ मेग्निफाइड हैं, ये फिगर्ज़ exaggerated हैं। आज 90 फीसदी हाउस होल्ड के पास पानी नहीं है। यह बात सही है कि बहुत सी स्कीमें हमारी बन जाती है उसमें हम शो करते हैं कि सारे हाउस होल्ड उस स्कीम में कवर्ड है लेकिन आज भी आपके सामने महेन्द्र सिंह जी मैं तथ्य ला सकता हूं कि बहुत सी पानी की स्कीमें जो घर तक

पहुंचनी थी, वह आज भी दलितों के घरों तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप स्कीम देखें वह हर हाउस होल्ड को कवर करती है। यह हकीकत है। आप छानबीन कर लें और मैं तथ्य लाऊंगा। बहुत से ऐसे आज भी हाउस होल्ड हैं जो पानी से वंचित हैं लेकिन शो किया है कि वह कवर्ड हैं। इसलिए यह भी कार्य हमें पूरा करना चाहिए। यही नहीं यह जो कह रहें हैं कि 24x7, मैं नहीं समझता कि यह सम्भव है। कौन सी पायलट स्कीम आप चलाना चाहते हैं? मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन यदि हफ्ते में भी एक दफा पानी मिल जाए तो मैं समझूंगा कि देहात के लोग आपके शुक्रगुज़ार होंगे, आपको दुहाई देंगे लेकिन एक हफ्ते में भी आज पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है।

27.03.2018/1500/SS-DC/1

श्री राकेश सिंघा क्रमागतः

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे समय दें तो एक-एक स्कीम को मैं आपके पास लाना चाहता हूं और कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं जो हमें मदद दे सकती है और इस पानी के मसले को थोड़ा बेहतर बना सकती है। पहली बात तो मैं समझता हूं कि ये जो रेशनलाईजेशन है यह सैंक्शंड पोस्ट का करने की ज़रूरत है। स्कीमें कई हो गईं लेकिन जो हमारे पास सैंक्शंड पोस्टस हैं वे दस साल पहले के हैं। नई स्कीम आ गई, आप विभाग से पता करें, वे कहते हैं कि आपकी तो पानी की सारी पोस्टें हैं लेकिन वे कब की बात कर रहे हैं आज से दस या पंद्रह साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे-जैसे न्यू स्कीम आती थी तो न्यू सैंक्शंड पोस्टस आनी चाहिए थीं लेकिन हमने उलटा कर दिया। डाइंग काडर तय कर दिया। जैसे-जैसे रिटायर, वे सब डाइंग काडर में कर दिया तो मुझे बताएं कि यह कहां सम्भव है और हालात क्या हो गए कि जो हमने आज़ादी के बाद असैट्स पैदा किये वह एक-एक असैट्स आज खत्म हो रहा है। बर्बाद हो रहा है और उसकी परवाह किसी को नहीं है। चोरियां हो रही हैं, पम्प उड़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं और उडेंगे जब हमारे पास एक चौकीदार को रखने का प्रावधान नहीं है जहां पर हमारा पम्प हाउस चलता है। तो पहला कार्य यह करना है। अगर इसको नहीं कर पायेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम पानी को बेहतर बना सकते हैं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक हम सैक्टोरल टैंकस का निर्माण नहीं करेंगे तो पानी का दोहन नहीं किया जा सकता है। सोर्स से डायरैक्ट अगर हम घर में पानी पहुंचाना चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है। उसके लिए जितने भी रिसोर्सिज़ हमारे पास हैं, 14वें वित्तायोग में हैं, मनरेगा के अंदर हैं सब को अगर हम पूल कर दें तो अच्छे सैक्टोरल टैंकस बन सकते हैं। जो स्टोर भी कर सकते हैं और सप्लाई का भी काम कर सकते हैं। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

तीसरा सुझाव मेरा यह है कि किसी और सदस्य ने भी कहा कि जब भी हमारा पम्प हाउस बनाया जाता है, उठाऊ पानी की योजना बनाई जाती है तो सड़क का कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसलिए वह बन तो गया, उसकी कॉस्ट भी ज्यादा बनी क्योंकि आपको सारा मैटीरियल पीठ पर ढोना पड़ा और आज जब पम्प टूट जाता है या खराब हो जाता है, आपका ट्रांसफार्मर बैठ जाता है तो

27.03.2018/1500/SS-DC/2

उसको पहुंचाने के लिए भी बहुत पैसा लगता है। --(व्यवधान)-- उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ दो मिनट दीजिए।

चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास पम्प ऑपरेटर के रहने के लिए जगह नहीं है। एक छोटी-सी कुटिया अगर हम बना दें तो उसके लिए फायदा होगा और वह मशीनरी भी बच सकती है। चोरों से भी हम बच सकते हैं।

पांचवीं बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रभावशाली लोगों ने मेन पाइप सप्लाई से कनैक्शन लिया है इसको बंद कीजिए चाहे वह पैसे वाला हो या प्रभावशाली हो या जो मर्जी हो। उन्होंने राइजिंग मेन से कनैक्शन लिया है मुझे बताएं तो बाकियों को कैसे पानी मिलेगा, यह सम्भव नहीं है।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जो ज़िक्र किया है उसमें सिर्फ अभी दस फीसदी काम हुआ है। जो नन्द लाल जी ने कहा है अभी तक उस पानी की स्कीम की जो मतियाना-सैंज-कुमारसैन के नाम से जानी जाती है जिसको कूटपट्ट खड्ड कह रहे हैं उसकी दो सोर्स से फंडिंग है। एक नाबार्ड से है और दूसरा नेशनल

रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम से फंडिड है। आपसे मैं विनती करना चाहता हूं कि ये ऐसी कुछ स्कीम्ज़ हैं और आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी स्कीम हो, सिर्फ मैं अपने चुनाव क्षेत्र की बात नहीं कह रहा हूं, जो मेज़र हमारी स्कीम्ज़ हैं अगर आप उसको फंड करेंगे, वह आज ब्रिक्स से हो सकती है, तो हम उसे पूरा करेंगे। जो उसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ जायेगा तो उसको हम कम कर सकते हैं। फंड की वजह से कोई भी पानी की स्कीम कहीं भी हिमाचल प्रदेश में है वह मरनी नहीं चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मैन ऑफ ऐक्शन हैं इसलिए मैं समझता हूं कि इसको आप गम्भीरता से लेंगे और इस पानी के मसले को हल करेंगे। अगर आधा घंटा आप कहीं मुझे देंगे तो मैं एक-एक स्कीम जो मेरे चुनाव क्षेत्र की है उस पर चर्चा करूंगा। जो कमियां हैं उनको भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं जो आपने मुझे यहां बोलने के लिए समय दिया।

27.03.2018/1505/केएस/एचके/1

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में श्री पवन कुमार काजल जी भाग लेंगे।

श्री पवन कुमार काजलः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मांग संख्या-13 सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के तहत चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आप डाइनैमिक भी हैं और जब से आप प्रदेश के आई.पी.एच. मिनिस्टर बने हैं, सभी को काफी उम्मीदे हैं कि अगर आई.पी.एच. का सुधार आपके समय में नहीं हुआ तो कभी नहीं हो सकता। क्योंकि समय कम है इसलिए मैं सीधे अपने विधान सभा क्षेत्र की तरफ जाना चाहूंगा। इरिगेशन की आज से 20 वर्ष पहले जितनी भी स्कीमें बनी थी, वे ठप्प पड़ी हैं। उसमें से गलियां- ठाकुरद्वारा, दौलतपुर-जलाड़ी, वैदी-बडियारा स्कीम, सनौरा-सरांगड़ी स्कीम, तरखांकर-सलोण स्कीम, देरियां-समीरपुर स्कीम, इनमें करोड़ों रुपयों का जो खर्च हुआ है, वह पूरी तरह डिफंक्ट है। इसको बनाने वाले कौन से अधिकारी थे? हम जब गांव में जाते हैं तो हमें शर्म लगती है। ये जो करोड़ों रुपये की बड़ी-

बड़ी पाइपें वहां पर लगी हैं, लोग हमसे पूछते हैं लेकिन हम क्या जवाब दें कि विभाग ने जो बड़ी-बड़ी पाइपें डाली हैं, ये ऐसी ही होती हैं इनमें पानी नहीं है? तो आज चिन्तन करने की जरूरत है। एक तो जहां पर इरिगेशन की स्कीम कामयाब नहीं हो रही है, वहां पर सोर्स नहीं है तो हम बना क्यों रहे हैं? अगर 18 या 20 करोड़ रुपये की इरिगेशन की स्कीम बजट में आ गई, अगर उसमें सोर्स नहीं है, पानी नहीं है तो हम पाइपें क्यों खरीद रहे हैं? हम उसके लिए टैंक क्यों बना रहे हैं? इस बारे में चिन्ता करने की जरूरत है।

इसी तरह जो वाटर सप्लाई की स्कीम थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र के जितने भी टैंक हैं, एक दो टैंक को छोड़कर अगर बाकियों में पानी डालें तो उनमें रिसाव शुरू हो जाता है। अगर 50 हजार लीटर केपेसिटी का टैंक नया बना है तो रिपेयर कर कर के वह 25 हजार लीटर का रह गया है। 25 हजार भी अगर उसमें पानी टिक जाए तो जनता को लाभ होगा । हमारे कांगड़ा जिला में ज्यादातर हैंडपम्प कामयाब हैं नहीं तो वहां पर त्राहि-त्राहि हो जाती। इतना बड़ा विभाग है, इतने बड़े ऑफिसर्ज़ हैं, हम जनता को क्या बालें?

27.03.2018/1505/केएस/एचके/2

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पिछले डेढ़ साल पहले नाबार्ड के अंतर्गत मेरे कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की दो स्कीमें स्वीकृत हुई। एक 18 करोड़ 70 लाख की और एक चंगर में 8 करोड़ 70 लाख रुपये की स्कीम है। जब नाबार्ड से कोई स्कीम सैंक्शन होती है तो उसको पहले साल में 20 प्रतिशत पैसा मिलता है, दूसरे साल 40 प्रतिशत और तीसरे साल 40 प्रतिशत पैसा मिलता है ताकि उस स्कीम को शुरू किया जाए परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 18 करोड़ 70 लाख की जो मेरी स्कीम है, उसमें कोई भी बजट नहीं है। 8 करोड़ 70 लाख की जो यह स्कीम है उसके लिए 10-11 लाख रुपये हैं तो नाबार्ड जो सेंक्शन करता है तो पैसा गया कहां? इस बारे में भी आपसे उत्तर चाहूंगा। हमारे जिला कांगड़ा में अधिकतर हैंड पम्प लगते हैं। डिपार्टमैंट भी वहां पर हैंडपम्प लगाता है और जो प्रभावशाली लोग है, पैसे वाले आदमी हैं, वे भी हैंड

पम्प लगाते हैं तो उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा कि अगर जिसके पास पैसे हैं, वह तो हैंड पम्प लगा देता है लेकिन विभाग ऐसा करें कि जो भी हैंडपम्प लगाए

27.3.2018/1510/av/hk/1

श्री पवन कुमार काजल .....जारी

उसके लिए विभाग से एन0ओ0सी0 लेना पड़े। कई जगह एक हैण्ड पम्प से 25-30 परिवारों को पानी मिल रहा है और दूसरी जगह एक प्रभावशाली व्यक्ति एक घर के लिए हैण्ड पम्प लगा रहा है तथा उस पानी को अपने खेतों में पहुंचा रहा है। इसलिए अगर विभाग की तरफ से इसके लिए एन0ओ0सी0 की कण्डिशन रख दी जाए तो अच्छा रहेगा। मंत्री जी, मैं भुगतभोगी हूं और मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कांगड़ा विधान सभा क्षेत्र की स्कीमों का बेड़ा गर्क कैसे हुआ। मैं वहां से दूसरी बार जीता हूं, इससे पहले क्या होता था कि कभी शाहपुर से मंत्री बनते तो कभी नगरोटा से मंत्री बन जाते थे और कभी कहीं के मंत्री बन जानें। कांगड़ा का कोई-कोई मंत्री होता था और उसको बेचारे को पता ही नहीं लगता था। शाहपुर के ठेकेदार भी कांगड़ा और नगरोटा के भी कांगड़ा भेज दिए जाते थे कि बेड़ा गर्क करना है तो कांगड़ा जाओ। अगर आपने टैंक बनाना है तो कांगड़ा जाओ, अगर किसी ने पाइप लाइन डालनी है तो कांगड़ा जाओ; ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए कृपया आप कांगड़ा की स्कीमों को चैक करें। वहां पर जितने भी टैंक हैं उनमें किसी में भी पानी नहीं है। आप जब नये-नये मंत्री बनें तो आपने पूरा सफाई अभियान शुरू किया कि पानी के टैंकों को साफ कीजिए। आप इस बात को सुनिश्चित भी कीजिए कि पूरे प्रदेश में आपके कहने पर पानी के टैंकों की सफाई हुई या नहीं हुई। मैंने यहां पर अपनी व्यथा बता दी है और मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी सिंचाई की स्कीमें हैं वे सारी-की-सारी फेल है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वहां पर स्टाफ की कमी है। आई0पी0एच0 विभाग का जो थोड़ा बहुत बेड़ा गर्क करने को बचा है वे वहां पर आउट-सोर्स पर रखे हुए कर्मचारी कर देंगे। उन आउट-सोर्स पर रखे गए कर्मचारियों के मन में पीड़ा नहीं है जो कि एक विभाग से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के मन में अपने विभाग के प्रति चिन्ता होती है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी यहां पर कहा कि आउट-सोर्स पर 10 व्यक्तियों की पेमैंट जाती है

और वहां केवल 3-4 व्यक्ति ही लगाये होते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि हमें मंत्री जी से बड़ी उम्मीदें हैं। आप पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण पैदा करें कि सबको स्वच्छ पानी मिले। हम सिंचाई की स्कीमों से हटकर पहले पीने के पानी की स्कीमों के बारे में ज्यादा सोचें।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

27.3.2018/1510/av/hk/2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि मुझे मांग संख्या : 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई पर बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहां पर माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी भी उपस्थित हैं।

मैं यहां पर अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ बातें रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी की पूर्व सरकार द्वारा वैसे तो मुख्य रूप से एक पेयजल स्कीम शिमला ग्रामीण को दी गई है। इस स्कीम का नाम ग्रो-गंढल स्कीम है और इसकी लागत 105 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के माध्यम से तकरीबन 45 पंचायतों को पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन कई गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर इस स्कीम से पानी नहीं पहुंच पाया है। हमने इसको एम0एल0ए0 प्रायोरिटी में डाला है मगर कुछ एरिया जो इसके अंतर्गत कवर नहीं हो पायेंगे उनको भी प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। क्षेत्र के लोगों को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा सके और उसके लिए मैं समझता हूं कि यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमारे बजट अनुमान यहां पर पेश किए गए हैं उसमें यह बात रखी गई है कि किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करना है। उस आय को दोगुना कैसे करना है उसके लिए मैं समझता हूं कि सिंचाई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने इस बारे में बजट के बारे में हो रही चर्चा के दौरान भी चिन्ताए व्यक्त की थी और मैं उसको आज फिर से दोहरा रहा हूं। यहां पर जो सोलर पम्पिंग की बात की गई थी या जो यहां पर इरिगेशन के माध्यम से एक नई स्कीम शुरू करवाई गई है उसको आने वाले समय में किस तरह से

इम्पलीमैंट करवाया जाना चाहिए उसके बारे में अभी भी कोई रूप-रेखा तैयार नहीं हो पाई है।

27.03.2018/1515/TCV/YK-1

श्री विक्रमादित्य सिंह..... जारी।

इसको आने वाले समय में निश्चित तौर पर बड़े गम्भीरतापूर्वक देखने की आवश्यकता है। हमारी एक बस्ती-गुनाणा From शपड़ी-का-घराट स्कीम है जो पिछले 10 साल से लम्बित पड़ी हुई है। ये एक ही स्कीम है, जिसके बारे में मैं यहां उल्लेख कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात माननीय मंत्री जी को भी कहना चाहूंगा कि अधिकतर स्कीमों के बारे में हमें यह सुनने को मिलता है कि पानी की कोई कमी नहीं है या जो सोर्स है, वहां से पानी में कोई कमी नहीं है। It is because of the faulty implementation or कहूलों या पाइपों की एनुअल मैंटेनेंस नहीं हो रही है, उसके कारण पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन चीजों को देखने की आवश्यकता है। नये प्रोजैक्ट्स को लाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसकी इम्प्लीमैंटेशन और एनुअल मैंटेनेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको देखने की भी जरूरत है।

एक बड़े दुःख और हैरानी की बात है कि आज से तकरीबन 15 साल पहले 2002 में भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक सीवरेज सिस्टम का सुन्नी के अंदर शिलान्यास किया था। उसमें डेढ़ करोड़ रुपये बजट का प्रावधान भी उस समय हो चुका था। लेकिन इसका टैंडर लग जाने के बावजूद भी आज तक उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। ये भी कहा जा रहा है कि टूरिज्जम प्वाईंट ऑफ व्यू से उस क्षेत्र को डेवैल्प करना है। ये एरिया नगर परिषद् के अंदर आता है। अगर सरकार वहां पर लोगों को सीवरेज लाईन उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको हमें गम्भीरतापूर्वक देखने की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक के माध्यम से 800 करोड़ रुपये की योजना द्वारा शिमला के

लिए पानी लाने का प्रावधान किया गया है। मगर एक कहावत है- दीपक तले अंधेरा । मैं समझता हूं कि वैसा ही हाल सुन्नी का है। सुन्नी से ये पानी कोलडैम से शिमला के लिए लाया जा रहा है। लेकिन सुन्नी शहर के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं करवाया गया है। अभी जो

27.03.2018/1515/TCV/YK-2

मैंने 105 करोड़ रुपये की स्कीम की बात की है, उसमें भी सुन्नी शहर का कोई जिक्र नहीं है। जहां से पूरे शिमला के लिए आप पानी का प्रावधान करवाने का प्रयास कर रहे हैं, अगर उसी शहर को वहां से पानी नहीं मिलेगा, तो मैं समझता हूं कि this is something that needs to be looked upon. इसके साथ ही हमारा टुटू का इलाका है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 4 वार्ड नगर निगम के भी आते है। वहां पर भी सीवरेज का फाउंडेशन स्टोन 2015 में रखा गया, जिसमें अभी तक केवल 800 मीटर की पाइपें बिछी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें शिमला जिला के लोग ही नहीं रहते है इसमें पूरे प्रदेश से कर्मचारी व अन्य लोग रहते हैं। इसलिए इसको शिमला के नजरिये से न देखकर इसको प्रायोरिटी पर करवाने की जरूरत है। इसमें अभी जो पाइपें बिछनी है, वह लगभग 5.6 किलोमीटर है। यहां पर लाडा के बारे में बहुत बातें हुई है। अभी पूर्व में हमारे जन जातीय क्षेत्र के विधायक (श्री जगत सिंह नेगी) ने भी इस विषय को उठाया कि वहां पर विधायक इसका चेयरमैन बनना चाहिए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 बड़े पॉवर प्रोजैक्ट्स बन रहे हैं। एक सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा बनाया जा रहा है और दूसरा कोलडैम का प्रोजैक्ट है। इसमें किस तरह से यह पैसा स्थानीय क्षेत्र में लगना है, इसकी अभी तक कोई रूपरेखा तय नहीं हो पाई है। ये बात अलग है कि हम किसी चेयरमैन या किसी एम0डी0 को फोन कर देते हैं तो वे एकाध व्यक्ति को उनमें एडजैस्ट कर देते हैं। लेकिन मैं समझता कि इसमें 'लाडा अथॉरिटी' को बनाने की आवश्यकता है। अभी मैं कंसर्ड विधायक हूं और आने वाले समय में जो भी विधायक होगा उसको उसका चेयरमैन बनाया जाये।

27-03-2018/1520/NS/YK/1

श्री विक्रमादित्य सिंह ------जारी

ताकि जो कन्सर्न्ड एरियाज़ हैं, उन लोगों को आने वाले समय में फायदा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा और यह बहुत जरूरी है। मेरे क्षेत्र की तीन पंचायतें शिमला के साथ लगती हैं, इसलिए यह ज्यादा बैकवर्ड नहीं है। लेकिन छः पंचायतें सिराज क्षेत्र की आती हैं और यही क्षेत्र है जहां पर होर्टिकल्चरल एक्टिविटी करवायी जाती हैं। हमने यहां पर कैसे बागवानी के साथ होर्टिकल्चरल को बढ़ावा देना है, यह भी बड़ा गम्भीर मुद्दा है। निश्चित तौर पर, इस एरिया के लिए पीने के पानी के लिए कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्य मंत्री द्वारा तकरीबन एक लिफ्ट पंदोआ drinking water supply scheme के मारफ़त वहां पर पीने के पानी का प्रावधान करवाया गया है। अभी तक इसका 90 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। मगर वहां पर हमने इरिगेशन के माध्यम से कैसे उस क्षेत्र को आगे ले करके जाना है that is very important question? मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन रहेगा कि वे इस तरफ ध्यान दें। क्योंकि यही क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, जहां पर सेब, नाशपती आदि फलों की पैदावार होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायतें चनोग और चनाबग हैं, इन दोनों क्षेत्रों में टमाटर और खीरे की बहुत ज्यादा उपज़ होती है। मुख्य रूप से शिमला में जितनी सब्ज़ी आती है, वह इन्हीं क्षेत्रों से आती है। यहां पर दो इरीगेशन स्कीमें बड़े लम्बे समय से पैंडिंग पड़ी हुई हैं। इसमें एक चनोग सुज़ाना इरीगेशन स्कीम है, जो पिछले 25 सालों से पैंडिंग पड़ी हुई है। इसमें नई पाइपें लगनी हैं। इसकी कूहलें भी बहुत डैमेज़ हो गई हैं। यहां टमाटर और खीरे की बहुत ज्यादा उपज़ होती है। इसलिए आने वाले समय में इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मेरा आपसे इसके लिए निवेदन रहेगा। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी ग्राम पंचायत चनावग में सैंज चनावग स्कीम है, जो लगभग 105 करोड़ रुपये की राशि की लागत से वंचित रह गई थी और इसके लिए ऐस्टिमेटिड 40 लाख रुपये की राशि का Budgetary प्रोवीज़न विभाग द्वारा होना है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इसको जल्दी-से-जल्दी पूरा करवाया जाये ताकि वहां के लोगों को पीने के पानी का प्रावधान हो सके। एक क्षेत्र बठमाणा जाबरी है, जो धामी के नीचे का

इलाका है और वहां पर इरीगेशन स्कीम धलाया के लिए प्रपोज़ड है, जिसमें पम्प हाउस फंक्शनल नहीं है। इसके बारे में पूर्व में

27-03-2018/1520/NS/YK/2

भी वक्ताओं ने बात रखी थी। कई जगहों पर पम्प हाउस बने हुए हैं मगर उनकी मैंटेनैंस नहीं हो रही है और वे खराब हैं। कई जगहों पर नई मशीनें लगनी हैं और कई जगहों पर प्राईवेट के माध्यम से भी पम्प हाउस चलाये जा रहे हैं। इसको भी गम्भीरतापूर्वक देखने की आवश्यकता है। मेरी इसी पंचायत की लिफ्ट इरीगेशन स्कीम धलाया, सलोण और बनोण है, इसमें भी Budgetary प्रोवीज़न और 6,000 लीटर का टैंक बनाने की आवश्यकता है। अभी तक इसमें केवल 1500 लीटर की कैपेस्टिी का टैंक है और आने वाले समय में इसको भी देखने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप जल्दी से इसको पूरा करवायें ताकि आने वाले समय में हम प्राथमिकता में इन मुद्दों को उठायें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

27-03-2018/1520/NS/YK/3

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर चर्चा में भाग लेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कटौती प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय से अपने क्षेत्र कुल्लू के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगा। मैं अपने ज़िले के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, कुल्लू में ब्यास नदी बह रही है और ग्लेशियर फैड पूरी की पूरी रिवर है। वहां पर इसका बहाव बहुत बढ़िया है और यह बहुत ही शांत नदी है। इसमें कई चैनल हैं और यह पूरे इलाके को फीड कर रही है और यह नदी आगे जा करके मण्डी के क्षेत्र से हो करके गुजरती है।

27.03.2018/1525/RKS/ए.जी.-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर... जारी

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान सर्वप्रथम इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि कुल्लू के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना ब्यास नदी के तटीयकरण के लिए बनाई गई थी। इसमें पलचान से लेकर औट तक चार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कवर होते हैं। इसके लिए लगभग 1100 करोड़ रुपये के बजट का अनुमान था। हमें यह पता चला कि इस योजना की डी.पी.आर्ज. केंद्र सरकार के पास गई है। क्योंकि केंद्र सरकार ने सारे-का-सारा बजट गंगा की सफाई के लिए डाइवर्ट कर दिया और उसके लिए एक अलग से मंत्रालय भी बनाया गया है। गंगा की सफाई के चक्कर में कुल्लू की सफाई भी हो गई। माननीय मंत्री जी आप स्वयं कुल्लू /मनाली के वासी भी हैं और आप इस परियोजना के बारे में जरूर विचार करें। सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री जी के बारे में एक बात कही है कि वे ग्रास रूट में उतर कर काम करते हैं। एक-एक बात को गहनता से छानबीन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जितनी योजनाएं/परियोजनाएं बन रही हैं, चाहे वे सीवेरेज की हों, उठाऊ पेयजल की हों या फ्लो इरिगेशन की हों। कुछ भी हो, ग्रेविटी में हो, फ्लो में हो, इरिगेशन की हो, पीने के पानी की हो लेकिन जितनी भी योजनाएं आज तक बनी हैं, वे टेबलों पर बैठकर बनी हैं। पूर्व में किसने क्या किया, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पूर्व में कई सरकारें रही। मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में भी बहुत-सी योजनाएं हैं। मणिकर्ण घाटी में दो योजनाएं हैं और मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आप कृपया इन योजनाओं की ओर ध्यान दें। टील-शांगचन-वराधा योजना वर्ष 2007-08 में बनी थी। इस योजना का आगे का काम तो हो गया है परन्तु इसको सोर्स से नहीं जोड़ा गया है। इसका सोर्स सूख गया है। वही हाल Chinjra-Flati Scheme का है। वहां पर भी आगे का काम तो हो गया है परन्तु सोर्स से नहीं जोड़ा गया है। अब नये सोर्स ढूंढे जा रहे हैं ताकि इन स्कीम्ज को आगे बढ़ाया जाए। मैं तटीयकरण की बात पर फिर से आना

चाहूंगा। तटीयकरण जब होगा तो उससे लैंड रिक्लेम होगी। जितना बजट तटीयकरण के लिए आएगा, उससे उस लैंड की वैल्यू भी बढ़ेगी। उस लैंड में आप पार्किंग, रोड्स या घाट बना सकते हैं। मैं यह नहीं

27.03.2018/1525/RKS/ए.जी.-2

कहता कि यह टूरिज्म डिपार्टमैंट का काम है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म डिपार्टमैंट को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता है। जबकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश है। मैंने केरला में देखा वहां पर टूरिज्म विभाग तो अपना काम करता ही है परन्तु फोरैस्ट डिपार्टमैंट भी टूरिज्म का काम करता है। मैं चाहूंगा कि जब आप तटीयकरण की योजना बनाएं तो वहां पर सुंदर घाट भी बनाए जाएं। आप अच्छे-अच्छे संगम स्थल, जैसे ब्यास-पार्वती का है, वैसे-वैसे स्थान विकसित कीजिए। वहां पर आप पार्क्स बनाइए। इन सब चीजों को योजनाओं के साथ जोड़ना चाहिए। सीवरेज की जहां तक बात है, उसमें मैंने अपनी प्राथमिकताएं दी हैं। कुल्लू और भुंतर शहर के बीच रामशीला से लेकर बजौरा तक एक heavily populated area है या आप इसे नगवाईं तक ले लो। वहां पर सीवरेज का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैंने इसको अपनी प्राथमिकता में डाला है। जब भी सीवरेज की पाइप डाली जाए उसके सर्वे से पहले ग्राम पंचायत के प्रधानों को और जिन-जिन की जमीने वहां पर आती है, उनको बुलाया जाए और उनसे एफिडैविट्स पहले लिए जाएं। ताकि जब स्कीम्ज बनकर तैयार हो जाती है तो उसके बाद ज़मीन वाले रोड़ा न अटकाएं। माननीय मंत्री जी मैं आपका ध्यान कुछ स्कीमों की और दिलाना चाहूंगा। 'Hathithan-Seund-Kahudhar' कृपया आप इस योजना की ओर भी ध्यान दें। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ योजनाएं लिफ्ट इरिगेशन स्कीम की बनीं हैं

27.03.2018/1530/बी0एस0/डी0सी0-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर .....जारी

उन्होंने स्टोरेज़ टैंक तक तो पानी लिफ्ट कर दिया, लेकिन उसके आगे किस तरह पानी खेतों में जाएगा, स्कीम में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैंने उनसे पूछा कि आपने इसे क्यों पूरा नहीं किया, क्या स्टोर टैंक से आगे लोग खेतों तक पानी बाल्टियों में ले जाएंगे? उन्होंने यह कहा कि जी स्कीम का प्राक्कलन ही इतना ज्यादा हो रहा था कि हम अभी स्टोर टैंक से आगे कार्य नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आया कि यह किस तरह की बाते कर रहे हैं। मैं खास तौर से मंत्री जी का ध्यान कुल्लू, बल्याणी, भूंमफिर और बड़ा गावं की ओर दिलाना चाहता हूं यहां पर यह सारा कार्य होना है। बाकी हमारे वहां पर कुछेक ऐसी स्कीमें है, जो पुरानी कुल्हें थीं रेवेन्यू में वे कुल्हें हैं। खास तौर पर जो हमारे नीचले क्षेत्र हैं जैसे महौल, समसी और भूंतर इसमें कुल्हें चलती थी। आज के दिन में उन कुल्हों पर अति क्रमण हो गया है। मैं उस पंचायत का काफी सयम पहले प्रतिनिधि रहा हूं। उस वक्त हमने पंचायत के माध्यम से एक कोशिश की थी और वह कुल्ह डोभा नाम की है। पांच-छः पंचायतों को वह कुल्ह पानी देती है। हमने खुद उस कुल्ह को बनाया था और पूरे क्षेत्र की लाईफ लाइन वह कुल्ह थी, उसे चालू किया था। आज क्योंकि रिवर बैड डाउन हो गया है , मैने उस कुल्ह को भी प्राथमिकता में डाला है। कृपया मैं आपका इसके लिए भी ध्यान चाहूंगा। बाकी समय-समय पर जब भी हमारी विधान सभा होगी मैं अन्य समस्याओं से भी अवगत करवाता रहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय पूर्व मुख्य मंत्री आदरणी वीरभद्र सिंह जी का इन्होंने अपनी सरकार के समय में एक ग्रेविटी स्कीम 24X7 दी, जो कुल्लू में संभव है। हमने एक नाले को टैप किया वहां से उसको लिया, क्योंकि उसके पीछे एक पावर प्रोजैक्ट है उसमें गाद की भी समस्या नहीं है। वहां कुल्लू शहर के लिए बहुत अच्छा पानी आ रहा है। लेकिन उसमें अभी देरी चल रही है। विभाग लापरवाही बरत रहा है। अभी यह स्कीम चालू हो जानी चाहिए थी। इसके ऊपर मैं चाहूंगा आप इस पर ध्यान देंगे। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कुल्लू के सामने खराल का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखा सबसे ज्यादा रहता है। कुल्लू में एक ही जगह है जहां पर कि गर्मियों में पानी के टैंकर लगाए जाते हैं

27.03.2018/1530/बी0एस0/डी0सी0-2

वह खराहल क्षेत्र है। वहां पर पिछले साल माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने उस क्षेत्र के लिए दो पानी की स्कीमें एक सिंचाई की और एक पीने के पानी की स्कीम दी । उसमें दूसरी स्टेज में काम होना है। बिजली महादेव के जो गांव है वे अभी भी प्यासे हैं। उस तरफ भी प्यासे हैं इस तरफ भी प्यासे हैं। नीचे व्यास में पानी बह रहा है। कृपया आप इस पर भी थोड़ा गौर करें और आगे बढ़ें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

27.03.2018/1530/बी0एस0/डी0सी0-3

उपाध्यक्षः अब चर्चा में श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे ।

श्री आशीष बुटेल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या-13 सिंचाई जलापूर्ति एवं सफाई, में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र से पहली बार विधायक चुनकर आया हूं। पहली बार प्लानिंग की मिटिंग में हिस्सा लेने के लिए मुझे मौका मिला था । उसमें एक बात जो सामने आई थी और जिसका जिक्र मैंने वहां भी किया था कि कई जगह एम.एल.ए. प्राथमिकता 2011 से ले करके अभी तक वहां स्लाईड चली थी, जिसके अन्दर यह दर्शाया गया था कि जो एम.एल.ए. की प्राथमिकता में डी.पी.आर. गई हैं, मानलीजिए वे 10 स्कीमें हैं, लेकिन उन में से मात्र 5 की ही डी.पी.आर. तैयार हुई हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने विभाग में यह आदेश करें, अपने अधिकारियां को आदेश करें कि हर स्कीम की चाहे वह आगे जाकर रिजेक्ट हो जाए परंतु जब कोई एम.एल.ए. अपनी प्राथमिकता में स्कीम देता है तो उसकी डी.पी.आर. तो कम से कम तैयार हों। मुझे बहुत हैरानी हुई कि 2011 की डी.पी.आर. जब

कोई एम.एल.ए. और थे, तब उन्होंने अपनी प्राथमिकता में स्कीम डाली थी उसकी डी.पी.आर. भी आज तक तैयार नहीं हुई।

27-03-2018/1535/DT/DC/1

श्री आशीष बुटेल -----जारी।

मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इसको जल्दी तैयार करवाया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि पीने वाले पानी की शोर्टेज़ हो सकती है और कूहलों में पानी की कमी हो सकती है। लेकिन सोर्सिज़ में कोई कमी नहीं है। इनको सिर्फ टैप करने की जरूरत है। कूहलें हमारी एग्रीकल्चर की और हमारी इकोनोमी की लाईफ लाइन हैं। मैं, मंत्री महोदय आपसे यह ज़िक्र करना चाहूंगा कि मैंने अभी हाल ही में यह देखा कि "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" में भी हमारी कुछ कूहलें आई हैं या किसी अन्य स्कीम के अंदर ये कूहलें आई हैं और आपके विभाग ने इन पर ऑनलाइन टैंडर का सिस्टम शुरू किया है। यह बहुत अच्छी बात है। आप 'ए' क्लास ठेकेदारों को टैंडर देते हैं। लेकिन आपने उसमें यह कहा है कि हर कंपोनैंट के लिए सिर्फ एक ही ठेकेदार होगा। अगर मशीनरी का कोई ठेकेदार होगा तो वह एक ही होगा जोकि जायज़ सी बात लगती है। जब डिस्ट्रिब्यूशन की बात आती है तो आपने एक ठेकेदार की जगह थोड़ी सी leniency दिखाई है और कई ठेकेदारों को काम दिया है। लेकिन 10 किलोमीटर की कूहल बनाने के लिए अगर आप एक ठेकेदार को काम देंगे तो शायद यह 10 साल में भी पूरा नहीं हो पायेगा। मैं समझता हूं कि अगर हम इसे छोटे-छोटे हिस्सों में बांट सकें तो इससे काम जल्दी होगा। उपाध्यक्ष महोदय, कूहलों का काम सीज़नल होता है। जब बारिश का मौसम होगा तो आप कूहल बंद कर सकते हैं और उस समय यह काम चल सकता है अन्यथा यह काम नहीं चल पाता है। अगर आप चाहें तो इस काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट कर एक बार देंखे और क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ न करें। इससे हमारे छोटे ठेकेदारों को भी काम मिलेगा और यह काम जल्दी भी होगा। किसानों को भी इससे सहूलियत मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, पालमपुर में कुछ हाइडल प्रोजैक्ट्स लगे हैं। इस बार बहुत सूखा पड़ने के आसार हैं। मैं हाल ही में डाढ पंचायत में दो-तीन दिन पहले गया था। वहां के लोगों का मानना है कि कूहलों का पानी बिल्कुल सूख चुका है। यह इसलिए हो रहा है कि वहां पर जो हाइडल प्रोजैक्ट्स हैं, उनको जितना पानी छोड़ना चाहिए, वे नहीं छोड़ते हैं। मैं आपके ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हूं। आप अपने अधिकारियों को इसके लिए भी निर्देश दें कि वे पूरा पानी छुड़वायें ताकि हमारे किसानों तक पानी पहुंच सके, जो हाइडल प्रोजैक्ट्स ने कमिट किया हुआ है। इसके अलावा मैं यहां पर पीने के पानी की बात करूंगा।

27-03-2018/1535/DT/DC/2

पालमपुर में पीने के पानी की शोर्टेज़ इस वज़ह से भी हो सकती है कि सोर्सिज़ टैप न हुए हों। लेकिन मैं यहा पर यह कहना चाहूंगा कि leakage is also one of the major problem. लीकेज़ जहां-जहां पर भी हो रही हैं और हम उनको वैल्ड करें तो सरकार का बहुत सारा पैसा बच जाएगा। आप 24x7 पायलट प्रोजैक्ट्स की जो बात कर रहे हैं, इसके लिए पालमपुर में कम-से-कम आपको दिक्कत नहीं आयेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी मानना है कि हर सोर्स पर फिल्टर बैड होना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में हम बात कर रहे थे कि कहीं पर हैंडपम्प के पानी की शोर्टेज़ थी। लेकिन वहां पर लाइन बिछी हुई है। वहां पर महीने में एक या दो बार जो नैचुरल सोर्सिज़ हैं, उनसे पानी आ रहा है। वहां पर एक हैंडपम्प डिग करके दिया है और हमने यह कहा कि उसी लाइन में उस हैंडपम्प के पानी को डाल दिया जाये। लेकिन गांव वालों ने इसके लिए मना कर दिया है। इसका कारण यह था कि नैचुरल सोर्स से कभी भी महीने में एक बार गलती से पानी आ जाये तो उसमें कीड़े-मकौड़े आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पानी पीने योग्य नहीं रह जाता है। यह हैंडपम्प के पानी को contaminate करता है। इसके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, पालमपुर क्षेत्र की सीवरेज़ का काम तकरीबन पालमपुर शहर में पूरा हो चुका है। इसमें सिर्फ थोड़ी-सी लागत से पूरे पालमपुर का जो म्यूनिसिपल कमेटी एरिया है, वह पूरा हो जायेगा। इसमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं एक करोड़ के अंदर ही यह काम हो जायेगा। आपके पास इसकी डिमांड भी आ चुकी है। कृपया इसे सैंक्शन करें और अपने बज़ट में लें। इसके

अलावा पालमपुर एक ऐसा शहर है, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी के अगर 5 किलोमीटर के रेडियस में आप देंखे तो वहां पर 40,000 की पोपूलेशन रहती है। अगर इस पोपूलेशन को हमें फीड करना है या कोई सुविधा देनी है, सीवरेज़ या पीने के पानी की सुविधा देनी है तो

27.03.2018/1540/SLS-HK-1

श्री आशीष बुटेल ...जारी

अगर आपके ज़रिए यह सब चीजें हम वहां पर ला सकें जिसकी डी.पी.आर. हमने आपको भेजी है। एक स्कीम बिंद नाला की है जिसके लिए यह डी.पी.आर.आपके पास आई हुई है। इसके अलावा सिवरेज की पालमपुर के एडज्वायनिंग एरियाज की भी एक डी.पी.आर. आई हुई है। इसको अगर आप भेज दें तो बहुत अच्छा होगा।

अंत में मैं एक रिक्वैस्ट और करना चाहूंगा। डिलिमिटेशन के बाद शायद पालमपुर एक ऐसा विधान सभा क्षेत्र बना जहां पर हर डिपार्टमैंट, चाहे रूरल डवलपमैंट हो, उसके ब्लॉक्स 3 हो गए - बैजनाथ, पंचरुखी और भवारना जहां हमारे लोगों को जाना पड़ता है, लोक निर्माण विभाग में देखें तो वहां बैजनाथ और पालमपुर 2 डिविजन्ज हो गईं, उनमें बंट गया और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य में भी देखें तो पालमपुर डिविजन है लेकिन वहां पर सब-डिविजन 3 हैं। जब यह सब-डिविजन अलग-अलग हो गए हैं तो उसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो हमारी आई.पी.एच. की सब-डिविजन बैजनाथ के साथ है, उसके साथ 6 पंचायतें हैं, उनको निकालकर अगर आप पालमपुर सब-डिविजन में डाल सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

27.03.2018/1540/SLS-HK-2

उपाध्यक्ष : अब मांग संख्या : 13 पर मैं लॉस्ट वक्ता के रूप में श्री सतपाल सिंह रायजादा को आमंत्रित करता हूं।

श्री सतपाल सिंह रायजादा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कुछ बातों के ऊपर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा। गर्मी का मौसम आ रहा है, और ऊना सबसे गर्म क्षेत्र माना गया है। वहां पीने के पानी की भी और सिंचाई के लिए भी पानी की बहुत किल्लत रहती है। महोदय, सबसे बड़ी समस्या लीकेज है। हम नई योजनाएं बनाते हैं जो बनती हैं लेकिन पिछली जितनी भी योजनाएं हैं उनमें अगर लीकेज बंद कर दी जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैं अपने गांव की बात बताऊंगा। मेरे गांव में ही 5-6 जगहों पर पानी लीकेज कर रहा है। हम जब विभाग को बताते हैं तो उनकी भी अपनी कई समस्याएं होती हैं, जैसे कि स्टॉफ नहीं है या यह काम ठेकेदार को दिया है। इस ढंग से यह समस्या चलती आ रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जितनी भी हमारी स्कीमें हैं, वह सब एक दिन बैठ जाएंगी। पानी की लीकेज को बंद करना बहुत ज़रूरी है।

इसके साथ-साथ महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है, एक पंप की मशीन खराब हो गई और उसको सही करने के लिए 5-7 दिन लग गए। इसलिए ऐसी अतिरिक्त मोटरों का इंतजाम किया जाए ताकि खराब मोटर को समय पर रिप्लेस किया जा सके और पानी सप्लाई करने में कोई समस्या न आए। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा सिस्टम ज़रूर रखें।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि ऊना की एक बड़ी परियोजना भभोर साहब थी। भभोर साहब से पानी उठाकर हमारे कई गांवों को दिया गया जिनमें बडाला, देला आदि गांव शामिल हैं। पीछे यह स्कीम खनन माफिया के कारण या वहां से पत्थर उठाने के कारण जगह-जगह से टूट चुकी है। इसकी मशीनें भी लगभग 20 साल पुरानी हो चुकी हैं।

क्या इसकी रिपेयर के लिए कुछ किया जाएगा? अगर इस स्कीम को नए तरीके से सही ढंग से चलाया जाता है तो वहां पर जो बहुत

27.03.2018/1540/SLS-HK-3

बड़ी समस्या सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की आ रही है, वह ठीक हो सकती है।

मैं पिछले 15 सालों से देख रहा हूं कि जितनी भी स्कीमें आई हैं उनमें 10-15 स्कीमें ऐसी हैं जिनमें सिंचाई के पानी की पाइपें भी जगह-जगह से लीक कर रही हैं। महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सिंचाई के लिए पानी की पाइपें कई जगह पर इतनी ज्यादा डैमेज्ड हैं कि जब एक जगह पर पानी दिया जाता है तो दूसरी जगह पर वह पानी नुकसान कर रहा है क्योंकि जहां पानी की ज़रूरत नहीं है वहां पर बहुत ज्यादा पानी की लीकेज हो रही है और पानी वहां भर जाता है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस चीज के ऊपर आप ज़रूर ध्यान दें।

27/03/2018/1545/RG/HK/1
श्री सतपाल सिंह रायजादा------जारी

इसके साथ-साथ मेरे क्षेत्र में तीन एन.ए.सी. आती हैं ऊना, संतोषगढ़ और मैहतपुर-बसदेहड़ा और तीनों में पानी निकासी की समस्या है। ऊना में पानी की निकासी के लिए वार्ड नं.-4 और उपायुक्त कार्यालय के लिए एक डी.पी.आर. बनी थी। यहां बरसातों में पानी घुस जाता है। लेकिन वह डी.पी.आर. वहीं-की-वहीं रह गई और उसका पैसा मंजूर नहीं हुआ। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से गुजारिश करुंगा। क्योंकि ऊना शहर, उपायुक्त कार्यालय और अन्य स्थानों पर वहां बरसातों में पानी घुस जाता है। तो इस समस्या से निजात दिलाने के लिए इस स्कीम को क्रियान्वित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं सीवरेज सिस्टम के बारे में कहना चाहूंगा कि जो मैहतपुर, संतोषगढ़ और ऊना में सीवरेज सिस्टम है, हर बार हम यही सुनते हैं कि

इसका लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और यह सुनते-सुनते हमें 10-15 वर्ष हो गए हैं। लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। कई सरकारें आईं और चली गईं---(घण्टी)---लेकिन सीवरेज का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इस काम की अच्छी तरह शुरूआत की जाए। आप एक वरिष्ठ मंत्री हैं और माननीय सदस्यों ने भी आपकी बहुत तारीफ की है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि नई स्कीमों के साथ-साथ हमें विशेष तौर पर पुरानी स्कीमों पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि उनमें कहा कमी है और खासकर इन गर्मियों में जो पम्प इत्यादि खराब हो जाते हैं, नए अतिरिक्त पम्पों का इन्तज़ाम अवश्य रखा जाए। आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : रायजादा जी, आपको बोलने का मौका तो कई बार मिलता रहेगा।
अब इस विस्तृत चर्चा के पश्चात माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

27/03/2018/1545/RG/HK/2

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-13, सिंचाई, जलापूर्ति एव सफाई, इस पर सम्माननीय कांग्रेस विधायक दल के नेता सर्वश्री मुकेश अग्निहोत्री जी, अनिरूद्ध सिंह जी, बहन श्रीमती आशा कुमारी जी, श्री हर्षवर्धन चौहान जी, श्री जगत सिंह नेगी जी, श्री राम लाल ठाकुर जी, श्री राजेन्द्र राणा जी, श्री नन्द लाल जी, डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल जी, आदरणीय राकेश सिंघा जी, पवन कुमार काजल जी, विक्रमादित्य सिंह जी, सुन्दर सिंह ठाकुर जी, श्री आशीष बुटेल जी और श्री सतपाल सिंह रायजादा ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए और विशेष करके आप लोगों ने जो मेरा मार्ग प्रशस्त किया है, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि जो हमारी इस विधान सभा में नए सदस्य जीतकर आए हैं, वे भी वरिष्ठ सदस्यों से कम नहीं हैं। उनके पास बहुत से ऐसे नए विचार हैं जिससे ऐसा लग रहा था कि बहुत सी बातें इस सदन में कई वर्षों से जो हमारे ध्यान में नहीं आईं, वे बातें नए सदस्यों ने हमारे ध्यान में लाई हैं

27.03.2018/1550/जेके/वाईके/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः------जारी-------

उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने बड़ी-बड़ी योजनाओं के विषय उठाए। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के बारे में मुझसे जानना चाहा कि जो 4751 करोड़ रूपए की एक योजना है उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को दें। मैं एक-एक विषय के ऊपर आऊंगा। आपने दूसरी बात मेरे से जाननी चाही कि जो मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल योजना ब्रिक्स से सम्बन्धित जो 3 हजार 267 करोड़ रूपए की योजना है उसके बारे में हम सदन को भी जानकारी दें और साथ में प्रदेश की जनता को भी जानकारी मिले । आपने AIBP के बारे में भी कहा है। हर खेत को पानी लगे, उसके बारे में जानना चाहा है। कमांड एरिया डवैल्पमैंट के बारे में भी आपने जानना चाहा है, मिड इरिगेशन के बारे में भी, सौर ऊर्ज़ा सिंचाई योजना के बारे में और स्वां चैनेलाइजेशन के बारे में भी जानना चाहा है। और एक बात जो आपने अनैतिक वो दो एम0एल0ए0 को जोड़ दिया, यह विधान सभा की गरिमा का प्रश्न है, मैं आपसे चाहूंगा कि कृपया इस अनैतिक शब्द को हटा दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नाबार्ड की आउटर लिमिट के बारे में भी, डी0पी0आर0 बनाने के बारे में भी आपने जानना चाहा है और मैंने कोशिश की है कि सभी माननीय सदस्यों ने जो-जो प्रदेश स्तर की बाते कही है, मैंने उनको भी नोट किया है और जो-जो जिला स्तर की बात कही है उसको भी नोट किया है और जो अपने विधान सभा चुनाव क्षेत्र से सम्बन्धित है, उन बातों को भी मैंने नोट किया है। इससे मेरी जानकारी बढ़ी है। कई बार क्या होता है कि विभाग में बहुत सी योजनाएं व कार्य हैं । उन योजनाओं व कार्यों के बारें में मंत्री तक बात ही नहीं पहुंचाते कि कौन सी योजना है और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं? पेयजल को ले कर मैं इस हाउस के माध्यम से आदरणीय श्री शांता कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं। जब वे 1977 में इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें तो पूरे प्रदेश के अन्दर पानी को उठा करके कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं, इस योजना का शुभारम्भ माननीय शांता कुमार जी ने किया । फिर वर्ष 1990 में दूसरी बार वे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें तो उस वक्त र उन्होंने, पहले तो

27.03.2018/1550/जेके/वाईके/2

उनका यह था कि पानी को उठा करके पहाड़ की चोटी पर ले जाना लेकिन दूसरी बार उन्होंने कहा कि इस ज़मीन की सतह के नीचे के पानी को उठा करके कैसे हम गांव के लोगों की प्यास बुझा सकते हैं? यह दूसरी योजना भी आदरणीय शांता कुमार जी ने इस प्रदेश के अन्दर शुरू की थी। डॉ0 धनी राम शांडिल जी ने कहा कि जल ही जीवन है। निश्चित तौर पर जल ही जीवन है। मनुष्यों के लिए भी, पशु-पक्षियों के लिए भी, वन्य प्राणियों के लिए भी और जितनी भी वैजिटेशन्ज़ हैं उन सबके लिए भी। जल के वगैर हमारा जीवन अधूरा है। इस पर भी मैं आगे कहूंगा, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। इस जलवायु परिवर्तन पर प्रश्न केवल सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं है। यह तो एक ऐसा फोरम है, यह तो प्रदेश का एक ऐसा मन्दिर है कि यहां से हम ऐसे-ऐसे डिसिज़न लें जिनसे हम इस प्रदेश की जनता को जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित कर सकें। जलवायु परिवर्तन पर भी मैं आगे आऊंगा कि हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसका सामना कर सकते हैं? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज से बहुत वर्षों पहले कहा था कि अगर इस संसार के अन्दर तृतीय विश्वयुद्ध होगा तो पानी के नाम पर होगा। उस वक्त तो हमें ऐसा लगता था कि अटल जी ने यह क्या बात कह दी ? लेकिन उनके जीवन का जो अनुभव था,

27.03.2018/1555/SS-YK/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री क्रमागतः

उन्होंने जो बात उस वक्त कही थी आज निश्चित तौर पर लग रहा है कि हम उस ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज बहुत से माननीय सदस्यों ने टैंकों की सफाई और टैंकों व पाइपों की लीकेज के बारे में कहा है। निश्चित तौर पर यह कई जगह मेरे ध्यान में भी आया है लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम देखते हैं कि बहुत पाइपों की लीकेज है। अगर राइजिंग मेन है तो वह लीक कर रही है। अगर वह ग्रैविटी मेन है तो वह लीक कर रही है। अगर वह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वह लीक कर रहा है। अगर हमारे भंडारण टैंक हैं तो

वे जिस क्षमता के लिए बनाए गए थे, मेरे ख्याल में सम्माननीय सदस्य, श्री काजल जी ने कहा कि उसकी एजैक्टिंग करते-करते क्षमता कम हो रही है। कई बार उसकी एजैक्टिंग बाहर से कर रहे हैं, कई बार उसकी एजैक्टिंग अंदर से कर रहे हैं और उसकी एजैक्टिंग करते-करते अगर उस टैंक की क्षमता 50 हजार लीटर की थी तो वह घट करके 20 या 25 हजार लीटर रह गई। इतना करने के बावजूद भी वह टैंक लीक कर रहा है। यह जो वेस्टेज ऑफ वाटर है इसको कैसे रोका जा सके, यह भी एक चिन्ता का विषय है। यह पूरे प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है। इस पर भी आपने हमारा ध्यान आकर्षित किया है निश्चित तौर पर हम इस पर काम करेंगे।

आपने एक बात और कही है कि हैंडपम्प जो प्राइवेट लगा रहे हैं उसको परमिशन मिलनी चाहिए। वैसे तो बिना आई0पी0एच0 की अनुमति के कहीं भी कोई प्राइवेट बॉडी अपना हैंडपम्प नहीं लगा सकती है। उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है।

एक बात आपने मैंटीनेंस के बारे में कही। हम स्कीम बना रहे हैं, मोटरें इंस्टॉल कर रहे हैं, पम्प इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन हमारे पास उसकी रिपेयर और मैंटीनेंस के लिए जो धनराशि होनी चाहिए वह धनराशि न के बराबर है। जब भी कोई मोटर खराब होती है या कुछ और होता है तो आज भी हज़ारों ऐसे मामले इस प्रदेश के अंदर हैं, विभिन्न मंडलों के हैं, सब-डिवीजनों के हैं, सैक्शन्ज़ के हैं कि उनके पम्प कहीं पड़े हुए हैं। वे पम्प जहां रिपेयर के लिए छोड़े हैं वे उन पम्पों को नहीं दे रहे हैं। एक जगह मैं गया और मैंने पूछा कि पम्प क्यों नहीं दे रहे हैं तो कहने लगे कि पिछली पेमेंट करो तो हम आपको पम्प देंगे। जब तक पिछली पेमेंट

27.03.2018/1555/SS-YK/2

नहीं करेंगे तब तक आपको पम्प नहीं देंगे। एक ऐसी स्थिति है कि रिपेयर एंड मैंटीनेंस में जो हमें अमाउंट मिलना चाहिए उसमें वाकई में कुछ कमी है।

एक बात सीवरेज के बारे में सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने कही है और अन्य सम्माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि इस प्रदेश के अंदर जो सीवरेज की योजनाएं हैं, 57 ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जिनमें केवलमात्र सीवरेज की योजनाएं चल रही हैं या चलाने जा रहे हैं। लेकिन हम इस बात को भूल रहे हैं कि अब उन 57 क्षेत्रों के साथ-साथ जो प्रदेश के अंदर प्लानिंग

एरिया बन गया, उसमें जितने भी कायदे-कानून हैं वे टी0सी0पी0 के लगे हुए हैं। कायदे-कानून टी0सी0पी0 के लगे लेकिन जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिएं उससे वे वंचित हैं। सीवरेज की जब बात करते हैं तो वे कहते हैं कि यह ग्रामीण क्षेत्र है इसमें सीवरेज नहीं हो सकती है। आज अनेकों ऐसे गांव, प्लानिंग एरियाज़ हैं जहां इतनी ज्यादा पापुलेशन हो चुकी है कि अब समय आ चुका है कि हम उस पुराने ढर्रे पर ही न चलें। इस पर भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। आज कई जगह इंडविजुअल सैप्टिक टैंक बन रहे हैं, वे छोटे-छोटे बन रहे हैं और कुछ ही वर्षों के बाद वे भर जाते हैं। जब वे भरते हैं और उनका ओवर फ्लो होता है तो उनकी गन्दगी गांव के रास्ते के बीच में पड़ती है। रास्ते से होते हुए वह पूरे गांव को गन्दा कर देती है। उसकी वजह से आज अनेकों बीमारियों हमारे गांव में फैल रही हैं। इस पर भी आपने ध्यान आकर्षित किया है इस पर भी निश्चित तौर पर विभाग ध्यान देगा। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना करूंगा क्योंकि इस पर अब हमारे को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, हम केवल मात्र शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न रहें; नगर पंचायतों, नगर परिषदों या नगर निगमों तक ही सीमित न रहें, इससे बाहर निकलें। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अब हम इस पर आगे बढ़ें। मित्रों, अगर मैं एक-एक का जवाब दूंगा तो मैं समझूंगा कि वह किसी के लिए मानना बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

27.03.2018/1600/केएस/वाईके/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी---

इस करके जो आज की वस्तुस्थिति है, (व्यवधान) मिलेगा और प्रैक्टिकल रूप में जवाब मिलेगा। बहन आशा जी ने डलहौजी की बात की थी, मैंने अपने पास लिखा है, आपकी जो एक स्कीम आउटसोर्स हुई है, उसका भी लिखा है, दूसरी स्कीमों का भी लिखा है। बड़ी-बड़ी स्कीमें हैं।

श्री हर्षवधन चौहानः मंत्री जी, आप आश्वासन दें कि जिन पहलुओं पर हमने कहा है, विभाग उन पर उचित कार्रवाई करेगा।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः हषवर्धन जी, आपने तो थोड़ी सी बातें कही है। आपके चुनाव क्षेत्र की बहुत स्कीमों की मेरे पास डिटेल आई हुई है। अगर मैं उन सभी स्कीमों के बारे में बताने लगूं तो यह हम सब के लिए पॉसिबल नहीं होगा। आपको मेरी वर्किंग का पता है और मुझे आपकी वर्किंग का पता है क्योंकि हम एक कमेटी में साथ थे।

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः मंत्री जी, ब्रिक्स के लिए वीरभद्र सिंह जी का भी धन्यवाद कर देते क्योंकि आपने शांता कुमार जी का भी धन्यवाद किया है।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्रीः अग्निहोत्री जी, अभी तो मैं ब्रिक्स पर पहुंचा ही नहीं हूं। जब मैं उस बारे में बालूंगा तब मैं धन्यवाद करूंगा। आप एडवांस में क्यों धन्यवाद करने के लिए कह रहे हो? आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं, सबसे बुजुर्ग नेता हैं। हम इनका पूरा मान-सम्मान करते हैं। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। वक्त के मुताबिक हर व्यक्ति निर्णय करता है। वक्त बलवान होता है, इन्सान बलवान नहीं होता इसलिए जो हो गया, हो गया अब आगे की सोचेंगें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना की तरफ इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2015 में लागू की। जब योजना

27.03.2018/1600/केएस/वाईके/2

लागू की उस वक्त उनका मानना था कि योजनाएं ऊपर से नीचे को क्यों आए? योजना नीचे से ऊपर को जाए। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बना और जितने भी हमारे जिलाधीश थे, उन्होंने अपने-अपने जिले का डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान बनाया। 12 जिलों का डिस्ट्रिक्ट इरिगेशन प्लान आ करके हमारे स्टेट में स्टेट इरिगेशन प्लान बन गया। और जब वह प्लान बना तो स्टेट लैवल की एक सैंक्शनिंग कमेटी बनी। उन्होंने पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं बनाई। उन योजनाओं के लिए हमें इस हाउस के माध्यम से आदरणीय प्रधान

मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए । आप बोलेंगें कि वह क्या है? तो वह है कि हिमाचल प्रदेश को स्पैशल केटैगरी स्टेट में डालने से हमारी जो सैंट्रल फंडिंग है वह अब 90:10 के अनुपात में आना शुरू हुई है। आपने ए.आई.बी.पी. के बारे में भी बात की। उस पर मैं आगे चर्चा करूंगा। हमारे यहां से जितनी स्कीमें गई, 1857 स्कीमों का अनुमानित 5664 करोड़ रुपये का एक प्रोजैक्ट भारत सरकार को भेजा। मित्रो, उसमें अगर कमी रही है,

27.3.2018/1605/av/ag/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जारी----------

उसमें अनेकों खामियां थीं। यहां से भारत सरकार को कोई योजना भेजना ही सब कुछ नहीं है कि हमने यहां से डी0पी0आर0 भेज दी है और अब भारत सरकार करे या न करे। वहां पर जो स्क्रूटनी होती है और वहां पर जो औपचारिकताएं हैं उनको हमारे आफिसरों ने पूरा नहीं किया। उन औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ उसमें विभाग के मंत्री और सचिव का विशेष योगदान होना चाहिए और उन्हें यहां से लेकर दिल्ली तक हर चीज फोलो करनी चाहिए। यहां से लेकर दिल्ली तक जो फोलो करेगा वह पैसा ले जाता है। आज अनेकों ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दिल्ली में अपने सचिव स्तर के आफिसर और चीफ इंजीनियर बैठाये हुए हैं। उनको केवल एक ही काम दिया गया है कि प्रदेश से जो विभिन्न विभागों से सम्बंधित प्रोजैक्ट आ रहे हैं आपने उनको फोलोअप करना है और फोलोअप करने के बाद उनको सैंक्शन करना है। लेकिन उसमें कमी रही है और उसके लिए मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता। मगर एक बात जरूर है कि एक ऐसी स्थिति में हमें यह दायित्व मिला है, अगर पिछले वालों ने सारा कुछ पटरी पर रखा होता तो इस गाड़ी को आगे दौड़ाने में हमें कोई असुविधा न होती। लेकिन यह गाड़ी डी-रेल हो चुकी है और इसको दोबारा से पटरी पर लाना पड़ रहा है और पटरी पर लाकर इसको दौड़ाना पड़ेगा। इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके सहयोग के बिना, पूरे सदन के सहयोग के बगैर और प्रदेश की जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। यहां पर

दूसरी बात नाबार्ड के बारे में कही गई है। इस बारे में बहुत सारे सम्माननीय सदस्यों ने कहा है और मेरे पास अभी इसकी एक्युरेट फीगर नहीं है लेकिन मुझे ऐसा बताया गया है कि नाबार्ड के पास 800 डी0पी0आर0 पड़ी है। उनमें से कोई भी डी0पी0आर0 ऐसी नहीं है जो एक करोड़ रुपये से कम होगी। कई बार ऐसा होता है कि कोई डी0पी0आर0 5 या 10 लाख रुपये की है मगर इसमें कोई भी डी0पी0आर0 1 करोड़ रुपये से कम नहीं है। अब आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि 800 डी0पी0आर0 पहले की पड़ी हुई हैं और अब जो 68 नये

27.3.2018/1605/av/ag/2

सदस्य चुनकर आये हैं तथा हमने आगे के लिए जो अपनी-अपनी डी0पी0आर0 देनी है उसके लिए कहा जाता है कि 800 डी0पी0आर0 तो पहले पड़ी हुई हैं अब नई डी0पी0आर0 कैसे करेंगे। हमें इस बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?(---व्यवधान ---) माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी यही कहा था कि इतनी ज्यादा डी0पी0आरज0 हैं और इसके लिए दोनों तरफ के वर्तमान विधायक अपने-अपने चुनाव क्षेत्र के लिए अपनी-अपनी प्रायोरिटी फिक्स कर दें कि मेरी प्रायोरिटी वाटर सप्लाई स्कीम, रोड्स या दूसरी स्कीमों में इस-इस प्रकार से हैं। यहां पर एक बात और सामने आई है कि जो नाबार्ड का पैसा है क्योंकि आज से पांच साल पहले तो यह होता था कि नाबार्ड से जो भी स्कीम सैंक्शन होकर आती थी उसका पैसा एकमुश्त आ जाता था। उसके बाद फिर उसके लिए टैंडर लग जाते थे और वह टैंडर पूरे हो जाते थे। लेकिन एक ऐसा सिस्टम अपनाया गया कि वह नाबार्ड का पैसा क्योंकि अब स्कीमें तो बहुत सारी सैंक्शन हो चुकी है मगर बहुत सारी स्कीमें चालू नहीं हुई और जो चालू भी हुई हैं वह अब ऐसी स्थिति में है कि ज्यादा गैप पड़ने के कारण उनके लिए रिवाईज्ड डी0पी0आर0 बनानी पड़ रही है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : यह नाबार्ड कर रहा है या फाइनैंस डिपार्टमैंट कर रहा है?

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री : माननीय सदस्य, मैं बताता हूं। हमारी जो डी0पी0आर0 हैं उनके लिए थोड़ा-थोड़ा पैसा दिया जा रहा है और उसकी वजह से हमारी कई डी0पी0आर0 डबल में पहुंच रही है और कई जगह पर रिवाईज्ड बनाना पड़ रहा है। इस करके हमें इस सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा और अगर हम इस सिस्टम को नहीं सुधारेंगे

तो हमारे बहुत सारे ऐस्टिमेट वैसे-के-वैसे रह जायेंगे। मैं आपका ध्यान लघु सिंचाई योजना की तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2017-18 में लघु सिंचाई योजना के लिए 222 करोड़ रुपये रखे गये थे। मैं इस हाउस के माध्यम से मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और नेता, कांग्रेस पार्टी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को बताना चाहूंगा कि इस वर्ष यानि 2018-19 के लिए उस 222 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 248 करोड़ रुपये कर दिया है।-

27.03.2018/1610/TCV/AG-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री..... जारी।

आप AIBP की बात कर रहे थे कि मीडियम इरिगेशन्ज में क्या है? मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि AIBP में पूरे भारतवर्ष से प्राथमिकताएं मांगी गई। सभी राज्यों से प्राथमिकतायें मांगी गई कि आप किन-किन स्कीमों को AIBP में डालना चाहते हैं। लेकिन मुझे बड़े दुःख से कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2015-16 में 149 स्कीम्ज़ पूरे देश से भारत सरकार के पास पहुंची और 149 में से भारत सरकार ने केवलमात्र 99 स्कीम्ज़ प्रायोरिटी में ली। इन सिंचाई की स्कीमों के लिए पूरी फंडिंग भारत सरकार ने करनी थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश उससे बाहर हो गया। हम इन 99 और 149 स्कीम्ज़ से भी बाहर हो गये। मैं अभी-अभी दिल्ली गया था । मैंने AIBP के बारे में केन्द्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से निवेदन किया कि AIBP में हमने बड़ी-बड़ी स्कीमें डाली थी, इसमें और स्कीमें तो हैं लेकिन हमारी कोई स्कीम नहीं है। उन्होंने सचिव, श्री यू0पी0 सिंह जी को बुलाया और हमारी स्कीमों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है? उनका फलोअप ही नहीं था। जिस प्रकार से स्कीमें हमारे पास पहुंचनी चाहिए थी, वह नहीं पहुंची। स्कीमों को भेजने का मतलब यह नहीं है कि डी0पी0आर0 बनाई और डॉयरेक्टर से करवा करके चण्डीगढ़ में सी0डब्ल्यू0सी0 के पास फैंक दी, चाहे उसमें जितनी मर्ज़ी कमियां क्यों न हों। वे स्कीमें तो छन्न करके भारत सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। जो स्कीमें छन्न करके उनके पास पहुंचती है, उनको फंडिंग होती है। माननीय अग्निहोत्री जी

आप बताओ, मेरा क्या कसूर है। अब पठानिया जी मेरे सिर के ऊपर बैठे हुए हैं। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु छाती के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी दो-दो स्कीमें हैं, इनको करो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं। अगर वहां से पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी प्रदेश सरकार 85 करोड़ रुपये इन 2 स्कीमों को पूरा करने के लिए दे रही है। इसके बावजूद भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने केन्द्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से निवेदन किया है। उन्होंने अपने सचिव, श्री यू0पी0 सिंह जी को कहा कि इसका कुछ-न-कुछ समाधान

27.03.2018/1610/TCV/AG-2

निकाला जाये। मुझे उम्मीद है इसका समाधान निकलेगा। इसका समाधान क्या निकलेगा, यह तभी बताएंगे, जब समाधान निकलेगा। वरना आप कहेंगे कि ये तो आप वैसे ही घोषणाएं कर रहे हैं। हम उसी योजना का नाम इस हाउस में लेंगे, जिस योजना के लिए हम कोई-न-कोई प्रावधान लेकर लाएंगे।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसके अलावा बहुत से सदस्यों ने कहा कि पानी नीचे से उठाया और ऊपर टैंक में डाल दिया। फिर उन्होंने कहा कि यह इस क्राईटेरिया में नहीं आती थी। क्योंकि 2000 हैक्टेयर से कम की जो भी सिंचाई की स्कीमें हैं, वे माइनर इरिगेशन में आती है। जो माइनर इरिगेशन में स्कीमें आती है, उन स्कीमों में भारत सरकार प्रति हैक्टेयर 2.50 लाख रुपये देती है। इससे ज्यादा नहीं देती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, यहां 2.50 लाख रुपये से अगर हम किसी स्कीम को पूरा करना चाहे तो वह पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंजीनियर्ज़ सारा कमांद एरिया ले लेते हैं। वे कहते हैं कि 2000 या 2000 हैक्टेयर से कम एरिया ले लेते हैं, जितना पैसा भारत सरकार से मिलेगा, उतना ठीक है, बाकी बाद में देख लेंगे।

27-03-2018/1615/NS/DC/1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ------जारी

हम कमांद एरिया डिवैल्पमैंट की डी0पी0आर0 बना रहे हैं और हम डी0पी0आर0 भारत सरकार को भेज रहे हैं ताकि भारत सरकार से पैसा ले सकें। मित्रों, आज इस सरकार के शपथ के तीन महीने हुए हैं और तीन महीनों के अंदर जब कोई मुख्य मंत्री, मंत्री या विधायक बनता है तो अपने क्षेत्र, जिला और प्रदेश में उसके सम्मान समारोह होते हैं तथा उसका स्वागत किया जाता है। इसके बावजूद हमारे मुख्य मंत्री जी ने और हमने मिल करके प्रयास किये हैं कि हम कितनी योजनायें भारत सरकार से ला सकते हैं? आदरणीय वीरभद्र सिंह जी आपकी बगल में बैठे हैं, इनको आपसे ज्यादा पता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है? मैं कह सकता हूं कि किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह राज्य अपने पांव पर खड़ा हो सके। आज पंजाब की क्या हालत है? आज पंजाब की हालत हिमाचल प्रदेश से दस गुणा ज्यादा बदतर है। इसलिए हम कमांद एरिया डिवैल्पमैंट के माध्यम से भारत सरकार से स्कीमें ला रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने वर्ष 2018-19 के लिए कमांद एरिया के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से भी बज़ट रखा है। मैं, अग्निहोत्री जी आपके माध्यम से आपके सभी मित्रों को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017-18 में इसके लिए लगभग 75 करोड़ रुपये की राशि रखी गई थी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने वर्ष 2018-19 के लिए इस 75 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ा करके 130 करोड़ रुपये कर दिया है। यह कितने प्रतिशत ऊपर हुआ है? मुझे हिसाब-किताब कम आता है। इसके अलावा हम और भी प्रयास कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर जो सिंचाई की व्यवस्था है, उस सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए हम और भी प्रयास करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं पेयजल योजनाओं के ऊपर आता हूं और 'ब्रिक्स' की बात करता हूं। आपने कहा कि महेन्द्र सिंह जी आप हवाई तीर मारते हैं, गप्पें मारते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं गप्पे तो नहीं मारता लेकिन काम करने की कोशिश करता हूं। 'मुख्य मंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्त्ति योजना' के लिए मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस योजना के तहत पांच सालों के लिए

3,267 करोड़ रुपये की राशि रखी है। वहीं इस साल के लिए लगभग 670 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। ---(व्यवधान)--- आप सुनिये। आप चिन्ता न करें।

27-03-2018/1615/NS/DC/2

यहां (मुख्य मंत्री की तरफ इशारा करते हुए) सीधा-सा है। यहां ऐसा नहीं है कि इस तरफ की लाइन बंद कर देनी है। यहां पर चारों लाइनें खुली हैं। मैं माननीय सदन में बोल रहा हूं, किसी जनसभा में नहीं बोल रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिये हैं कि हर क्षेत्र की ग्रामीण पेयजल योजनाओं या बड़ी-बड़ी योजनाओं के लिए पैसा देना है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अन्य पेयजल योजनाओं के लिए प्रावधान किये हैं, मैं उन पर नहीं जाना चाहता हूं, फिर तो बड़ी लम्बी वार्ता हो जायेगी।

मैं आपका ध्यान हैंडपम्प की तरफ ले जाना चाहता हूं। प्रदेश में कुल हैंडपम्प लगभग 36,989 लगे हुए हैं। यह ठीक है कि बहुत से हैंडपम्प ऐसे हैं जोकि defunct हैं।

27.03.2018/1620/RKS/DC-1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री... जारी

हमने विभाग को आदेश दिए हैं कि जो डिफंक्ट हैंडपंप हैं उनकी फ्लशिंग की जाए। जिन हैंडपंपों में पानी नहीं आता है, जिनका सामान सर्विस योग्य है, उस सामान को निकालकर स्टोर में रख दीजिए और जहां दूसरा हैंडपंप लगना है, वहां उसको एडजस्ट कर दीजिए। मैं इस माननीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन हैंडपम्पों से पीला पानी निकलना शुरू हो जाए, मटमैला पानी निकलना शुरू हो जाए, कृपया उन हैंडपंपों को बंद कर दीजिए। जब पीला और लाल पानी निकलना शुरू हो जाता है तो वह पानी स्वास्थ्य के लिए, पेट की बीमारियों के लिए सबसे खतरनाक होता है। यह हम सब का दायित्व है। एक-एक निर्वाचन क्षेत्र के अंदर लगभग 5-5, 6-6, 7-7 सौ हैंडपम्प लगे हुए हैं। विभाग भी 6-7 सौ हैंडपंपों को चैक नहीं कर पाएगा। हमारे पीछे एक कैडर है और हम अपने कैडर

को इस बात से अवगत करवा दें कि जहां पर इस प्रकार की स्थिति पैदा हो, वहां उन हैंडपम्पों को बंद कर दिया जाए। इसके लिए हम भी आपकी मदद चाहते हैं।

यहां पर शहरी क्षेत्र की बात हुई। शिमला शहर के लिए कोलडैम से 775 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की एक पेयजल परियोजना वर्ल्ड बैंक के पास अभी विचाराधीन है। मैं यह नहीं कहता कि यह परियोजना स्वीकृत हो गई है। लेकिन इसकी जो औपचारिकताएं हैं, हम उन औपचारिकताएं को पूरा करने जा रहे हैं। शिमला हमारे प्रदेश की राजधानी है। मुझे आज यहां बहुत-से लोग मिले और उन्होंने कहा कि शिमला में तीसरे दिन पानी आना शुरू हो गया है। इसलिए हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इस 775 करोड़ रुपये की योजना के अंतर्गत जो कोलडैम से पानी उठाना है, उसमें वर्ल्ड बैंक की कुछ शर्तें हैं और हम उन शर्तों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। (...व्यवधान...) मैं माननीय सदस्य, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के कहने पर श्री वीरभद्र सिंह जी का भी इसके लिए धन्यवाद करता हूं। (...व्यवधान...) जलवायु परिवर्तन को लेकर हम सब बहुत चिंतित हैं। माननीय अध्यक्ष जी आपने इसी संदर्भ में एक मीटिंग रखी हुई है और इसके लिए आपने सभी

27.03.2018/1620/RKS/DC-2

विधायकों, मंत्रीगण और माननीय मुख्य मंत्री जी को पीटरहॉफ में सादर आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि जितने भी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग में हैं, उन ग्लेशियरों का पिघलना लगातार चला हुआ है। जिस तरीके से बर्फबारी नहीं हो रही है, बर्फबारी का न होना भी हम सब के लिए चिंता का विषय है। बारिश का कम होना भी न केवल हिमाचल प्रदेश के लिए, हिन्दुस्तान के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक खतरा है। हमें इस तरफ आगे क्या करना चाहिए? मैं यह महसूस करता हूं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हमारे ग्लेशियर कम होते जा रहे हैं। जिन ग्लेशियरों का पानी नालों, खड्डों और नदियों के माध्यम से हमारे प्रदेश को

सिंचाई व पीने के पानी के लिए फीड करता था और वही पानी उत्तरी भारत में भी जाता था। उसके लिए हमें हिमाचल प्रदेश के अंदर विकल्प ढूंढना पड़ेंगे। आदरणीय अग्निहोत्री जी आपने 4751 करोड़ रुपये के बारे में एक हवाई बात कही है। यहां हवाई बात नहीं कही जाती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसे टॉप प्रायोरिटी में लिया है।

27.03.2018/1625/बी0एस0/एच0के0-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री .....जारी

तीन मिटिंगे इस बारे में की हुई हैं। अधिकारियों के साथ हुई है। BRICS के लोग आए हुए थे उनके साथ हुई है। तीन बैठकें हमने की हैं। इस प्रदेश के अदंर, पहाड़ी राज्य होने के नाते हमारे पास जो भौगोलिक परिस्थितियां है, वे इस प्रकार की है कि हम वर्षा के जल का संग्रहण कैसे कर सकते हैं ? उस वर्षा के जल का संग्रहण करने के लिए Rain Water Harvesting Structure-cum-Lift Irrigation Scheme-cum- Water Supply Scheme-cum-Flow Irrigation Scheme हम इस तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमने इसके लिए कनसेप्ट नोट भारत सरकार को, आदरणीय गडकरी जी के मंत्रालय को, मैंने व्यक्तिगत रूप से दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पत्र दिया था और मैंन भी व्यक्तिगत रूप से दिया हुआ है। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी का जलवायु परिवर्तन को ले करके ड्रीम प्रोजैक्ट है कि वर्षा के जल का संग्रहण करना। हमने साथ में जोड़ा है कि कैसे हम अपने किसानों की आमद को दोगुणा कर सकते हैं। जिस बात का जिक्र कमारे माननीय सदस्यों ने यहां पर किया था। 4751 करोड़ रुपये का कनसेप्ट नोट हमने केन्द्र सरकार को भेजा है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि जो कनसेप्ट हमने भेजा है वह स्वीकृत हो करके आ गया, ऐसा नही है। इसकी औपचारिकताएं बहुत हैं। वहां वाटर सोर्स मिनिस्ट्री से वित्त मंत्रालय को यह मामला जाएगा उसके बाद किस एजेंसी को देते हैं वल्ड बैंक को देते हैं या किसको देते हैं । उसके बाद फिर वे लोग यहां आएंगे उसके बाद कंस्लटेंट लगेगा। फिर इसकी वाकायदा

डी.पी.आर. बनेगी। जब डी.पी.आर. बनेगी। फिर इसकी फंडिग हमने 6 फेजिज में की हुई है और जो हमने 6 फेजिज में फंडिग का प्रावधान किया है उसमें पहले चरण में हमने 708 करोड़ रुपया रखा है। मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर और विशेष करके हमारा पहाड़ी राज्य होने के नाते हमारा पठानकोट से ले करके पूरा क्षेत्र पोंटा साहिब तक पूरे-का-पूरा क्षेत्र इस Rain Water Harvesting Structure की हमारी प्रपोजल है इसमें बहुत ज्यादा लाभान्वित हो सकता है। इससे हमारे पास जो बर्फ के ग्लेशियर कम हो रहे हैं उसका भी एक विकल्प

27.03.2018/1625/बी0एस0/एच0के0-2

हो जाएगा। इस विकल्प से क्या कर सकते है? हम इससे पीने का पानी, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मतलब है कि हम कुछ न करें हम हनिमून पीरियड में सिर्फ मालाएं पहनते रहें। हम उन लोगों में से नहीं है, हम काम करने वाले लोगों में से हैं। वहां से ले करके यहां तक (सत्ता पक्ष और विपक्ष) सब काम करने वाले लोग हैं। जब हम कर्म करेंगे तभी फल की इच्छा रखेंगे। हम आप से भी चाहते हैं कि आप अच्छे कार्यों के लिए सहयोग करें। कटाक्ष करें, हम नहीं कहते आप निंदा न करें। लेकिन निंदा ऐसी करो जो सबको मान्य हो। आप हमेशा मेरी निंदा करते हैं मुझे सब पता है। वैसी निंदा न करें। हम एक और प्रयास करने जा रहे हैं। यहां पर एक बात आदरणीय राणा जी ने कही कि हमीरपुर और सरकाघाट और सुजानपुर क्षेत्रों के लिए हमने स्कीमें लाई । मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मैंने Urban Development Ministry से स्कीम लाई थी। 2012 में मेरे पास अर्बन डवेल्पमैंट विभाग था । मैंने 41 करोड़ रुपये की एक स्कीम सरकाघाट टॉन के नाम से अपने क्षेत्र के लिए लाई, एक स्कीम मुझे आदरणीय धूमल साहब ने कहा कि हमीरपुर के लिए ले आओ, हमने 65 करोड़ रुपये की स्कीम उनके लिए लाई और एक स्कीम सुजानपुर के लिए भी लाई। आदरणीय अग्निहोत्री जी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि

उन स्कीमों का कार्य जिस रफ्तार से चला हुआ था वह धीमी रफ्तार से हो रहा था। जो कार्य पूरा होना चाहिए था वह पूरा नहीं हुआ और 2015 में भारत सरकार ने उस स्कीम का नाम बदल दिया। जिन प्रदेशों ने यूटेलाईजेशन स्र्टीफिकेट दे दिया उन्होंने उस पैसे को ले लिया उनको पैसा पूरा मिल गया। जिन्होंने कुछ नहीं किया और यह सोचा कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय का पैसा है या महेन्द्र सिंह के टाइम का पैसा था, वह पूरा पैसा नहीं मिला। अब उस स्कीम का नाम भारत सरकार के अन्दर बदल कर अमरूत हो गया है।

27.03.2018/1630 /DT/HK-1

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री... जारी

अभी मैं सरकाघाट स्कीम की एक डी0पी0आर0 लेकर भारत सरकार के पास गया कि इस स्कीम में हमारा इतना पैसा बचता है। आदरणीय पूरी जी जो भारत सरकार में मंत्री है, उन्होंने कहा कि वह स्कीम तो बंद हो गई है । अब तो अमृत फस्ट फेस चल पड़ा है। मैंने कहा उसमें तो यह है ही नहीं । उन्होंने कहा कि यह इसमें नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकाघाट की स्कीम में 15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आदरणीय राणा जी आपकी हमीरपुर की स्कीम का नुकसान हुआ। आपकी सुजानपुर की स्कीम का नुकसान हुआ। सरकारें निरंतरता में हैं। आपने जो किया है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम उसे रोक नहीं रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। उस वक्त अगर यह काम कर दिया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती। हमारे मित्रों ने कहा कि यह पुरानी स्कीमें हैं। हम एक और काम करने जा रहे हैं और आप कहेंगे कि एक और हवाई फायर हो गया। यह एंटी हेलगन के फायर नहीं है। ये एंटी हैलगन के प्रैक्टिकल फायर है। जितनी हमारी पुरानी पेयजल योजना हैं, ये स्कीमें 1970, 1980 ,1990 और 2000 के दशक में बनी हई हैं। उस समय बहुत कम आबादी थी और ये स्कीमें कम पॉप्यूलेशन की आबादी के लिए डिजाइन हुई थी।

हम पुरानी स्कीमों को ऑगमैंट करने के लिए लगभग 700-800 करोड़ रुपये की एक और प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को भेजेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के पत्र को स्वयं ले करके जाऊंगा। कोशिश करना हमारा काम है, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे और आसमान की तरफ देखते रहेंगे कि आसमान की तरफ से कुछ पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। आसमान से कुछ पड़ने वाला नहीं है। जब हम प्रसास करेंगे तभी हमें कुछ-न-कुछ मिलेगा। एक सुझाव बहुत अच्छा आया है। नये विधायकों ने सुझाव दिया है कि जब सूखा पड़ता है तो मोटर खराब हो जाती है, , पम्प खराब हो जाता है और स्कीम एक महीना, दो महीना बंद रहती है। उस वक्त हम पानी नहीं पहुंचा सकते। हम एक्सट्रा पम्प और एक्सट्रा मोटर्स वहां स्थापित करें। इसका भी हम प्रावधान कर रहे हैं। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इसमें

27.03.2018/1630 /DT/HK-2

भी हमारा मार्ग दर्शन करें, ताकि हम इस तरफ आगे बढ़ सकें। आपने पाइप क्रय करने की बात कही है। जो वर्ष 2017-18 के लिए बजट प्रावधान था उसमें पाइपें नहीं खरीदी गई। उसमें मेरा क्या कसूर है। आदरणीय मुख्य मंत्री जी का क्या कसूर है। हमरा क्या कसूर है। पाइपों के लिए आदरणीय वीरभद्र सिंह जी ने पैसा दिया था इनके पास वित्त विभाग था। खरीदनी तो विभाग का काम था। जो पाइप परचेज कमेटी थी उसका चेयर पर्सन मंत्री होता है। मंत्री जी मीटिंग न करे तो उसमें मुख्य मंत्री जी ने क्या करना या अधिकारियों ने क्या करना? आई.पी.एच. एक ऐसा विभाग है, इस विभाग में अगर पाइप होगी तभी पैसा खर्च होगा अगर पाइप नहीं होगा तो पैसा कहां खर्च होगा। पाइप आएगी तो उसकी लेईंग होगी अगर लेईंग होगी तो टैंक बनेंगे, टैंक में पैसा खर्च होगा। 16 मार्च, 2018 पाइप परचेज कमेटी की बैठक में लास्ट आर्डर दिया है। हम आने वाले समय के लिए आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हमने अपने विभाग को कहा है कि आप 1 अप्रैल, 2018 को चारों जोनों की डिमांड को प्रमुख अभियंता के पास पहुंचाएं और 7 अप्रैल, 2018 तक हम पाइप परचेज कमेटी की बैठक कर लेंगे। ताकि हमारा आर्डर चला जाए और पाइप टाइमली पहुंच जाए।

आदरणीय ठाकुर राम लाल जी कह रहे थे कि उन क्षेत्रों में पहले पाइपें पहुंचा दे जो सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में आते हैं। हम उन क्षेत्रों में पाइपें पहले पहुंचा दे जहां बर्फ पड़ती है। हम उन क्षेत्रों में पाइपें पहुंचा दे जहां कच्ची सड़के हैं, जहां आगे गाडियां नही चल सकती।

27.03.2018/1635/SLS-HK-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ...जारी

हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। पाईप परचेज करती बार मात्र उस स्कीम के बजट के 35% की पाईप परचेज होती है। मैं माननीय मुख्य मंत्री से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि पाईप कंपोनैंट लगभग 60% का है, इसलिए जब 60% का है तो उतने की ही पाईप खरीदी जाए। हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे।

आपमें से बहुतों ने कहा है कि आई.पी.एच. विभाग के अंदर भ्रष्टाचार है। आपने हमारे ध्यान में लाया है। ठाकुर राम लाल जी ने ठीक कहा कि पाईपें इस तरह थीं। यह आपके समय की बात थी। लेकिन आपके समय की हो या हमारे समय की हो, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, वह चाहे किसी के भी समय में हो, उसको तो रोकना चाहिए। यह नहीं कि आप करो और हम आंखें बंद कर देते हैं। इसके लिए हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि हमने जितनी पाईप के ऑर्डर दिए हैं, क्या उतनी पाईप हमारे पास पहुंच रही है। हम औचक निरीक्षण करेंगे। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि आप भी इसका निरीक्षण करें। यह एक नेशनल प्रॉपर्टी है; हम सबकी धरोहर है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए मात्र हम ही जिम्मेवार हैं। इसलिए जहां भी आपको लगे, आप चैक करो कि कहीं पाईपें कम तो नहीं आई।

इसके अलावा, जो सूखे की स्थिति है, उसके लिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम एक ऐसी स्थिति में कदम रखने जा रहे हैं कि हमारी जितनी भी ग्रेविटी की स्कीमें थीं वह मैक्सिमम अब सूखने के कगार पर हैं। हमारी जितनी भी उठाऊ पेयजल की स्कीमें थीं जो हमने नालों

और खड्डों से बनाई थीं, वह सूखने के कगार पर हैं। हम ऐसे सोर्सिज को लेकर पूरे 12 जिलों के अंदर सूखाग्रस्त मुद्दे पर बैठकें कर रहे हैं। पहली बैठक हमने बिलासपुर में की है। ठाकुर राम लाल जी, हमारी पार्टी के तीनों विधायक उस बैठक में उपस्थित थे। हम जो डायरैक्टिव्ज दे सकते थे, हमने पूरे प्रशासन को दिए कि इसके लिए पूरी तैयारी करो। हम इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि जो टैंकर बाहर से आएं वह टैंकर अंदर से साफ हों, उनका निरीक्षण

27.03.2018/1635/SLS-HK-2

किया जाए। फिर जो पानी जहां से हम उठा रहे हैं वह सोर्स भी बिल्कुल साफ-सुथरा होना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि हम कहीं गंदा पानी उठाएं और गंदा पानी उठा कर हम और बीमारी फैला दें। इसमें हमें आप सबका सहयोग, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों का सहयोग और पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग चाहिए ताकि हम इस स्थिति से निपट सकें।

आपमें से बहुतों ने कहा है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर एक ऐसी स्थिति है कि हमने बहुत सी स्कीमें आऊटसोर्स की हैं या ठेके पर चलाने के लिए दी हैं। आपने भी उसका संज्ञान लिया है कि उससे हमें नुकसान हो रहा है। यह हमारे ध्यान में भी है कि हमें उससे नुकसान हो रहा है। मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हम एक प्रोपोजल ला रहे हैं कि जितनी-जितनी राशि हम किसी स्कीम पर किसी ठेकेदार को दे रहे हैं और ठेकेदार उस स्कीम के लिए 26 लोगों का एग्रीमैंट करता है लेकिन मौक़े पर 8 आदमी लगाता है और एक करोड़ रुपया एक स्कीम का एक साल के लिए जाता है, हम उसको कैसे रोकें। हमें सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि जो अनस्किल्ड लोग वहां पर रखे जाते हैं उनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हमारी पंपिंग मशीनरी को हो रहा है, मोटरों को हो रहा है और पानी के वितरण में दिक्कत आ रही है। इसलिए इस पर भी हम विचार कर रहे हैं ताकि हम इसका कोई-न-कोई समाधान निकालें।

मित्रों, आप सबने जो बहुमूल्य सुझाव दिए हैं,...(व्यवधान)... जो होम डिविजन है, वह आपके समय में भी होता रहा है, हमारे समय में भी होता रहा है। जहां बहन आशा जी कह

रही हैं कि 2-2 XEN हैं, यह तो आपको अपर्चुनिटी मिली है कि आपके वहां 2 XEN हैं। आप दोनों से काम लो। दोनों को आधा-आधा एरिया बांट दो।

इसके अलावा यहां और भी बहुत से सुझाव आए हैं। जैसे कइयों ने कहा है कि हमारी 4 पंचायतें उस तरफ पड़ती हैं या 4 पंचायतें उस तरफ पड़ती हैं। अनिरूद्ध जी ने भी यह कहा है, हमने कहा है कि आप इन राइटिंग दो, हम निश्चित तौर पर भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक, जो सबको सूट करता होगा, हम उस काम को करेंगे।

मेरा आपसे विनम्र अनुरोध हैं, कि मैंने आपकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है,

27/03/2018/1640/RG/YK/1
सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री------जारी

और लिखी भी है। अब मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब मित्रगण अपने कटौती प्रस्तावों को वापस लेने की कृपा करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्रीमती आशा कुमारी जी कुछ कहना चाहती हैं।

श्रीमती आशा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक छोटा सा स्पष्टीकरण मांगना चाहती हूं। वैसे तो ये शब्दों के जाल बुनने में माहिर हैं, लेकिन मैं इनसे यह जानना चाहती हूं कि इन्होंने कहा कि नाबार्ड के पास 800 डी.पी.आर्ज. गई हुई हैं और we should cooperate with you कि कौन सी प्रॉयोरिटी पर देनी हैं। ये पहले तो यह बताएं कि ये कहां की और कौन सी स्कीमें हैं? ये कब से गई हुई हैं, कब से वहां लम्बित हैं और किस क्षेत्र की हैं। ये 800 का फिगर, it could be all कि जब आप मंत्री थे, तो सारी-की-सारी आप ही ने भेजी थीं ।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष जी, <u>निश्चित तौर पर जो आई.पी.एच. की स्कीमें गई हुई हैं, हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि आप उनकी एक डिटेल मंगवाएं। हम सभी विधायकों को उस डिटेल को वे जिस-जिस चुनाव क्षेत्र की हैं, सर्कुलेट करेंगे। उसमें आप लोगों ने तय करना है कि आप किसको प्राथमिकता देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते।</u>

अध्यक्ष : श्री मुकेश अग्निहोत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तृत उत्तर दिया है और कोशिश की कि किसी भी ढंग से हमें सन्तुष्ट किया जाए। अब इसका पता तो 5वें साल में लगेगा क्योंकि जो इन्होंने महल खड़ा कर दिया है चाहे वह रेन वाटर हारवेस्टिंग का 4750/- करोड़ रुपये का है, चाहे ब्रिक्स का 3257/-करोड़ रुपये का है और 800/-करोड़ रुपये का एक और महल खड़ा कर लिया। तो ऐसे 5-7 महलों का पता तो आने वाले समय में लगेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोशिश की है कि हम लोगों को सन्तुष्ट किया जाए। तो हम इनकी बात को मानते हुए अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं। आज इनकी बात को मान लेते हैं क्योंकि इन्होंने बड़े-बड़े प्रोजैक्ट्स गिनाए हैं और उनकी बात इन्होंने कही है। लेकिन हमारा इनसे आग्रह है कि होम डिवीजन और सर्कल से ऑफिसर्ज को हटा दें।
27/03/2018/1640/RG/YK/2

अध्यक्ष : माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहेंगे?

माननीय सदस्यगण : जी हां।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदन की अनुमति है कि श्री मुकेश अग्निहोत्री, श्री अनिरूद्ध सिंह, श्रीमती आशा कुमारी, श्री हर्षवर्धन चौहान, श्री जगत सिंह नेगी, श्री राम लाल ठाकुर, श्री राजेन्द्र राणा, श्री नन्द लाल, डॉ0(कर्नल) धनी राम शांडिल, श्री राकेश सिंघा, श्री पवन कुमार काजल, श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री आशीष बुटेल और श्री सतपाल सिंह रायज़ादा के कटौती प्रस्ताव वापस ले लिए जाएं?

जो इसके पक्ष में हैं, हां कहें, जो इसके विरुद्ध हैं, न कहें,
हां की, हां की, हां में रही,

प्रस्ताव स्वीकार

(कटौती प्रस्ताव वापस हुए)

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-13, सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित्त दर्शाई गई धनराशियां क्रमशः 25,30,55,93,000/-रुपये और 5,59,74,27,000/-रुपये संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं?

प्रस्ताव स्वीकार
(मांग पूर्णरूप से पारित हुई)

अगली मांग संख्या-10, लोक निर्माण, सड़क, पुल एवं भवन है और कल इस मांग को लिया जाएगा।

27/03/2018/1640/RG/YK/3

अब इस माननीय सदन की बैठक कल बुधवार, दिनांक 28 मार्च, 2018 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक : 27 मार्च, 2018 **सचिव**